R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2024-26

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 22 I अंक : 19
01 से 15 जुलाई 2024
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

नीट और नर्सिंग फर्जीवाड़ा

युवाओं के भविष्य से खिलवाड़

जिम्मेदार कौन...?

नीट फर्जीवाड़े की जांच कर रही सीबीआई नर्सिंग फर्जीवाड़े में फंसी

मप्र के व्यापमं फर्जीवाड़े से भी बड़ा फर्जीवाड़ा है नीट पेपर लीक

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

Address : M-179, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

राजपाट

9 | जांच की आंच...

मप्र में कई आईएएस और आईपीएस अफसर रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन उनके खिलाफ जांच चल रही है। इस जांच की फांस में फंसे होने के कारण कईयों की पेंशन में कटौती भी की जा रही है। प्रमोटी आईपीएस सीएस...

राजपथ

10–11 | गारंटी पूरी करने का...

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भले ही 6 महीने का कार्यकाल पूरा कर चुके हों लेकिन उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। इनमें से कई चुनौतियां तो उन्हें विरासत में मिली हैं, लेकिन प्रदेश का मुखिया होने के नाते इसकी...

लापरवाही

13 | बिना रजिस्ट्रेशन घरों में पल...

भोपाल सहित प्रदेशभर में कुत्तों के आतंक बढ़ने के बाद सरकार ने निर्देश दिए थे कि पालतू कुत्ते, बिल्ली आदि का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। लेकिन राजधानी भोपाल में ही सरकार के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया...

चौसर

18 | उपचुनाव में असली परीक्षा

2023 के विधानसभा चुनाव और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मप्र की सियासत में एक बार फिर चुनावी चौसर सज गई है। प्रदेश में कुछ सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। पहला उपचुनाव पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट पर हो रहा है। जिसमें...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

मप्र में हुए व्यापमं फर्जीवाड़े के बाद देश में नीट-यूजी और मप्र में नर्सिंग फर्जीवाड़ा सामने आया है। देशभर में जहां नीट फर्जीवाड़े को लेकर हंगामा मचा हुआ है, वहीं मप्र में नर्सिंग फर्जीवाड़े से एक बार फिर लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। हालांकि नीट फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद देशभर में ताबड़तोड़ कार्यवाही हो रही है। वहीं सबसे चिंताजनक बात तो यह है कि जो सीबीआई नीट फर्जीवाड़े की जांच कर रही है, वही एजेंसी मप्र में नर्सिंग फर्जीवाड़े में फंसी हुई है।

राजनीति

30–31 | दाग अच्छे हैं!

राजनीतिक दलों का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ सत्ता प्राप्त करना रह गया है। इसके लिए बेशक संगीन अपराधों के आरोपियों को ही टिकट देकर क्यों न जिताना पड़े। अपराध के आरोपियों को टिकट देने के लिए राजनीतिक दल जितने जिम्मेदार हैं, उतने ही उन लोकसभा क्षेत्रों के मतदाता...

महाराष्ट्र

35 | गठबंधनों में बढ़ती दरार

लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। दावा किया जा रहा है कि राज्य में एक बार फिर से सियासी उठापठक हो सकती है। इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव की सभी दलों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन सताधारी महायुति...

बिहार

38 | आरक्षण की राजनीति

आरक्षण की राजनीति भाजपा के लिए नासूर बनने वाली है। भाजपा की आमतौर पर छवि सवर्णों की पार्टी के रूप में रही है। बड़ी मुश्किल से पार्टी ने अपनी छवि पिछड़ों की पार्टी के रूप में बनाई थी, पर राजनीतिक माहौल कुछ ऐसा बन रहा है कि पार्टी...

6 -7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

केवल राजनीतिक पशु बनकर रह गई गौमाता...

किसी शायर ने लिखा है...

इंसान से इंसान नफरत करता है और
गाय को काटकर अपनी जीत समझता है...

उपरोक्त पंक्तियां वर्तमान समय में कई बार चरितार्थ हो चुकी हैं। अभी हाल ही में देश के हृदय प्रदेश मप्र के सिवनी जिले में आधा सैकड़ा से अधिक गायों का गला काटकर मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। इसके बाद शासन-प्रशासन हरकत में आया है और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिर ऐसी नौबत आती ही क्यों है? जबकि देश और प्रदेश में गौमाता के संरक्षण के लिए संकल्पित पार्टी की सरकार है। दरअसल, भारत में गाय राष्ट्रीय पशु बने न बने एक राजनीतिक पशु जरूर बन गई है। बहस के एक तरफ वैसे लोग हैं जो गाय को गौमाता का दर्जा देते हैं, उसकी पूजन करते हैं और उसका संरक्षण करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वैसे लोग हैं जो गाय को भक्षण के लिए उपयुक्त समझते हैं। इलाहाबाद हाइकोर्ट के एक जज की टिप्पणी यहां गौरतलब है, जिन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि वह गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे। जाहिर है इस बहस में वैसे लोग भी कूद पड़े, जिनका अपना राजनीतिक स्वार्थ है। उनको लगता है कि एक हाईकोर्ट के जज द्वारा इस तरह की टिप्पणी कहां तक जायज है? पिछले कुछ वर्षों में गौकशी को लेकर बहुत से राज्यों ने अपने-अपने नियम बनाए हैं, हालांकि इसके बावजूद भी गौहत्या और नतीजतन ह्यूमन लिंचिंग की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। ऐसे में किसी हाईकोर्ट के जज का बहस के बीच में कूद पड़ने से विवाद पैदा होना तो जायज ही है। हमारे पुराणों में ऐसे कई वृतांत आते हैं जहां पर सतयुग और त्रेता युग के राजाओं ने गौमाता की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को भी समर्पित करने का वचन कर दिया। गौमाता की मनुष्यों के द्वारा हत्या होना प्राचीन भारत के इतिहास में एकदम असंभव था। एक बार भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप ने देखा कि एक शेर गाय का पीछा करता हुआ आ रहा है और उसे मारना चाहता है। राजा दिलीप ने उस शेर को कहा कि यदि तुम्हें गौमाता को खाकर अपनी भूख मिटानी है तो गौमाता के स्थान पर मुझे खा लो। जब उन्होंने अपने शरीर और प्राण को ही शेर के सामने समर्पित कर दिया तो भगवान अपनी मूल अवस्था में प्रकट होकर राजा दिलीप से बोले कि यह तुम्हारी परीक्षा थी राजन जिसमें तुम सफल हुए। जो गौमाता को बचाने में सक्षम होता है वही राजा कहलाने और बनने योग्य है। पिछले 100-200 वर्षों की यदि बात की जाए तो भारत में इस दृष्टिकोण से राजा कहलाने योग्य शासक हुआ ही नहीं। महात्मा गांधी ने कुछ विशेष वर्गों के प्रति अपना डर या सहानुभूति के कारण भारत के टूटने के निर्णय को स्वीकार किया और उसके बाद भी खंडित भारत में गौमाता की हत्या को संवैधानिक दृष्टि से निषेध करवाने में असफल रहे। गांधी और नेहरू ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय आगे आने वाले भारत के शासकों पर छोड़ दिया और उन्होंने इस विषय को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डालकर अपना पल्ला झाड़ लिया। ऐसे में गौमाता का संरक्षण कैसे होगा? जब भी चुनाव आते हैं, राजनीतिक पार्टियां गौसंरक्षण का राग अलापने लगती हैं। चुनाव खत्म होते ही गाय अपनी किस्मत के भरोसे रह जाती हैं। दरअसल, भारत में गौमाता केवल राजनीतिक पशु बनकर रह गई है, जिसे राजनेता अपने-अपने तरीके से भुनाने की कोशिश करते रहते हैं।

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 22, अंक 19, पृष्ठ-48, 1 से 15 जुलाई, 2024

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स, एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर भोपाल- 462011 (म.प्र.), फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:-** संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, **जयपुर:-** आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :-** मधु आलोक निगम।

प्रमुख संवाददाता
भावना सक्सेना-भोपाल, जय मदानी-भोपाल, देवीराम-इंदौर, हर्ष सक्सेना-भोपाल, दक्ष दवे-इंदौर, संदीप वर्मा-इंदौर, विपिन कंधारी-इंदौर, गौरव तिवारी-विदिशा, ज्योत्सना यादव-गंजबासौदा, राजेश तिवारी-उज्जैन, टोनी छाबड़ा-धार, आशीष नेमा-नरसिंहगढ़, अनिल सोडानी-नई दिल्ली, हसमुख जैन-मुंबई, इंद्र कुमार बिन्नानी-पुणे।

प्रदेश संवाददाता
पारस सरावगी (इंदौर) 09329586555
नवीन रघुवंशी (इंदौर) 09827227000 (इंदौर)
धर्मेन्द्र कथूरिया (जबलपुर) 098276 18400
श्यामसिंह सिकरवार (उज्जैन) 094259 85070
सुधाष सोमानी (रतलाम) 089823 27267
मोहित बंसल (विदिशा) 075666 71111

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी, फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, , फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर, मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

अपराध पर अंकुश

मप्र में आपराधिक घटनाएं दिन पर दिन बढ़ रही हैं। अपराध की रोकथाम और नियंत्रण के लिए शहरी और ग्रामीण भीड़भाड़ वाली जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए गृह विभाग कानून बनाने पर काम कर रहा है। सरकार का यह कदम सराहनीय है।

● **जितेंद्र जाटव,** भोपाल (म.प्र.)

निगम–मंडल संकट में

प्रदेश में अधिकांश नगर निगम सरकार के लिए सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। अब घाटे में चल रहे प्रदेश के निगम–मंडलों को सरकार बंद करने की तैयारी में है। जो कि एक अच्छा कदम है। जल्द ही निगम–मंडलों को सूचीबद्ध कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

● **बैना गुप्ता,** इंदौर (म.प्र.)

भाजपा का प्रदर्शन

मप्र की 29 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने वाले मप्र भाजपा के नेताओं का दूसरे राज्यों में दम दिखा। भाजपा ने उप्र, बिहार, झारखंड, हरियाणा और तेलंगाना में डॉ. मोहन यादव का पूरा अभियान यादव बहुल इलाकों में ही बनाया था। जहां भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया।

● **योगेश यादव,** ब्यावरा (म.प्र.)

मप्र होगा देश में नंबर–1

मप्र में भाजपा की सरकार आए दिन विकास को नई गति देने के कार्य में जुटी हुई है। सरकार ने कृषि विकास दर 25 प्रतिशत तक पहुंचा दिया है। अब दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अमूल के साथ मिलकर काम करने की योजना है। औद्योगिक विकास हो सके और हर युवा को रोजगार मिल सके इसके तहत प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए चार नए आइटी पार्क शुरू किए जा रहे हैं। उज्जैन, रीवा में आइटी पार्क बनाया जाएगा। भोपाल में दूसरा आईटी पार्क बनाया जाएगा। अब यह स्मार्ट सिटी परिसर में बनाया जाएगा। इंदौर में चौथे आइटी पार्क का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री मप्र को देश का नंबर–1 राज्य बनाने के वादे पर काम कर रहे हैं।

● **मोना सोलंकी,** ग्वालियर (म.प्र.)

संघ की नाराजगी का खामियाजा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को दूर रखते हुए हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाया है। उन्होंने किसी को भी अपना कमांडर नहीं बनने दिया, यहां तक कि आरएसएस को भी नहीं। रिश्ते के बीच तनाव इतना स्पष्ट था कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। प्रधानमंत्री रहते हुए अपने दस साल के शासन के दौरान, मोदी द्वारा आरएसएस से सलाह लेने के शायद ही कोई उदाहरण हों। संघ इससे काफी नाराज दिखाई पड़ रहा है। इस नाराजगी का खामियाजा लोकसभा के चुनाव में भाजपा को देखना पड़ा।

● **नीलेंद्र श्रीवास्तव,** जबलपुर (म.प्र.)

भ्रष्टों पर कार्यवाही हो...

मप्र में हर साल गेहूं खरीदी में भ्रष्टाचार सामने आता है। इस बार जब सतना में घोटाला सामने आया तो लगा था कि पूरे प्रदेश में जांच अभियान चलेगा। लेकिन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग व नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों ने अपनी सुस्त कार्यप्रणाली का एक और उदाहरण दिया है। सरकार को ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, जिससे किसानों में एक अच्छा संदेश जाए।

● **जीवन नागर,** सीहोर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन–1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ–02, 03, एमपी नगर, भोपाल

दांव-पेच

क्यों मुरझाने लगा कमल?

आम चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा ने खुद के लिए 370 और एनडीए 400 पार का टारगेट सेट किया था लेकिन भाजपा अपने दम पर बहुमत के करीब नहीं पहुंच सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी में जीत का अंतर भी मात्र 1 लाख 52 हजार 513 रहा। यही नहीं भाजपा को उन राज्यों में ज्यादा नुकसान हुआ जहां उसे बड़ी जीत की उम्मीद थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव से पहले पूरे आत्मविश्वास के साथ दिख रही भाजपा का कमल क्यों मुरझाने लगा? राजनीतिक पंडितों का कहना है कि भाजपा ने केंद्र सरकार की स्कीम के लाभार्थियों पर फोकस किया था। फ्री राशन स्कीम का भाजपा को फायदा भी मिला लेकिन महंगाई की मार ने इस फायदे को कम करने का काम किया। महंगाई से लोग परेशान थे और लगातार इसकी चर्चा भी कर रहे थे लेकिन चुनाव में भाजपा इस मुद्दे से कन्नी काटती रही, जिससे लोगों में निराशा पैदा हुई। मंहगाई को लेकर भाजपा कार्यकर्ता ही शिकायत करते रहे लेकिन इसकी अनदेखी हुई। पूरे चुनावभर लगभग हर राज्य में युवा बेरोजगारी की बात करते रहे और सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर बेरोजगारी को गिनाते रहे। बेरोजगारी तो पहले से थी लेकिन कोरोनाकाल के बाद स्थिति और खराब हुई। जो प्राइवेट रोजगार पहले था वह कोरोना में चला गया।

संदीप सहारे 'आप'

आम चुनाव 2024 के नतीजे जारी होने से कथित शराब घोटाले में जेल गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर जेल चले गए हैं। असल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 21 दिन के लिए केजरीवाल जेल से बाहर आए थे और चुनाव प्रचार करने के बाद उनको फिर सरेंडर करना पड़ा। इस बार जेल जाने से पहले उन्होंने अपनी पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ एक बैठक की। पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति के सभी सदस्य इस बैठक में शामिल हुए। फिर उन्होंने विधायकों के साथ भी बैठक की। बताया जा रहा है कि दोनों बैठकों में पार्टी के संचालन और अगले साल जनवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल के जेल में रहने पर पार्टी के कामकाज कौन संभालेगा। क्या उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल पार्टी का कामकाज देखेंगी? राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि केजरीवाल ने अपनी गैरमौजूदगी में पार्टी का कामकाज देखने के लिए पार्टी के चुनावी रणनीतिकार संदीप पाठक को अधिकृत किया है। पार्टी में इससे कई लोग नाराज बताए जा रहे हैं। जानकार सूत्रों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों पार्टी में तीन 'एस' की चर्चा थी। संदीप पाठक, सुनीता केजरीवाल और संजय सिंह। माना जा रहा था कि केजरीवाल संजय सिंह को पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर जेल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

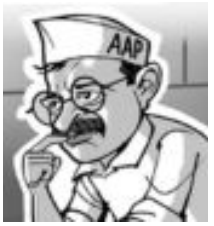

मोदी 3.0- बासी कढ़ी!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी शपथ को करीब महीनेभर हो गए हैं। कैबिनेट, संसद की बैठक, स्पीकर चुनाव और राष्ट्रपति का अभिभाषण सब हो गया है। तो सोचें, क्या आपको कोई एक भी क्षण, एक भी घटना, एक भी चेहरा, एक भी जुमला और एक भी ऐसा परिवर्तन दिखलाई दिया जिससे लगा मानों ताजा हवा का झोंका हो। क्या कैबिनेट में कुछ नया, ताजा दिखा? क्या प्रधानमंत्री दफ्तर, सरकार की आला नौकरशाही में कोई परिवर्तन झलका? ऐसी कोई नई प्राथमिकता, नया मुद्दा, नया विषय प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के मुंह से निकला जिससे लगे कि जिन बातों (रोजगार, महंगाई, बेहाल जिंदगी, नौजवान आबादी, किसान, मजदूर, मध्यवर्ग आदि) पर मतदाताओं ने मोदी के चार सौ पार के नारे को नकारा, तो उससे सबक सीखकर जिंदगी के रियल मसलों पर मोदी 3.0 में नया कुछ बनने की संभावना है? इस बात को इस तरह भी रख सकते है कि मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी को बदलने का मैसेज दिया, विपक्ष में दम भरा तो शासन और राजनीति में आम राय से, सबसे सलाह करके, सबसे पूछकर निर्णय का नया सिलसिला बनना चाहिए था या नहीं? उस नाते क्या नरेंद्र मोदी को अपने को रिइंवेंट नहीं करना था?

हे राम! यह बुलेट ट्रेन!

10 साल पहले भी बुलेट ट्रेन थी, पांच साल पहले भी थी और अगले पांच साल भी रहेगी। कह सकते हैं जिस दिन नरेंद्र मोदी बुलेट ट्रेन को हरी झंडी बताएंगे उस दिन वे यह भी घोषणा कर देंगे कि भारत विकसित देश हो गया है। नई संसद के आगे राष्ट्रपति द्रौपद्री मुर्मू ने भारत के भविष्य का जो कथित महत्वाकांक्षी और साहसी संकल्प बताया है तो इसके प्रतिमान में बुलेट ट्रेन का नेटवर्क बनाने और भारत-मध्य पूर्व यूरोप के आर्थिक कॉरिडोर के इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र भी है। बाकी मुख्य बिंदुओं में नागरिकता संसोधन बिल, जम्मू-कश्मीर, बजट, विश्व रंगमंच में भारत की भूमिका, 70 साल से अधिक उम्र के लोगों का मुफ्त इलाज, आपातकाल को याद करने, सकारात्मक राजनीति, पेपर लीक पर राष्ट्रपति द्वारा बोला गया। यों हम 140 करोड़ लोगों के लिए भाषण और जुमले टाइमपास की एक अनिवार्य जरूरत है। पेपर लीक रियल इश्यू है लेकिन बुलेट ट्रेन क्या सचमुच प्राथमिकता वाला मसला है।

सच्चे संघवाद की समझ

नासमझी ऐसी कि दुनिया के सामने वसुधैव कुटुंबकम या सर्वे भवन्तु सुखिन: की डींगे हांकने वाले विभिन्न राज्यों, बल्कि एक राज्य, समुदाय और दल में भी ईर्ष्या-द्वेष, अविश्वास को हवा देते हैं। मानो, अपने समुदाय या दल के भी सबको अपना नहीं मानते। तब संघ-राज्य संबंध पर हल्केपन का क्या कहना! कैसी विडम्बना की अंग्रेजों ने भारतीय समाज को अधिक समझा था! उन्होंने यहां विशिष्ट क्षेत्रों, शासकों, समूहों को बिलकुल स्वायत्त रहने दिया था। जबकि वे असंख्य रियासतें मजे से खत्म कर सकते थे। कल्पना कीजिए कि फिल्म निर्माण, और खेलकूद को केंद्रीय विषय बनाकर उसे राजकीय एकाधिकार में ले लिया जाए। तब बाबू लोग फिल्म बनाने की और टूर्नामेंट के हर प्रस्ताव पर निर्णय लेंगे। मंत्री लोग अपने क्षेत्र के विकास, यानी मतदाताओं को लुभाने की दृष्टि से फिल्म पास करेंगे। उसमें आरक्षण प्रावधान करेंगे। फिल्मों की शूटिंग, और क्रिकेट मैच अपने राज्य में कराने का हुक्म देकर उद्घाटन करते हुए भाषण देंगे। यह कोई असंभव कल्पना नहीं।

खटाखट अभियोजन से सरकार परेशान

मप्र की नई सरकार का पूरा जोर सुशासन पर है। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए। इसके लिए सरकार ने भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी की है। इसके तहत जिन अफसरों पर लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं, उनके खिलाफ जांच तेज कर दी गई है। वर्षों से जिन अफसरों के भ्रष्टाचार की फाइल नहीं खुली थी, उन्हें खोल दिया गया है। सरकार की मंशानुसार 1994 बैच के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने यह जिम्मा संभाला है। सूत्रों का कहना है कि साहब ने सरकार के निर्देश पर भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ दर्ज शिकायतों की जांच पड़ताल कर खटाखट अभियोजन की स्वीकृति देनी शुरू कर दी है। इसका असर यह देखने को मिल रहा है कि सरकार के पास अभियोजन की फाइलों का पहाड़ खड़ा होने लगा है। सूत्र दावा कर रहे हैं कि सरकार को भी उम्मीद नहीं थी कि उनके निर्देश का इस तरह पालन होगा। बताया जाता है कि सरकार के पास पहुंची फाइलों को भले ही अभी तक खोला नहीं गया है, लेकिन साहब अपने काम में पूरी तरह लीन हैं। बताया जाता है कि साहब जिस गति से अभियोजन की स्वीकृति दे रहे हैं, उससे प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में अफसर सहमे हुए हैं, क्योंकि जिन अफसरों को लगता था कि अब उनकी फाइलों पर चढ़ी धूल कभी नहीं हटेगी, वे फाइलें भी खोली जा चुकी हैं।

नहीं मिल रहा भाव...

देश और प्रदेश की राजनीति में बड़ा कद रखने वाले एक माननीय इन दिनों पसोपेश में हैं। पूर्व में राजनीति की कई बड़ी कुर्सियों पर आसीन रहे माननीय इस समय प्रदेश सरकार में मंत्री की कुर्सी संभाले हुए हैं। साहब की पीड़ा यह है कि न तो उन्हें सरकार के मुखिया भाव दे रहे हैं और न ही अधिकारी उनकी सुन रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि मालवा-निमाड़ के इन कद्दावर माननीय की अपने क्षेत्र की एक बड़ी मिल की बेशकीमती जमीन पर नजर है। वर्षों से बंद पड़े इस मिल की जमीन को सरकार अपने तरीके से व्यवस्थित करना चाहती है। लेकिन मंत्रीजी को इससे दूर रखा गया है। ऐसे में मंत्रीजी परेशान हैं। सूत्र बताते हैं कि वे मंत्री होने के नाते उस मिल की जमीनों का निरीक्षण करना चाहते हैं। लेकिन न तो सरकार के मुखिया और न ही विभाग के अफसर उनको भाव दे रहे हैं। हद तो यह है कि जिस नगर निगम में कभी उनकी तूती बोलती थी, अब उस नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारी भी उन्हें भाव नहीं दे रहे हैं। यानी साहब की तनिक भी नहीं चल रही है। सूत्रों का कहना है कि साहब को उम्मीद थी कि मंत्रिमंडल में बड़ी कुर्सी मिलने के बाद उनका सरकार में बड़ा हस्तक्षेप रहेगा, लेकिन उनकी मंशा पर पानी फिरता नजर आ रहा है।

चाहे कोई हो मजबूरी, वसूली चाहिए पूरी

उपरोक्त पंक्तियां कोई लोकोक्ति या कहावत नहीं है। यह मालवा-निमाड़ क्षेत्र के एक जिले में पदस्थ पुलिस कप्तान का फरमान है। सूत्रों का कहना है कि साहब जबसे जिले में पुलिस कप्तान बनकर आए हैं, उनकी धौंस से पूरा पुलिस महकमा परेशान है। दरअसल, साहब ने आते ही अपनी कमाई पर सबसे पहले फोकस किया है। उन्होंने पदस्थापना के साथ ही जिले के सारे थानों की कुंडली खंगाली और उसके बाद हर थाने से 25,000/- रुपए महीना का रेट फिक्स कर दिया है। यही नहीं साहब ने थानेदारों से कह दिया है कि तुम कितनी वसूली करते हो, कहां से वसूली करते हो, कितना कमाते हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो हर महीने पूरी वसूली चाहिए। बताया जाता है कि साहब के इस फरमान के बाद थानेदारों का भी पहला फोकस यही रहता है कि जैसे-तैसे हो, सबसे पहले साहब के हिस्से की रकम जुटाई जाए। यहां तक तो सबकुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सूत्रों का दावा है कि इस बीच साहब ने थानेदारों को एक और फरमान थमा दिया कि मैं कुछ नहीं जानता, आचार संहिता के दौरान की भी पूरी रकम मुझे हर हाल में चाहिए। साहब के इस फरमान से थानों में हड़कंप मच गया है। सूत्र बताते हैं कि थानेदार साहब की झोली भरने के लिए अब तरह-तरह के तिकड़म अपना रहे हैं। कुछ ने तो इसको लेकर बगावती तेवर भी दिखाना शुरू कर दिया है और उच्च स्तर पर शिकायत की तैयारी की जा रही है।

मंत्री पुत्र की दखलअंदाजी

बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में एक मंत्री पुत्र की सरकारी कामकाज में दखलअंदाजी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल, मंत्रीजी स्वभाव से सीधे-साधे नेताओं में गिने जाते हैं। लेकिन उनके आसपास हमेशा से ही चालबाज अफसरों का घेरा बना रहता है। सूत्र बताते हैं कि ऐसे ही चालबाज अफसरों ने मंत्रीजी के पुत्र को फांस लिया है और मंत्रीजी के विभाग से संबंधित कारोबार में मंत्री पुत्र को आगे कर चांदी काट रहे हैं। वैसे तो प्रदेश में हर मंत्री के परिजन और उनके पुत्र उनके विभाग के कामकाज में सक्रियता दिखाते हैं। लेकिन यहां बात दखलअंदाजी की हो रही है। मालवा-निमाड़ क्षेत्र से आने वाले मंत्रीजी अभी तक चालबाज अफसरों की कारस्तानी से बदनामी का दाग झेल रहे थे, लेकिन अब उनके सुपुत्र ही इस काम में लग गए हैं। इससे मंत्रीजी की छवि भी खराब हो रही है, क्योंकि विभागीय अधिकारी के साथ मिलकर मंत्रीजी के पुत्र जो काम कर रहे हैं, वह तस्करी की श्रेणी में आता है। ऐसे में मंत्रीपुत्र कभी भी कानून की चपेट में आ सकते हैं।

आखिर ये लेनदेन क्या है?

फिल्म सौदागर का गीत- यू ईलू-ईलू क्या है, आपने सुना ही होगा। कुछ इसी तरह प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में लोग खबरचियों से पूछ रहे हैं कि ये लेनदेन क्या है? जब इसकी पड़ताल की गई तो चौंकाने वाला मामला सामने आया। सूत्रों का कहना है कि महाकौशल क्षेत्र के खनिज संपदा से भरे एक जिले में वन भूमि को राजस्व भूमि बनाने का खेल खेला जा रहा है और इस खेल में करोड़ों रुपए का लेनदेन किया गया है। सूत्र बताते हैं कि उक्त जिले के एक बड़े धनाड्य कारोबारी ने एक मंत्री से सांठगांठ कर वन भूमि को राजस्व भूमि बनाने की योजना बनाई है। मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। ऐसे में कोशिश की जा रही है कि सरकार उक्त वन भूमि को राजस्व भूमि घोषित कर दे, ताकि वहां बहुतायत में आयरन का जो भंडार मिला है, उसका खनन किया जा सके। सूत्र बताते हैं कि मंत्रीजी ने करोड़ों रुपए लेकर अपनी तिजोरी तो भर ली है, वहीं इसकी भनक लगते ही अन्य राजनीतिक और प्रशासनिक लोगों की लालसा भी जाग उठी है।

विस अध्यक्ष अब कठपुतली नहीं!

मप्र में अक्सर आरोप लगते रहते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल के इशारे पर काम करते हैं। कई बार अध्यक्ष की कार्यप्रणाली से ऐसा देखने को भी मिलता है। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा के पहले सत्र से ही यह दर्शा दिया है कि अध्यक्ष अब कठपुतली नहीं है।

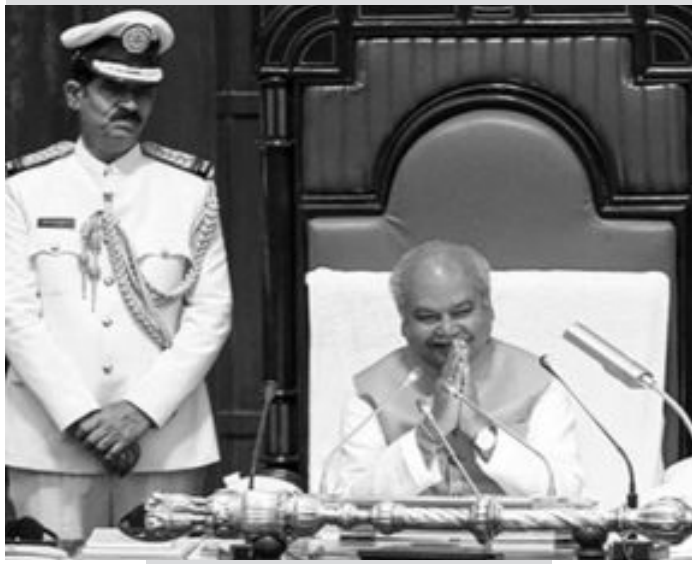

मप्र विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से शुरू होगा। यह सत्र काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बजट पेश होगा, वहीं कई विधेयक भी लाए जाने हैं। 19 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में 14 बैठकें होंगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष विधानसभा के इस सत्र को हंगामेदार बनाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि पिछले विधानसभा सत्रों की तरह यह सत्र भी समय से पूर्व समाप्त न हो जाए। लेकिन 16वीं विधानसभा के पहले सत्र को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने जिस तरह पूरे समय तक चलाया, उससे यह लगता है कि सदन पूरे समय चलेगा, लेकिन जिस तरह की तैयारी कांग्रेस ने की है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बजट पेश होने के बाद विधानसभा की कार्यवाही कभी भी स्थगित हो सकती है।

नरेंद्र सिंह तोमर उन नेताओं में से नहीं हैं, जो किसी के इशारे पर काम करते हैं। उनका अपना व्यक्तित्व है और वे पूरी मर्यादा के साथ काम करने के लिए जाने जाते हैं। 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करने के दौरान भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि उन पर किसी का दबाव नहीं चलेगा। और न ही वे किसी से कोई भेदभाव करेंगे। इसका नजारा पहले सत्र में सभी ने देखा। गौरतलब है कि मप्र विधानसभा अध्यक्ष के लिए जब राज्य और केंद्र सरकार में असरदार किरदार निभा चुके देश के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार नरेंद्र सिंह तोमर का नाम तय किया गया था, तब ही यह तस्वीर साफ थी कि अब विधानसभा में परिणामदायी नवाचार आकार लेंगे। 8 फरवरी 2024 को बजट सत्र में प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न की कंडिका में किया गया बदलाव विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की प्रभावी कार्यशैली का ही परिचायक है। अब विधानसभा सदस्यों को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी लंबित प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। इससे सत्तापक्ष और विपक्ष, जीतने और हारने वाले सभी सदस्यों को यह संतुष्टि रहेगी कि उनके सवालों का जवाब मिलने पर लोकहित की उनकी मंशा पूरी हो सकेगी। विधानसभा की प्रश्न एवं अल्प सूचना प्रश्न में हुआ यह बदलाव लोकहितकारी साबित होगा।

मप्र विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रश्न एवं अल्प सूचना प्रश्न की कंडिका में बदलाव किया है। अब विधानसभा के विघटन के बाद भी लंबित प्रश्नों के जवाब सरकार द्वारा संबंधित सदस्य को प्रदान किए जाएंगे। पहले जहां विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने पर पूर्व के सत्रों के लंबित प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर नहीं दिए जाते थे और इससे लोकहित के कई विषयों पर कार्यवाही नहीं हो पाती थी। किंतु अब नए संशोधन से लंबित प्रश्नों के उत्तर विधानसभा कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी दिया जाएगा और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का यह महत्वपूर्ण निर्णय मील का पत्थर साबित होगा।

विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने 20 दिसंबर 2023 को अध्यक्ष पद पर निर्वाचन के बाद इस संबंध में घोषणा की थी। 8 फरवरी 2024 को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने पर प्रश्न-संदर्भ समिति के समक्ष लंबित प्रकरणों को शून्य अथवा व्यपगत एवं समाप्त नहीं किया जाएगा। अब विधानसभा के विघटन के पूर्व सत्र तक लंबित प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों का परीक्षण किया जाएगा। इस संबंध में परीक्षण कर प्रश्न एवं संदर्भ समिति द्वारा कार्यवाही की जाएगी तथा समिति द्वारा अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। इसके लिए अध्यक्ष के स्थाई आदेश के अध्याय 3 प्रश्न एवं अल्प सूचना प्रश्न की कंडिका 13(क) के पश्चात संशोधन द्वारा अंत: स्थापित नवीन कंडिका 13(ख) को विलोपित कर दिया गया है। यह आदेश पूर्ववर्ती चतुर्दश एवं पंचदश विधानसभा के सभी लंबित प्रश्नों पर लागू किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में पंद्रहवीं विधानसभा में फरवरी 2023 तक ऐसे प्रकरणों की संख्या 805 है। पूर्व नियमों के अनुसार ये स्वत: व्यपगत हो गए थे, किंतु अब नियम में संशोधन होने के पश्चात् व्यपगत नहीं होंगे एवं इस संबंध में परीक्षण करके प्रश्न एवं संदर्भ समिति द्वारा कार्यवाही करके प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लिया गया यह फैसला विधानसभा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इससे अफसरों के सवाल का जवाब टालने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। तो यह बहाना भी नहीं चलेगा कि जानकारी एकत्र की जा रही है। या फिर अफसर विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने पर चिंतामुक्त नहीं हो पाएंगे कि अब सवाल अतीत का हिस्सा बन गए हैं, जिनका जवाब कभी नहीं देना पड़ेगा। इससे विधानसभा सदस्यों की गरिमा बढ़ेगी और वह खुद को ज्यादा सशक्त महसूस करेंगे। और बात केवल इस एक लोकहितकारी फैसले पर खत्म होने वाली नहीं है। अब 1 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र में विपक्ष को भी उम्मीद है कि आसंदी से अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर उनकी बातों को सुनेंगे और उन्हें बोलने का पूरा मौका देंगे।

● **सुनील सिंह**

हर भूमिका में प्रभावी

नरेंद्र सिंह तोमर अब तक जिस भी भूमिका में रहे हैं, उसमें प्रभावी साबित हुए हैं। मप्र में 2008 और 2013 में बतौर संगठन के मुखिया भी नरेंद्र सिंह तोमर की कार्यशैली के सब मुरीद हैं। तो अब विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी तोमर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच अपनी सशक्त कार्यशैली का लोहा मनवा रहे हैं। सक्रिय राजनीति में सबकी बातें सुनकर नपी-तुली प्रतिक्रिया देकर जो सबको खुश रखने की क्षमता रखते हैं। सरकार और संगठन में रहकर उन्होंने यह चरितार्थ किया है। मोदी सरकार के समय हुए किसान आंदोलन को कोई भुला नहीं सकता, तो आंदोलनकारी नेताओं के बीच पहुंचकर उनकी सब बात सुनकर और नपी-तुली प्रतिक्रिया देकर किसान नेताओं का दिल जीतने वाले तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी सबको याद रहेंगे।

जांच की आंच

मप्र में कई आईएएस और आईपीएस अफसर रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन उनके खिलाफ जांच चल रही है। इस जांच की फांस में फंसे होने के कारण कईयों की पेंशन में कटौती भी की जा रही है। प्रमोटी आईपीएस सीएस मालवीय के खिलाफ 10-12 विभागीय जांच चल रही थीं। दूध डेयरी चलाने, महिलाओं से छेड़छाड़ से संबंधित भी मामले थे। इनको सजा भी होनी थी, लेकिन इसी साल अप्रैल में इनका देहांत हो गया। यानी जांच अधर में ही लटककर रह गई।

इनकी 10 फीसदी पेंशन अटकी

प्रदेश के 2 रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी ऐसे हैं, जिनके खिलाफ चल रही जांच के कारण उनकी 10 फीसदी पेंशन रुकी हुई है। इनमें एक हैं, 1985 बैच के महान भारत सागर। 12 हजार की टोपी खरीदी मामले में इनके खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत की गई। जिसकी जांच चल रही है। साहब रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनकी 10 फीसदी पेंशन अटकी हुई है। वहीं 1986 बैच के आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा के खिलाफ भी विभागीय जांच चल रही है। वे भी रिटायर हो गए हैं और उनकी 10 फीसदी पेंशन रुकी हुई है। 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी शिवदयाल के खिलाफ भी शोकाज नोटिस दिया गया है। जब यह देवास में एसपी रहे थे, तभी उन पर गंभीर आरोप लगे थे। अब उन्हें वहां से हटाकर बटालियन में पदस्थ किया गया है।

उपेंद्र जैन बने स्पेशल डीजी

1991 बैच के आईपीएस अधिकारी उपेंद्र कुमार जैन हाल ही में पदोन्नत होकर विशेष पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं। 1990 बैच के आलोक अवस्थी के सेवानिवृत्त होने के बाद 31 जुलाई को 1989 बैच के संजय कुमार झा रिटायर होंगे। उनकी जगह प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव स्पेशल डीजी होंगी। सुषमा सिंह और अनिल गुप्ता ये दोनों अधिकारी 31 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे। इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता नए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हो सकते हैं। उज्जैन पुलिस महानिरीक्षक संतोष सिंह इंदौर पुलिस कमिश्नर की जगह लेने के बाद दीपिका सुरी, प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव के बाद महिला अपराध की कमान संभाल सकती हैं। वहीं प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव पुलिस ट्रेनिंग में जा सकती हैं।

नयों की तेज चाल

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में करीब एक दर्जन से अधिक आईएएस और आईपीएस अफसर सरकार के निशाने पर हैं। कारण उसका सीधा सा है, कि इन्होंने हर एक मामले में अति कर रखी है। मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से आए दिन इनकी लेनदेन-चरित्र को लेकर चर्चाएं तेजी से चल रही हैं। तबादलों की सूची में इन कई अफसरानों का नाम लिया जा रहा है। देखना यह है कि सरकार इनमें से कितनों का तबादला कर पाती है और कितने बचकर निकल जाते हैं। हाल ही में सरकार ने आयुक्त वाणिज्यिक कर को चलता कर दिया है। अभी हाल ही में बमुश्किल उनका तबादला ठीकठाक जगह पर हुआ था। इसी तरह सरकार के निशाने पर कई अफसर हैं।

फिर नए स्वरूप में चालू होगी डायल 100

प्रदेश में नवंबर 2015 में डायल 100 बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए चालू की गई थी। जिसका समय मार्च 2020 तक था। उसके बाद प्रतिमाह 2-2 महीने का एक्सटेंशन देकर इसको बढ़ाया जा रहा है। जबकि इसके हार्डवेयर, स्वीचेस सब खराब हो चुके हैं। अब नई 1670 करोड़ की मंजूरी मिलना है। जिसका प्रजेंटेशन वगैरह हो चुका है। इसमें कुल इस बार 1200 वाहन लगाए जाएंगे। शहरों में इनोवा और ग्रामीणों में बुलेरो की बात चल रही है। इसको 1 सितंबर से चालू करना है। खास बात यह है कि उज्जैन में इसका एक और कॉल सेंटर बनाया जाएगा। जिससे आने वाले समय में सीएस की मॉनीटरिंग भी होती रहेगी। पेंच इसमें इस बात को लेकर अटका हुआ है कि वाहनों को किराए पर लेना है या खरीदना है। और इस बार डायल 100 पर साइबर की कॉल, आग, एंबुलेंस सारी इंटीग्रेटेड एकसाथ होगी। डायल 100, 112, 1930, 1098 ये सारी सेवाएं एक ही कॉल सेंटर पर होंगी।

सीएमओ में बदलाव

अपनी साढ़े चार साल की शेष बची पारी के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री सचिवालय में भी अहम बदलाव किए हैं। जिस तरह सचिवालय के अधिकारियों के बीच कार्य का विभाजन हुआ है, उसको देखकर लगता है कि रैंक के अनुसार बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री सचिवालय में और बदलाव होगा। अगर बदलाव होगा तो किसको हटाया जाएगा? वहीं बताया जा रहा है कि वर्तमान मुख्य सचिव अपना कार्यकाल पूरा करेंगी और जब नया मुख्य सचिव आएगा, तब मुख्यमंत्री सचिवालय में भी बदलाव किया जाएगा। अभी हाल ही में जो ट्रांसफर हुए हैं, वे पूरी तरह संतुलित दिख रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि मुख्यमंत्री परिणाम देने वाले अधिकारियों को अधिक तवज्जो दे रहे हैं।

4 एसपीएस को आईपीएस संवर्ग

राज्य पुलिस सेवा के 4 अधिकारियों को इस बार आईपीएस संवर्ग मिल सकेगा। इसके लिए 12 अधिकारियों के नाम प्रस्तावित किए जाएंगे। पुलिस मुख्यालय ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे गृह विभाग के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। इसी तरह राज्य वन सेवा के लिए एक साथ दो वर्ष के पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कराने की तैयारी है। इससे 24 अधिकारियों को आईएफएस संवर्ग मिलेगा। वहीं प्रदेश के गैर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को 8 वर्ष से आईएएस बनने का मौका नहीं दिया गया है। इस बार भी इन्हें यह अवसर नहीं मिलेगा। प्रदेश में आईएएस संवर्ग में नियुक्ति के लिए उपलब्ध सभी 7 पद राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से अनुमोदन प्राप्त करने फाइल भेजी है। उधर, राज्य पुलिस सेवा के 4 अधिकारियों को आईपीएस संवर्ग में नियुक्ति मिलेगी। इसका प्रस्ताव भी पुलिस मुख्यालय द्वारा तैयार कर लिया गया है। प्रदेश में वर्ष 2016 में अंतिम बार 4 गैर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आईएएस संवर्ग में नियुक्ति का अवसर मिला था।

● **राजेंद्र आगाल**

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भले ही 6 महीने का कार्यकाल पूरा कर चुके हों लेकिन उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। इनमें से कई चुनौतियां तो उन्हें विरासत में मिली हैं, लेकिन प्रदेश का मुखिया होने के नाते इसकी जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री की ही होगी। मुख्यमंत्री ने अब तक यह दिखा दिया है कि वे चुनौतियों से रुकने वाले व्यक्ति नहीं हैं। इसलिए अब वे विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी द्वारा दी गई गारंटियों को पूरा करने के लिए मिशन मोड में आ गए हैं।

गारंटी पूरी करने का मिशन मोड

मप्र की नई सरकार ने 6 माह पूरे कर लिए हैं। इस दौरान सरकार ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसकी वजह से पूरे देश में प्रदेश का डंका बजा है। हालांकि इस दौरान नई सरकार के सामने कई चुनौतियां भी आई हैं, जो सरकार को बेचैन कर रही हैं। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद नई सरकार एक बार फिर से काम में जुट गई है। लोकसभा चुनाव की वजह से 13 दिसंबर को शपथ लेने के बाद डॉ. मोहन यादव को काम करने के लिए सिर्फ 93 दिन ही मिले। 16 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई। 6 जून को आचार संहिता हटने के बाद एक बार फिर सरकार के कामकाज में गति आई है। नई सरकार को 6 महीने हो चुके हैं। इतने समय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐसे कई कार्य किए हैं, जो चर्चा में रहे। खासकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह जताने की कोशिश की है कि यह आम लोगों की सरकार है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के छह महीने के कार्यकाल में कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें अधिकारी आम जनता की तकलीफें सुनने के बदले उनकी उपेक्षा करते दिखे, ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री ने तत्काल इन अधिकारियों पर कार्रवाई की। सबसे ज्यादा चर्चा में रहा शाजापुर में ट्रक ड्राइवर की हड़ताल के दौरान ड्राइवर से कलेक्टर की अभद्रता का मामला। या फिर उमरिया में एसडीएम द्वारा महिला कर्मचारी से जूते के फीते बंधवाने, बांधवगढ़ एसडीएम की कार को ओवरटेक करने पर दो लोगों को पीटने, देवास में महिला तहसीलदार द्वारा किसान पर अभ्रद भाषा का प्रयोग करना। सभी मामलों में मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाई और अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि उनके लिए जनता का सम्मान और सुशासन का संकल्प सर्वोपरि है। प्रदेश के सभी 55 जिलों में साइबर तहसील व्यवस्था लागू कर दी, जिसमें नामांतरण के लिए पटवारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। संपत्ति के पंजीयन के साथ नामांतरण भी हो जाएगा। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए शोर मचाने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्र धार्मिक स्थलों से हटवाए गए। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग को प्रतिबंधित करने के साथ 32 हजार से अधिक लाउडस्पीकरों को हटवाया गया। विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा के संकल्प पत्र में कुल 456 वादे शामिल थे जिनमें से 41 पूरे किए गए हैं। बचे हुए 218 संकल्प पर कार्य तेजी से चल रहा है।

विधानसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश की जनता से जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने के लिए मोहन यादव मिशन मोड में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सभी विभागों और मंत्रियों को संकल्प पत्र-2023 की घोषणाओं और वचनों को पूरा करने और उसे जमीन पर उतारने के लिए मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी वाली गाड़ी प्रदेश के गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंची है और करीब 50 लाख लोगों को विभिन्न योजनाओं का फायदा पहुंचाया है। संकल्प पत्र की घोषणा को पूरा करते हुए मोहन यादव सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों का मानदेय 3 हजार रुपए से बढ़ाकर 4 हजार रुपए प्रति मानक बोरा कर प्रदेश के 35 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी है। डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनते

सरकार ने खोला खजाना

लोकसभा चुनाव में भाजपा के 29 सीटों पर जीतने के बाद सरकार जनता से किए वादे को पूरे करने में जुट गई है। पूर्व की योजनाओं के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। मप्र में नौकरी एक बड़ा मुद्दा है। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही राज्य सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया है। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 46 हजार से अधिक नए पद सृजित किए हैं। इन पदों पर जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही आने वाले दिनों में अन्य क्षेत्रों में भी नई बहालियां आएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि केन-बेतवा परियोजना प्रथम नदी जोड़ो परियोजना है। परियोजना के अमल में वन भूमि के कारण जो समस्या उत्पन्न हुई थी, उसे समाप्त कर दिया गया है। परियोजना से संबंधित टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इसी तरह प्रदेश के पश्चिमी अंचल को लाभांवित करने वाली पार्वती-काली सिंध-चंबल परियोजना का 20 वर्ष से उलझा मसला हल हो गया है। राजस्थान और मप्र को 35-35 हजार करोड़ रुपए की राशि भारत सरकार से प्राप्त होगी। वहीं मप्र के सीहोर में गेल इंडिया एथेन क्रैकर का सबसे बड़ा प्लांट लग रहा है।

ही पुराने मामलों की फाइलों को निपटाने में भी सक्रियता दिखाई। उन्होंने सबसे पहले इंदौर की प्रसिद्ध हुकुमचंद्र मिल के मजदूरों को उनके बकाया राशि देने संबंधी फाइल को आगे बढ़ाया और राशि मिलने की प्रक्रिया को पूरा किया। किसानों की समृद्धि के लिए खेती में सिंचाई का पानी पहुंचे, इसके लिए लंबे समय से लंबित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना के करार पर राजस्थान के साथ एमओयू किया। इसके साथ ही राजधानी भोपाल में यातायात की सुगमता के लिए बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने संबंधी निर्णय लेकर क्रियान्वयन भी प्रारंभ कराया। मोहन यादव सरकार के 6 माह के कार्यकाल में लगभग 3 माह लोकसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावी रही। इस दौरान कोई नया काम नहीं हुआ, लेकिन इसके पहले जो शुरुआत की उनके बारे में सरकार की ओर से दावा किया गया है कि नामांकन, बंटवारा, सीमांकन जैसे राजस्व के लाखों अविवादित लंबित मामलों के निराकरण के लिए अभियान चलाया गया और 30 लाख से अधिक प्रकरणों का निराकरण हो गया। राज्य शासन गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है, डबल इंजन सरकार का यह संकल्प सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। शासन की जन हितैषी योजनाएं-प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबसे पहले देश में जनधन खाते खोले गए। इसका परिणाम यह हुआ कि गरीब कल्याण की योजनाओं की राशि सीधे हितग्राहियों के खातों में पहुंचने लगी। गरीबों को न केवल न्याय मिले बल्कि उन तक न्याय पहुंच सके इसका प्रबंध सरकार ने किया है।

मप्र ने पिछले छह माहों के सुशासन के प्रयासों से यह जाहिर कर दिया है कि गरीबी पर ठोस प्रहार कर गरीब परिवारों को गरीबी के कुचक्र से बाहर लाया जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि उन परिवारों को नागरिक सेवाओं के पहुंच के दायरे में लाया जाए। उनकी आर्थिक

क्षमता बढ़ाई जाए। उनके लिए सूक्ष्म स्तर पर आर्थिक गतिविधियों की श्रृंखला चलाई जाए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए सरकार ने प्रतिबद्धता जाहिर की है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तथा सबका प्रयास का नारा वंचितों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियों की आधारशिला बन गया है। जरूरतमंदों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाने में सहायता दी जा रही है। गरीब हितैषी पहल के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को देशभर में पहचान मिली है। प्रधानमंत्री जन धन योजना अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल जिलों में 7 हजार 300 करोड रुपए से अधिक की लागत से अधोसंरचना के कार्य हो रहे हैं जिससे 11 लाख से अधिक व्यक्ति लाभान्वित होंगे। योजना अंतर्गत मप्र पहला राज्य है जिसने पांच माह में 5000 से अधिक आवास का निर्माण पूर्ण कर लिया है। शिवपुरी जिले में सर्वाधिक लगभग 1103 आवास पूर्ण किए गए हैं। ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें योजना के अंतर्गत हितग्राहियों की अधिक संख्या थी उन ग्रामों में कॉलोनी बनाकर आवास बनाए जा रहे हैं। प्रदेश सर्व स्पर्शी विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। समाज के सभी वर्गों की विकास में समान भागीदारी के लिए गरीब और कमजोर वर्ग के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह जताने की कोशिश की है कि यह आम लोगों की सरकार है। दुर्व्यवहार करने वाले अफसरों पर त्वरित कार्रवाई की गई है। निवेश के मामले में भी सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। गेल इंडिया सीहोर के आष्टा में एथेनॉल क्रैकर प्लांट लगा रही है। डॉ. मोहन यादव ने शपथ ग्रहण करने के बाद पहली बैठक में धार्मिक स्थलों सहित अन्य स्थलों में लाउडस्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। प्रदेश के हजारों मंदिरों-मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं। सरकार ने खुले में मांस की बिक्री पर भी रोक लगाने का कार्य किया है। पहली बैठक में ही मुख्यमंत्री ने साइबर तहसील को पूरे प्रदेश में लागू करने की व्यवस्था शुरू की। इसके तहत किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री होते ही अपने आप नामांतरण की सुविधा को शुरू किया गया। प्रदेश में सुशासन की दिशा में यह बड़ा कदम माना गया। डॉ. मोहन यादव ने केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दिलाई। यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है। इस परियोजना पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा।

● **कुमार विनोद**

भाजपा कार्यालय में बैठेंगे कैबिनेट मंत्री

भाजपा ने सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय के लिए मॉडल तैयार किया है। यह देश के दूसरे राज्यों में लागू हो गया है। अब इसे मप्र में भी लागू किया जाएगा। इसमें भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक मंत्री बैठेंगे। वे प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ताओं की बातों को सुनेंगे और उनको हल करेंगे। इसे सहयोग केंद्र मॉडल नाम दिया गया है। इसमें भाजपा के कैबिनेट मंत्रियों की सप्ताह में पांच दिन ड्यूटी लगाई जाएगी। उनके साथ संगठन का भी एक नेता साथ बैठेगा। ये सप्ताह में पांच दिन तीन घंटे कार्यालय में बैठेंगे। हालांकि अभी कब से शुरुआत होगी, मंत्री किस-किस दिन और कितने समय बैठेंगे यह सब तय होना है। केंद्रीय सह संगठन महासचिव शिवप्रकाश, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बीच चर्चा हो चुकी है। इसे विधानसभा के मानसून सत्र के बाद लागू किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के फीडबैक में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों पर उनकी सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। इसके चलते कई जगह कार्यकर्ता प्रचार की जगह घर बैठ गए। इससे कई बूथों पर पार्टी को नुकसान हुआ। यह जानकारी शीर्ष नेतृत्व तक पहुंची। इसके बाद सत्ता और संगठन के बीच समन्वय बनाने के लिए इस सहयोग केंद्र को जल्द शुरू करने की बात कही गई है। भाजपा अब कमजोर बूथों को जीतने के लिए विकास और टोली बैठक करके अपने आपको मजबूत करेगी। इसके लिए जिलों में विकास कार्यों के साथ ही संगठन के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठकों का आयोजन किया जाएगा।

आबकारी में मची है लूट!

मप्र सरकार के कमाऊ विभागों में से आबकारी विभाग इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी वजह यह है कि प्रदेश में धड़ल्ले से अवैध शराब का कारोबार चल रहा है और उसे रोकने की जिम्मेदारी जिस अधिकारी पर है, वे जमकर चांदी काट रहे हैं। आलम यह है कि प्रदेश का आबकारी विभाग लूट का केंद्र बन गया है। सूत्रों का कहना है कि जबसे 2010 बैच के आईएएस अधिकारी अभिजीत अग्रवाल आबकारी आयुक्त बने हैं, विभाग में लूट मची हुई है। आबकारी आयुक्त की लालफीताशाही से वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव परेशान हैं और मंत्री हैरान हैं।

दरअसल, आबकारी आयुक्त ने विभाग को पूरी तरह हाईजैक कर लिया है। नियमों को ताक पर रखकर वे अपनी मनमानी कर रहे हैं। आयुक्त ने अपनी मनमर्जी से आबकारी अधिकारियों को प्रभार भी देना शुरू कर दिया है। अभी तक 6-7 अधिकारियों को प्रभार सौंप दिया है, जबकि यह काम सरकार का है। लेकिन आबकारी आयुक्त सरकार से भी ऊपर हो गए हैं और नियमों की धज्जियां उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि उन्होंने अधिकारियों से हफ्ता वसूली भी शुरू कर दी है। आलम यह है कि आयुक्त द्वारा पैसा मांगने से अधिकारी भी परेशान हैं। आयुक्त की लालफीताशाही की चर्चा सीएम सचिवालय से लेकर निचले स्तर तक जोरों पर है। अधिकारी कह रहे हैं कि आयुक्त के पास ट्रांसफर का अधिकार नहीं है, फिर भी वे जिलों का प्रभार सौंप रहे हैं। प्रशासनिक वीथिका में चर्चा है कि जब कोई नौकरशाह राज्य सरकार के खजाने की चिंता करने लगे तो समझ लीजिए कि, विभाग में भ्रष्टाचार की नई कहानी लिखी जा रही है। ऐसी ही कहानी इन दिनों आबकारी विभाग में लिखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार आबकारी विभाग में पदस्थ आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने विभाग की कार्यशैली को बदलने के लिए कुछ ऐसे काम शुरू किए हैं, जिसकी चर्चा मंत्रालय की पांचवी मंजिल में सुबह-शाम होने लगी है। अभिजीत अग्रवाल के द्वारा आबकारी राजस्व में अप्रत्याशित वृद्धि का लक्ष्य बनाया गया है और जिलों में पदस्थ अफसरों को टारगेट थमा दिया है। बताया जाता है कि आबकारी आयुक्त ने अफसरों के ऊपर जो टारगेट लादा है, वह सरकार के नहीं बल्कि उनके खजाने के लिए है।

सूत्र तो यह भी बताते हैं कि जबसे अभिजीत अग्रवाल आबकारी आयुक्त बने हैं, प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार चरम पर पहुंच गया है। इसको लेकर शराब के ठेकेदार कई बार आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। लेकिन उनकी आपत्ति पर कोई सुनवाई नहीं होती है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि ग्वालियर स्थित आबकारी मुख्यालय में पहुंचने वाली शिकायतों पर भी आयुक्त गौर नहीं कर रहे हैं। दरअसल, आबकारी आयुक्त महीनों में एक-दो बार के लिए ही मुख्यालय आते हैं, जबकि अधिकांश समय भोपाल में ही बैठकर काम करते है। आबकारी विभाग से संबंधित फाइलों को भोपाल ले जाने के लिए कुछ कर्मचारियों की रोटेशन के हिसाब से ड्यूटी लगा दी गई है जो फाइलें ले जाने का काम करते हैं। बताया गया है कि जब आबकारी विभाग के ठेके हो रहे थे उस समय भी मुखिया मुख्यालय छोड़ भोपाल में डटे हुए थे और ऐसे में कई ठेकेदार ऐसे थे जिनको परेशानी हुई तो उनकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं था।

आबकारी आयुक्त की कार्यप्रणाली का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बाल मजदूरी के आरोप में घिरे सोम डिस्टलरीज की शराब फैक्ट्री पर कार्रवाई कर वाहवाही लूटने की जो कोशिश की है, उसने कई बड़े सवालों को जन्म दे दिया है। शराब माफिया सोम डिस्टलरीज के लाइसेंस को महज 20 दिनों के लिए निलंबित करना ये बताता है कि ये कड़ी कार्रवाई के नाम पर ये सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति है। बड़ा सवाल ये है कि जब सोम डिस्टलरीज की शराब फैक्ट्री में बाल मजदूरी के सारे सबूत मिल चुके हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग से लेकर प्रदेश सरकार और आबकारी विभाग ने आरोप को सही पाया है। खुद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी माना कि सोम कंपनी ने बाल मजदूरी का गंभीर अपराध किया है। लेकिन उसके बाद कड़ी सजा के नाम पर महज 20 दिनों के लिए कंपनी का लाइसेंस निलंबित करना, क्या यही कड़ी सजा होती है? क्या उन 58 मासूमों की जिंदगी की कीमत सरकार की नजरों में सिर्फ 20 दिन ही है। या इस निर्णय के पीछे भी सोम को बचाने की कोई साजिश है?

आबकारी विभाग के विशेषज्ञों का मानना है कि सोम डिस्टलरीज के लाइसेंस के निलंबन का जो आदेश आबकारी विभाग ने जारी किया है, उसे देखकर साफ पता चलता है कि कार्रवाई की आड़ में आबकारी विभाग के अधिकारियों ने सोम डिस्टलरीज को हाईकोर्ट से राहत पाने का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है। जानकारों के मुताबिक आदेश में ऐसे कई पेंच जानबूझकर फंसाए गए हैं जिससे हाईकोर्ट में सोम डिस्टलरीज को राहत तो मिल ही जाए, साथ ही भविष्य में भी सरकार शराब माफिया पर कठोर कार्रवाई करने की हालत में ना बचे। कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में आबकारी विभाग सोम का बचाव कर रहे हैं। सोम की शराब फैक्ट्री के खिलाफ लायसेंस निलंबन और फैक्ट्री सीज करने की जो कार्रवाई छापे के 4 दिन बाद मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद की गई है, अगर आबकारी आयुक्त ईमानदारी से चाहते तो ये कार्रवाई सोम के रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद तुरंत ही कर सकते थे। लेकिन कार्रवाई करने के बजाय जिला प्रशासन के साथ मिलकर आबकारी आयुक्त समेत विभाग के अधिकारियों ने सोम को बचने का पर्याप्त समय दिया। इंदौर में रहे एक अधिकारी जिन्होंने फर्जी एफडी से करोड़ों का घोटाला किया था, उस मामले में ईडी ने भी जानकारी मांगी है।

● **लोकेश शर्मा**

बापड़ा सीधा-साधा है...

आबकारी विभाग के अधिकारी की मनमानी की सबसे बड़ी वजह यह है कि वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा सीधे-साधे व्यक्ति हैं। यही वजह है कि मंत्री को पता नहीं है और उनके घर पर प्रभार का धंधा चल रहा है।एक आबकारी अफसर बंगले पर बैठकर वहां से धंधा कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि मप्र में आबकारी के दो पीठ चल रहे हैं, एक ग्वालियर से और दूसरा भोपाल से।एक साहब ने तो जिले के आबकारी अधिकारियों को टारगेट दे रखा है। इस मामले की जब प्रमुख सचिव को जानकारी मिली तो उन्होंने मुख्यमंत्री को बताना उचित समझा। सूत्रों का कहना है कि सचिवालय से प्रमुख सचिव के पास फोन आया कि जो भी चल रहा है चलने दो। इस पर प्रमुख सचिव ने दूसरी बार कहा तो उन्होंने कहा कि आप रोक सको तो रोक लो। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आबकारी विभाग में किस तरह की भर्राशाही चल रही है।

बिना रजिस्ट्रेशन घरों में पल रहे कुत्ते

भोपाल सहित प्रदेशभर में कुत्तों के आतंक बढ़ने के बाद सरकार ने निर्देश दिए थे कि पालतू कुत्ते, बिल्ली आदि का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। लेकिन राजधानी भोपाल में ही सरकार के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2019 की जनगणना के अनुसार राजधानी में करीब 10,000 पालतू कुत्ते हैं। हालांकि नगर निगम में महज 1350 कुत्तों का ही रजिस्ट्रेशन है। इसके अलावा करीब 2 लाख आवारा कुत्ते हैं। इनकी नसबंदी पर हर साल लाखों के खर्च के बाद भी इनकी आबादी नियंत्रित नहीं हो पा रही है।

नगर निगम के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राजधानी की हर कॉलोनी और कई मंत्रियों, अफसरों के घरों में कुत्ते पले हुए हैं। अधिकांश विदेशी नस्ल के हैं। ऐसे डॉग्स की जानकारी इकट्ठा करने और इनसे लोगों को होने वाली दिक्कतों पर नियंत्रण के लिए सरकार ने अनिवार्य तौर से रजिस्ट्रेशन कराने के नियम भी बनाए हैं। इसके बाद भी शहर में 1350 से कुछ अधिक डॉग्स को पालने का लायसेंस ही इनके मालिकों के पास है। यह स्थिति तब है जब डॉग्स मालिकों पर पेनाल्टी लगाने का नियम है और पेट डॉग्स के हमलों के मामले सामने आ चुके हैं। नियम है कि पशु चिकित्सक की ओर से जारी सर्टिफिकेट भी देना होगा कि उसे कोई संक्रमण नहीं है और वह परिसर में रखे जाने लायक है। रजिस्ट्रेशन के बाद निगम आयुक्त या मुख्य नगरपालिका अधिकारी पशु चिकित्सक की देख रेख में पशु को माइक्रो चिप अथवा टैग या अन्य साधनों से ब्रांडिंग कोड लगवाएगा, इसे पशु स्वामी की विस्तृत जानकारी होगी। कोड को निकाय के रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। कोडिंग का खर्च भी पशु स्वामी से लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन एक साल के लिए रहेगा, इसे हर वर्ष समाप्ति के 30 दिन के भीतर रिन्यू कराना होगा, ऐसा न कर पाने पर देरी के लिए प्रत्येक दिन रजिस्ट्रेशन फीस की दस फीसदी की दर से पेनाल्टी लगाई जाएगी। कोड के साथ या बिना खुले में घूमते मिले पशु को निकाय के अधिकारी जब्त करेंगे, कांजी हाउस में रखेंगे, जब्त करने के एक हफ्ते के भीतर मालिक को दावा करना होगा, ऐसा न होने पर उसका उपयुक्त रीति से निपटान किया जाएगा। कोई ब्रांडेड पशु दो बार से ज्यादा आवारा भटकते पाया जाता है को उसके मालिक को सात दिन में जवाब देने का नोटिस दिया जाएगा, इससे संतुष्ट न होने पर लायसेंस रद्द करने के साथ ही 100 से 500 रुपए की पेनाल्टी वसूली जाएगी।

भोपाल नगर निगम पालतू कुत्तों का लायसेंस बीते 15 साल से बना रहा है। अब तक 1350 से अधिक लायसेंस जारी किए जा चुके हैं। यह पेट डॉग्स की वास्तविक संख्या के मुकाबले काफी कम है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने मप्र नगरपालिका (रजिस्ट्रीकरण तथा आवारा पशुओं का नियंत्रण) नियम 2023, फरवरी 23 में अधिसूचित किए थे। इसमें स्पष्ट तौर से कहा गया है कि नगरीय निकाय की सीमा में रखे या लाए गए प्रत्येक पशु के स्वामी इन नियमों के नोटिफाईड होने के तीन महीने के भीतर या शहर में लाने के सात दिन के अंदर, पशु के रजिस्ट्रीकरण के लिए संबंधित अधिकारी को आवेदन करेगा। ऐसा न करने पर पशु मालिक पर रजिस्ट्रेशन फीस की दस गुना पेनाल्टी लगाई जाएगी। नियमों के मुताबिक पशु के खतरनाक या आक्रामक होने की शिकायत मिलने पर उसके मालिक को नोटिस देकर सात दिन में जवाब मांगा जाएगा। इससे संतुष्ट न होने पर नया नोटिस जारी करते हुए तीन दिन में पशु को उचित नियंत्रण में रखने का निर्देश देंगे। इस पर अमल नहीं करने की स्थिति में पशु को नीलाम कर दिया जाएगा।

मप्र में शहरी सीमा में पालतू जानवरों के पालने पर सात दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। मप्र नगर पालिका (आवारा जानवरों का पंजीकरण और उचित नियंत्रण) नियम 2023 मार्च से लागू है। लेकिन निगम में इस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। नए नियम के तहत शहरी क्षेत्र में कुत्ते, बिल्ली, गाय, बैल, भैंस के साथ-साथ अन्य पशु पालने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए सालाना शुल्क भी अदा करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद हर पशु के लिए पहचान चिन्ह जारी करने का भी नियम है। इसके बाद पालतू पशु आवारा घूमता पाया गया तो नोटिस के साथ जुर्माना भरना होता है। पंजीयन नगर निगम में होता है। रजिस्ट्रेशन न होने पर प्रतिदिन रजिस्ट्रेशन शुल्क के 10 प्रतिशत की दर से हर्जाने का नियम है।

● **अरविंद नारद**

150 रुपए में रजिस्ट्रेशन

कुत्तों के रजिस्ट्रेशन के लिए महज 150 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। हालांकि रजिस्ट्रेशन न कराने पर इससे 10 गुना पेनाल्टी देनी पड़ेगी। विभाग अब कुत्ते के साथ सभी पालतू जानवरों को माइक्रोचिप, जियो और ब्रांडिंग कोड से लैस करेगा। विभाग के इस नियम को एमआईसी के जरिए लागू किया जाएगा। इस नियम के तहत बिल्ली और गायों को भी लाया जाएगा। हालांकि भोपाल नगर निगम क्षेत्र में गाय पालने पर रोक लगी हुई है, नए नियम में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। दरअसल, कुत्तों को रिहायशी इलाके में घुमाने के कारण जो गंदगी फैलती है उससे स्थानीय लोगों में लड़ाई-झगड़े देखे गए हैं। विभाग आवारा कुत्तों को लेकर भी काम कर रहा है। इसके तहत हर जोन में कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनेंगे यहां आवारा कुत्तों को रखा जाएगा। इतना ही नहीं शहर से बाहर पशु अभयारण्य बनाया जाएगा। इसके साथ ही जानवरों के बर्थ कंट्रोल ऑपरेशन के लिए अभियान चलाए जाएंगे। अगर कोई अपने पालतू जानवर का रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो उसकी फोटो, नस्ल, उम्र और स्वास्थ्य संबंधित ब्यौरा देना होगा। कुत्ते का रैबीज टीकाकरण कराया गया है या नहीं, इसकी जानकारी भी देनी होगी। जानवरों के लिए कराए गए रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण हर साल किया जा सकेगा। इसके लिए केवल 50 रुपए खर्च करने होंगे। बताया जा रहा है कि विकास विभाग एक महीने के भीतर इस नियम को लागू कर देगा।

खरबों की जमीन पर झुग्गियां

मप्र ही नहीं देश के खूबसूरत शहरों में भोपाल भी शुमार है। यहां की आबोहवा और हरियाली आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। राजधानी की इसी खूबसूरती को देखते हुए 25 जून 2015 को इसे स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद शुरू हुई थी। तकरीबन 9 साल बाद भी भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना आधा-अधूरा है, लेकिन शहर में झुग्गी-झोपड़ियों का जाल लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारी आकड़ों का आंकलन करें तो राजधानी की खरबों रुपए से अधिक की जमीन पर आज झुग्गियां काबिज हैं। 10 प्रतिशत झुग्गियां हर साल शहर में बढ़ जाती हैं।

गौरतलब है कि देश के सबसे महंगे शहरों में भोपाल की गिनती होती है। यहां जमीनों के भाव सोने से भी अधिक महंगे हैं। इसके बावजूद यहां शहर के बीचों-बीच प्राइम लोकेशंस पर झुग्गी बस्तियां बसी हुई हैं। राजभवन से सटे इलाके में रोशनपुरा बस्ती, बाणगंगा, भीमनगर, विश्वकर्मा नगर जैसी टॉप-8 झुग्गी बस्तियां करीब 300 एकड़ में फैली हैं। इनके अलावा राहुल नगर, दुर्गा नगर, बाबा नगर, अर्जुन नगर, पंचशील, नया बसेरा, संजय नगर, गंगा नगर, बापू नगर, शबरी नगर, ओम नगर, दामखेड़ा, उड़िया बस्ती, नई बस्ती, मीरा नगर जैसी कुल 388 बस्तियां शहर में हैं। इन सबकी जमीन का हिसाब लगाएं तो यह करीब 1500 एकड़ के आसपास बैठती है। इनमें से ज्यादातर पॉश इलाकों में ही हैं।

भोपाल को स्लम फ्री सिटी करने के पीछे सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है, बावजूद इसके बस्तियों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ी है। सबसे ज्यादा झुग्गी वाले टॉप-10 शहरों में भोपाल का नाम भी शामिल है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि स्लम फ्री सिटी बनाने का सपना आखिर कब पूरा होगा। शहर स्मार्ट सिटी कैसे बनेंगे, जब हर कोशिश फेल हो रही है। सरकार झुग्गियों को हटाने के लिए लगभग 1400 करोड़ खर्च कर चुकी है, लेकिन इसके बाद भी बस्तियां लगातार बढ़ रही हैं। प्रदेश में भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की। कोई भी सरकार राजधानी भोपाल को झुग्गी से मुक्त नहीं करा पाई है। वर्तमान में पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने की कवायद की जा रही है। इधर घर और फ्लैट देने का अभियान धीमा हुआ और वहां झुग्गी बनाने की रफ्तार बढ़ती चली गई। वहीं सरहदी इलाकों में सबसे ज्यादा झुग्गियां बस गई हैं। सरकारी भूमि पर भी तेजी से कब्जों की संख्या बढ़ रही है।

सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भोपाल को झुग्गीमुक्त बनाने के लिए सरकार लगभग 1400 करोड़ खर्च कर चुकी है, लेकिन इसके बाद भी बस्तियां लगातार बढ़ रही हैं। 1984 में अर्जुन सिंह सरकार ने पहली बार झुग्गी मुक्त शहर के लिए अभियान चलाया। 2004 में बाबूलाल गौर ने झुग्गियों के री-डेंसिफिकेशन की योजना बनाई। 2015 में पीएम आवास योजना की शुरुआत हुई और शहर में पक्के मकान व पट्टे देने का अभियान शुरू हुआ। लेकिन सरकार के सारे प्रयास फेल होते चले गए। आज आलम यह है कि कोलार, अयोध्या बाइपास रोड, अवधपुरी भेल क्षेत्र, खजूरीकला, बरखेड़ा पठानी, करोंद, गांधीनगर, बैरागढ़, मिसरोद, 11 मील रोड, कटारा, बागमुगालिया, बागसेवनिया, पटेल नगर, कलियासोत कैचमेंट नेहरू नगर, नीलबड़, रातीबड़, भौरी आदि क्षेत्र में सबसे अधिक झुग्गी-झोपड़ियों का जाल बिछ गया है। हाउसिंग फॉर ऑल के तहत गरीबों के लिए साढ़े सात हजार से अधिक आवास बनने की योजना है। अभी तक साढ़े तीन हजार आवास बन चुके हैं। साढ़े चार हजार आवास और बनाए जाएंगे। 1100 आवास निर्माणाधीन हैं। वास्तविक हकदारों को आवास आवंटित किए गए हैं, लेकिन आलम यह है कि उसके बाद भी शहर में झुग्गी-झोपड़ियां बढ़ रही हैं। नगर निगम द्वारा जेएनएनयूआरएम, प्रधानमंत्री आवास योजना और हाउसिंग फॉर ऑल के तहत हितग्राहियों को बनाकर आवंटित किए गए 50 प्रतिशत से अधिक आवास किराए पर चल रहे हैं। पंचशील नगर, श्याम नगर, अर्जुन नगर, नेहरू नगर, जनता कॉलोनी, इंदिरा नगर, 11 नंबर, ईदगाह हिल्स, वाजपेयी नगर आदि क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के तहत गरीबों के लिए आवास बनाए गए हैं, जो बेहद कम दामों में झुग्गीवासियों को दिए गए। वर्तमान में यहां बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश आवास किराए पर हैं। यदि उक्त क्षेत्रों में जांच की जाए तो 50 प्रतिशत से अधिक आवासों के किराए पर चलने का खुलासा हो जाएगा।

● **विकास दुबे**

गठजोड़ से बढ़ रहा झुग्गियों का ग्राफ

शहर को झुग्गी मुक्त करने का सरकार का सपना शायद कभी साकार नहीं होगा, क्योंकि सरकारी कर्मचारी, स्थानीय नेता और झुग्गी माफिया के गठजोड़ से झुग्गियों को बसाने का कारोबार लंबे समय से चला आ रहा है। शहर में बढ़ता झुग्गियों का ग्राफ इस बात का जीता-जागता प्रमाण है, जबकि झुग्गियों के विस्थापन को लेकर कई योजनाएं बनीं, आवास बनाए गए, लेकिन झुग्गियों की संख्या कम नहीं हुई। झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने आवास तो लिए, लेकिन 50 प्रतिशत से अधिक हितग्राहियों ने उनको किराए पर दे दिया या बेच दिया है और आज वह लोग दोबारा झुग्गी में रह रहे हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि यही हाल रहा तो यह शहर कभी भी झुग्गी मुक्त नहीं हो पाएगा। नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनको इस बात की ही जानकारी नहीं है कि निगम द्वारा बनाए गए आवासों में कितने वास्तविक हकदार रहते हैं। अवैध झुग्गियों में रहने वाले परिवार प्रति वर्ष नगर निगम के जोनल कार्यालय से 700 रुपए शुल्क कटवाते हैं और एक बत्ती कनेक्शन के तहत 100 रुपए बिजली बिल भरते हैं। नियमानुसार अवैध होने की स्थिति में शुल्क लेने के बजाय कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यहीं पार्षद और भूमाफिया का गठजोड़ अपनी भूमिका निभाता है और शुल्क भुगतान करवाकर यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि संबंधित परिवार वर्षों से इस जगह पर काबिज है, जिसके आधार पर पट्टा स्वीकृत होता है।

क्या पूरा हो पाएगा पीएम आवास का लक्ष्य

नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में देश में तीन करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य से काफी पीछे हैं। जिस रफ्तार से इन दोनों राज्यों में निर्माण कार्य हो रहा है, उसे देखते हुए इन राज्यों को दिसंबर 2024 तक अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हर दिन करीब 6,000 घर बनाने की आवश्यकता होगी। उल्लेखनीय है कि किफायती आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में शुरू की गई थी। इसकी दो अलग-अलग शाखाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पीएमएवाई-ग्रामीण और अन्य के लिए पीएमएवाई-शहरी जैसी योजनाएं हैं। केंद्रीय बजट 2024-2025 में, केंद्र सरकार ने पीएमएवाई-जी के तहत अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाने की अपनी योजना की घोषणा की थी।

नव निर्वाचित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार ने 10 जून को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में पीएमएवाई के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण को मंजूरी दी। इनमें से 2 करोड़ पीएमएवाई-जी के तहत और बाकी पीएमएवाई-यू के तहत होंगे। सरकार ने साफ किया है कि ये तीन करोड़ घर पिछली योजनाओं के लक्ष्य के अतिरिक्त होंगे। सरकार ने शुरू में मार्च 2022 तक पीएमएवाई-जी के तहत 2.95 करोड़ और पीएमएवाई-यू कार्यक्रमों के तहत 1.2 करोड़ घर बनाने की समय सीमा तय की थी। हालांकि, सरकार इस लक्ष्य से चूक गई और अगस्त 2022 में सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने की समय सीमा दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई थी। पीएमएवाई-जी डैशबोर्ड के अनुसार, 2024 के अंत तक ग्रामीण इलाकों में 2.95 करोड़ घरों का लक्ष्य था, लेकिन 11 जून 2024 तक लगभग 2.62 करोड़ घरों का लक्ष्य ही पूरा हो पाया है, जो कुल लक्ष्य का 89 प्रतिशत है। अब देश को 11 जून, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 के बीच ग्रामीण इलाकों में 3,282,103 आवास इकाइयों का निर्माण पूरा करना है। इनमें से 11,57,788 आवास इकाइयां (या शेष का 35 प्रतिशत) अकेले पश्चिम बंगाल में बनाई जानी हैं, जिसका अर्थ है कि लक्ष्य पूरा होने तक राज्य में हर दिन 5,675 घर बनाने होंगे। पश्चिम बंगाल ने 31 दिसंबर, 2024 तक 45,69,423 घरों के निर्माण के राज्य के लक्ष्य का 75 प्रतिशत पूरा कर लिया है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के समग्र राष्ट्रीय प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी एक राज्य-स्तरीय रिपोर्ट के अनुसार, पांच राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने राज्य-स्तरीय पीएमएवाई-जी के लक्ष्य को आधे से भी कम पूरा किया है। इनमें नागालैंड, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और मेघालय शामिल हैं।

पक्के मकान की आस, हर दिन आवेदनों की लगी झड़ी

शिवराज सरकार की लाड़ली बहनों की 1250 रुपए की किस्त बढ़कर 1500 किए जाने की जहां चर्चा शुरू हो गई है, वहीं मोहन सरकार द्वारा लाड़ली बहनों को पक्के मकान देने की घोषणा के बाद छूटी महिलाओं ने आवेदन देना शुरू कर दिया है। सरकार ढाई हजार करोड़ रुपए के पक्के मकान लाड़ली बहनाओं को बनाकर देगी। जिसके लिए बजट में प्रावधान भी किया गया है। अगले 5 साल में बहनों को पक्के मकान बनाकर दिए जाने हैं। फिलहाल 1 करोड़ 30 लाख लाड़ली बहनाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली लाड़ली बहनाएं, जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है, वे इस योजना की पात्र रहेंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहनों को पक्के मकान देने की घोषणा करते ही छूटी हुई महिलाओं ने खुद को योजना में शामिल होने के लिए गुहार लगाई है। सीएम हेल्पलाइन पर बढ़ रही शिकायतों का आंकड़ा इन्हीं आवेदनों का है। महिला एवं बाल विकास विभाग अब इन्हें समझा-बुझाकर बंद कराने की कोशिश कर रहा है। ज्ञात हो कि हर माह 1250 रुपए की वित्तीय सहायता लेने के लिए महिलाएं सीएम हेल्पलाइन पर अब भी आवेदन कर रही है। लगभग 2077 से अधिक महिलाएं लाड़ली बहन होने का अधिकार चाहती हैं, लेकिन प्रशासन नियमों का हवाला देकर शिकायतें बंद करवा रहा है।

पीएमएवाई-यू के तहत शहरी क्षेत्रों में 31 दिसंबर, 2024 तक लगभग 1.2 करोड़ (कुल 1.186 करोड़) आवासों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा था। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध पीएमएवाई-यू की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से 11 जून, 2024 तक 83.6 लाख से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसका मतलब है कि लगभग 71 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो चुका है। देश को अब 11 जून, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 के बीच लगभग 35 लाख घरों का निर्माण पूरा करना है। इनमें से 34 प्रतिशत अकेले आंध्र प्रदेश में बनने हैं। इसका मतलब है कि आंध्र प्रदेश ने 31 दिसंबर, 2024 तक 2,137,028 घरों के निर्माण के राज्य के लक्ष्य का 45 प्रतिशत पूरा कर लिया है। शेष लक्ष्यों को पूरा करना पीएमएवाई-यू के समग्र राष्ट्रीय प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है। 31 दिसंबर, 2024 की समय-सीमा को पूरा करने के लिए, राज्य को 11,73,327 आवासीय इकाइयों यानी प्रतिदिन 5,752 घरों का निर्माण करना होगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की राज्य-स्तरीय रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश सहित छह अन्य राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने राज्यों में पीएमएवाई-यू के लक्ष्यों में से आधे से भी कम को पूरा किया है। इनमें अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, बिहार और कश्मीर शामिल हैं।

अब तक पीएमएवाई-जी ने पीएमएवाई-यू की तुलना में बेहतर प्रगति की है। हालांकि इन दोनों योजनाओं की नियमित रूप से निगरानी करने और चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 10 जून, 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पीएमएवाई-जी और पीएमएवाई-यू के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घरों का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सही गति से आगे बढ़े और 2030 तक तय समय पर पूरा हो। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत् विकास लक्ष्य 11 (स्थायी शहर और समुदाय) के तहत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो सीधे तौर पर 2030 तक सभी के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और किफायती और पर्याप्त आवास की बात करता है।

● **रजनीकांत पारे**

मप्र सरकार इस बार मानसून सत्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेगी। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने संकेत दिया है कि इस बार बजट में जनता पर टैक्स का कोई बोझ नहीं बढ़ेगा। यही नहीं सरकार ने बजट के लिए आम लोगों से सुझाव भी मांगा है। इसके लिए गत दिनों एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें वित्त मंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों से बजट के संदर्भ में चर्चा की। उधर, जानकारों का कहना है कि वित्तीय घाटा कम करने सरकार कई तरह के टैक्स का प्रावधान कर सकती है। अब सभी को एक जुलाई से शुरु होने वाले मानसून सत्र का इंतजार है।

नहीं बढ़ेगा टैक्स का बोझ

मप्र विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस सत्र में मोहन सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी। 25 जून को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वर्ष 2024-25 के बजट का प्रस्तुतीकरण हुआ। इसमें किए गए प्रविधानों पर सहमति जताई गई। वहीं विगत दिनों इस बजट की तैयारियों के सिलसिले में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने उद्योग समूह एवं वित्तीय संस्थाओं से जुड़े विशेषज्ञों के साथ संवाद किया। आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी के सभागार में आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में वित्तमंत्री देवड़ा ने कहा कि हमें लोगों की वित्तीय साक्षरता पर ध्यान देना होगा। रबी फसल आने पर निकासी बढ़ती है और खरीफ में जमा बढ़ता है। मंडियों में ट्रांजेक्शन नकद में अधिक होता है। 55 प्रतिशत नकद में लेनदेन होता है। स्कूल स्तर से ही वित्तीय साक्षरता पर जोर रहे। 75-76 लाख केसीसी है। 12 प्रतिशत एनपीए है। इससे अगला लोन प्रभावित होता है। 92 क्लस्टर 23 जिलों में हैं। इसमें समानता होनी चाहिए। सिंचाई के क्षेत्र में हमें अपना निवेश जारी रखना होगा। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि बजट सभी वर्गों के हित में होगा। जनता पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। उन्होंने संकेत दिए कि सरकार कोई कर नहीं बढ़ाएगी। कोई भी योजना बंद नहीं होगी। कांग्रेस के बार-बार प्रदेश के ऊपर कर्ज अधिक होने और अर्थव्यवस्था को लेकर उठाए जाने वाले प्रश्नों पर कहा कि वह बौखला गई है। उसे आत्मचिंतन करना चाहिए। कर्ज निर्धारित सीमा के भीतर ही लिया जा रहा है। कोई भी योजना बंद नहीं होगी। सबके लिए बजट प्रविधान होंगे।

उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि वित्त विभाग कई नवाचार कर रहा है। हमने बजट को लेकर जनता से इस वर्ष भी सुझाव मांगे हैं, क्योंकि प्रदेश का बजट जनता का बजट है, और जनता द्वारा बजट बनाया जाना, हमारे लोकतंत्र की अवधारणा को मजबूत करता है। हमने परंपरा विकसित की है कि आम जनता, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों तथा विषय विशेषज्ञों की वैचारिक भागीदारी से मिले बहुमूल्य सुझावों के आधार पर प्रदेश के बजट को प्रगतिशील स्वरूप दिया जाए। यह निरंतर तीसरा वर्ष है, जब हम पुन: आप सभी के सुझावों के आधार पर प्रदेश का बजट और अधिक विकसित, उन्नति, लोक कल्याणकारी व परिणाम जनक बनाने का कार्य करेंगे। देवड़ा ने कहा कि हमने वेबसाइट, ई-मेल, फोन और डाक से आम जनता से भी सुझाव प्राप्त किए हैं। महत्वपूर्ण सुझावों के आधार पर हमारी सरकार ने चाइल्ड बजट लागू किया। पेसा एक्ट को प्रभावी रूप से लागू किया। स्वास्थ्य क्षेत्र में समुचित बजट का प्रावधान रखा है। साथ ही सेमीकंडक्टर कंपनियों का प्रोत्साहन, गैर पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन दिया है। एमएसएमई सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया। औद्योगिक विकास की नीतियों को सरल बनाने जैसे कार्य भी किए।

विधानसभा में मुख्यमंत्री की ओर से 7 राज्यमंत्री देंगे जवाब

1 जुलाई से शुरू होने जा रहे विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की ओर से 7 राज्यमंत्री उत्तर देंगे। इसकी सूचना उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को भी दे दी है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए राज्यमंत्री कृष्णा गौर, धर्मेंद्र सिंह लोधी, गौतम टेटवाल, नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार और राधा सिंह को अधिकृत किया है। मुख्यमंत्री के पास सामान्य प्रशासन, गृह, जेल, खनिज साधन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, प्रवासी भारतीय, विमानन, नर्मदा घाटी विकास, जनसंपर्क, विधि एवं विधायी कार्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आनंद और लोक सेवा प्रबंधन विभाग हैं। विधानसभा में इनसे जुड़े प्रश्न यदि प्रश्नकाल में आते हैं तो अधिकृत मंत्रियों द्वारा इनके उत्तर दिए जाएंगे। संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रश्न दिनांक से पूर्व संबंधित राज्यमंत्री के साथ बैठकर उन्हें संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, ताकि सदस्य की जिज्ञासा का समाधान किया जा सके। अतारांकित प्रश्नों के उत्तर अधिकारियों द्वारा मंत्रियों के अनुमोदन से विधानसभा सचिवालय भेजे जाएंगे। कोई भी उत्तर अपूर्ण न हो, इसके लिए अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश कुमार राजौरा पहले ही अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्न और पूर्व के आश्वासनों को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा निगरानी भी की जा रही है।

बजट संवाद के दौरान आरबीआई के महाप्रबंधक हेमंत सोनी, नाबार्ड के उप महाप्रबंधक नंदू जे नाइक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी नई दिल्ली के प्रताप रंजन जेना भी मौजूद हैं। इस संवाद में कांता सिंह डिप्टी कंट्री रिप्रजेंटेटिव यूएन वूमेन इंडिया, मिस ह्यून ही बान चीफ सोशल पॉलिसी यूनिसेफ इंडिया, सिद्धार्थ चतुर्वेदी एक्स चेयरमैन सीआईआई, योगेश दुबे भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, केवी प्रताप सीनियर इकोनॉमिक एडवाइजर भारत सरकार के भी सुझाव लिए गए। गौरतलब है कि वित्त और वाणिज्यिक कर विभाग के मंत्री व उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने संभागीय स्तर पर बैठकें करके लोगों से सुझाव लिए। इसके पहले वित्त विभाग ने लोगों से ऑनलाइन और ऑफलाइन सुझाव भी बजट को लेकर मांगे। खास बात यह है कि इस बार अधिकांश विधायकों ने ऑनलाइन सवाल पूछा है। पिछले पांच साल में यह पहला अवसर है जब विधायकों ने ऑफलाइन से अधिक ऑनलाइन सवाल पूछा है। विधानसभा के मानसून सत्र में इस बार नर्सिंग घोटाले की गूंज सुनाई देने वाली है। क्योंकि विधायकों ने सबसे ज्यादा सवाल नर्सिंग घोटाले और कानून व्यवस्था को लेकर लगाए हैं। विपक्ष के विधायकों ने भी इसी मुद्दे से जुड़े सवाल पूछे हैं। बता दें कि मप्र विधानसभा का आगामी मानसून सत्र 1 जुलाई से 19 जुलाई तक रहेगा। जिसमें इस बार कई अहम बैठकें होंगी। इसी सत्र में बजट भी आना है। ऐसे में बजट को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं।

विधानसभा के मानसून सत्र में विधायकों ने 4 हजार से ज्यादा सवाल लगाए हैं। इस बार विधायकों ने नर्सिंग, कानून व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य, राजस्व विभाग से जुड़े सबसे ज्यादा सवाल पूछे हैं। विधायकों के पास विधानसभा में ऑनलाइन या ऑफलाइन सवाल लगाने का प्रावधान था। विधानसभा सचिवालय के पिछले पांच सालों से चल रहे प्रयास अब कारगर होते दिख रहे हैं। विधानसभा के बजट सत्र में पहली बार विधायकों ने ऑनलाइन प्रश्न ज्यादा पूछे हैं। ऑफलाइन सवालों की संख्या ऑनलाइन से अब कम हो गई है। इस बार विधायकों ने 4 हजार 287 सवाल लगाए हैं। इनमें ऑनलाइन सवालों की संख्या 2 हजार 386 तो ऑफलाइन की 1901 है। विधानसभा के मानसून सत्र में इस बार कुल 14 बैठकें होंगी। जिसमें मोहन सरकार मानसून सत्र में 8 से 10 विधेयक ला सकती है। इसके लिए मोहन सरकार के कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट भी इसी सत्र में आने वाला है। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। जिसके लिए सरकार ने जनता से भी बजट बनाने को लेकर सवाल पूछे हैं। बजट के बाद इस पर भी चर्चा होगी। जिसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही तैयारियां कर रहे हैं। विधानसभा सत्र के पहले दोनों पार्टियों के विधायक दलों की बैठकें भी होंगी।

गौरतलब है कि विधानसभा सचिवालय में विधायकों को नई तकनीक के साथ कदमताल करने के लंबे समय से प्रयास कर रहा है। इसके लिए विधायकों को पूर्व में लैपटाप भी दिए गए थे। इसके बाद सचिवालय ने विधायकों से इस बात का आग्रह किया कि वे नई तकनीक का प्रयोग करें और ऑनलाइन सवाल ज्यादा लगाएं। इसके लिए दो बार विधायकों के प्रशिक्षण सत्र भी सदन के मानसरोवर स्थित सभागार में आयोजित किए गए। शुरूआत में इसके सार्थक परिणाम नहीं आए। इसके बाद यह तय किया गया कि विधायकों के सहायकों को प्रशिक्षण दिया जाए। विधानसभा सचिवालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक अब विधायक ऑनलाइन तकनीक का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं और अधिकांश विधायक नई तकनीक का भी प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं। 30 मई को विधानसभा सत्र का विस्तृत कार्यक्रम घोषित किया गया था। इसके बाद विधायकों ने सवाल लगाने शुरू किए थे। इस बार आए 4 हजार 287 सवालों में 2109 तारांकित और 2179 अतारांकित सवाल हैं। वहीं सवालों का दौर समाप्त होने के बाद 25 जून से स्थगन और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों का सिलसिला शुरू हुआ। इसमें विधायक अपने क्षेत्र से जुड़े लोक महत्व के मसलों को सदन में उठाते हैं। इसी के साथ विधायक शून्यकाल में पढ़ी जाने वाली सूचनाएं भी सचिवालय को दी। महत्वपूर्ण यह है कि इस सत्र में सरकार इस वित्तीय बर्ष का बजट भी पेश करेगी।

सूत्रों की मानें तो बजट तीन या चार जुलाई को ही पेश हो सकता है। इसके बाद इस पर चर्चा होगी और सदन इसे बहुमत से पास करेगा। इसके अलावा सदन में कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश होंगे। पिछले कुछ सालों में सदन में बैठकों की संख्या लगातार कम हो रही है। इस बार बजट सत्र 1 जुलाई से 19 जुलाई तक चलेगा। 19 दिवसीय इस सत्र में कुल 14 बैठकें होनी है। पूर्व में बजट सत्र एक महीने से अधिक समय का होता था। जिसमें कम से कम 22 से 26 दिन की बैठकें होती थीं पर अब सत्र में सीमित बैठकें होती हैं। अधिकांश बार तो यह होता है कि हंगामे के चलते सत्र अपनी निर्धारित अवधि तक चल ही नहीं पाता।

● **कुमार राजेंद्र**

हंगामेदार होगा विधानसभा सत्र

नर्सिंग मामले समेत प्रवेश परीक्षाओं में हो रही कथित अनियमितताओं को लेकर इस बार सदन के खासे गर्माने के आसार हैं। इस मामले पर कांग्रेस काम रोको प्रस्ताव भी ला सकती है। माना जा रहा है कि विधानसभा का सत्र शुरू होते ही इस मामले पर कांग्रेस सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। इस कारण सदन में पक्ष-विपक्ष में टकराव के आसार हैं। विधानसभा सचिवालय के सूत्रों की मानें तो इस बार नर्सिंग घोटाले में सीबीआई अफसरों की गिरफ्तारी समेत प्रवेश परीक्षाओं में कथित तौर पर गड़बड़ी और कानून व्यवस्था से जुड़े मसलों पर विधायकों ने ज्यादा सवाल लगाए हैं। इसके अलावा किसानों की समस्याओं से जुड़े सवाल भी हैं। पेयजल की दिक्कत, नल-जल योजनाओं को लेकर भी कई विधायकों ने सवाल लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने नर्सिंग घोटाले को लेकर एक पोस्टर जारी किया है। इसमें लिखा है कि मप्र में व्यापमं घोटाले के स्तर पर नर्सिंग कॉलेजों में घोटाला हुआ है। इस घोटाले ने व्यापमं घोटाले को भी पीछे छोड़ दिया है। इसमें फर्जी कॉलेजों को मान्यता देने, फर्जी डिग्रियां बांटने और छात्रों से अवैध स्कॉलरशिप लेने में भी बड़ी गड़बड़ी हुई है। इस घोटाले में भाजपा से जुड़े कई बड़े नेताओं की संलिप्तता भी उजागर हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने जनता से अनुरोध करते हुए लिखा कि मप्र विधानसभा के मानसून सत्र में इस घोटाले को उजागर करने में मदद करें। उन्होंने आगे लिखा कि आपके पास नर्सिंग घोटाले से संबंधित जो भी जानकारी, दस्तावेज, फोटो, वीडियो, कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य जानकारी हो तो व्हाट्सअप या ई-मेल आईडी पर भेजें। उन्होंने आगे लिखा कि जानकारी देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

उपचुनाव में असली परीक्षा

2023 के विधानसभा चुनाव और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मप्र की सियासत में एक बार फिर चुनावी चौसर सज गई है। प्रदेश में कुछ सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। पहला उपचुनाव पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट पर हो रहा है। जिसमें कांग्रेस अपनी साख बचाने के लिए अब नए गेम प्लान के साथ उतर रही है। कांग्रेस के लिए यह अपनी साख बचाने का मौका है।

गौरतलब है कि 25 सालों से मप्र में भाजपा बेहद मजबूत स्थिति में है पर आगामी उपचुनाव से कांग्रेस उम्मीदें लगाकर बैठी है। मप्र की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी है। पहली सीट जिस पर उपचुनाव होना है, वह है छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट। यहां के वर्तमान विधायक कमलेश शाह के भाजपा में शामिल होने की वजह से यहां उपचुनाव हो रहे हैं। वहीं दूसरी सीट है बुधनी। दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से सांसद बनकर केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। ऐसे में अब उनकी विधायकी वाली ये सीट भी खाली हो गई है।

विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारने वाली कांग्रेस अब नए गेम प्लान के साथ मैदान में उतरी है। फिलहाल कांग्रेस की प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ का दखल फिर बढ़ गया है। कमलनाथ छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए काफी एक्टिव हैं। वहीं इस बार उन्होंने उपचुनाव में ऐसा प्रत्याशी उतार दिया है, जो भाजपा प्रत्याशी के दांत खट्टे कर सकता है। दरअसल, मप्र में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारने वाली कांग्रेस अब नए गेम प्लान के साथ मैदान में उतरी है। कांग्रेस ने उपचुनाव को लेकर अभी से घेराबंदी शुरू कर दी है। पार्टी ने इन विधानसभाओं में अपने ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं, जो जीतने वाले प्रत्याशी के चयन के साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए जुट गए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो अमरवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस भाजपा पर भारी पड़ सकती है। इस चुनाव में प्रत्याशी चयन से लेकर कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकते हैं। जिस अमरवाड़ा सीट से कांग्रेस के कमलेश शाह तीन बार चुनाव जीतकर विधायक बने, उसी सीट पर अब वे भाजपा के टिकट से लड़ेंगे। दरअसल, लोकसभा चुनाव के दौरान कमलेश भाजपा में शामिल हो गए थे। हालांकि, उन्हें दलबदल करने पर क्षेत्रीय जनता की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर आदिवासियों का खासा प्रभाव है। कमलनाथ ने इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी चयन में मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। उन्होंने आदिवासी आस्था के केंद्र आंचलकुंड धाम के छोटे महाराज धीरनशाह को टिकट दिलाया है। धीरनशाह इनावती आंचलकुंड के प्रमुख गणेश महाराज के छोटे भाई भी हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कमलेश शाह के प्रति नाराजगी और धीरनशाह के मैदान में उतरने का असर आदिवासी वोटर्स पर साफ पड़ेगा और ये कांग्रेस के पक्ष में हो सकता है।

श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत और सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस की निर्मला सप्रे के भाजपा में शामिल होने के बाद दोनों विधायकी से इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में श्योपुर और बीना में भी उपचुनाव की स्थिति बन रही। विजयपुर विधानसभा में संभावित उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने छह सदस्यीय समिति बनाई है। इसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह, राज्यसभा सदस्य अशोक सिंह, पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव, विधायक फूल सिंह बरैया, विधायक दिनेश गुर्जर और मुरैना से लोकसभा प्रत्याशी रहे सत्यपाल सिंह सिकरवार को शामिल किया गया है। इधर, बीना विधानसभा में संभावित उपचुनाव के लिए बनाई गई समिति में विधायक लखन धनधीरिया, पूर्व विधायक कुणाल चौधरी और सब यादवेंद्र सिंह यादव को शामिल किया गया है। विजयपुर और बीना विधानसभा सीट के लिए गठित समितियों के सदस्य इन क्षेत्रों का दौरा कर ब्लॉक, मंडलम सेक्टर के गठन एवं बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती के लिए काम करेंगे। उपचुनाव के लिए विधानसभा स्तर पर पुनर्गठन करने की कार्ययोजना तैयार करेंगे।

अमरवाड़ा के अलावा बुधनी में भी जल्द निर्वाचन आयोग उपचुनावों की घोषणा कर सकता है। विधानसभा सीटों के अलावा प्रदेश में एक राज्यसभा सीट भी खाली हो रही है। दरअसल, ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुना से लोकसभा सांसद बनने के बाद उनकी राज्यसभा सीट खाली हो रही है, जिससे राज्यसभा सीट पर भी चुनाव होगा। लेकिन प्रदेश में भाजपा विधायकों की बड़ी संख्या की वजह से राज्यसभा सीट के लिए वोटिंग होने की संभावना नहीं है।

● **जितेंद्र तिवारी**

कमलनाथ के पास एक आखिरी मौका

कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के लिए अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव राजनीतिक संजीवनी साबित हो सकते हैं। छिंदवाड़ा में एक बार फिर कमलनाथ और भाजपा के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि अमरवाड़ा विधानसभा में 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। भाजपा ने इसे लेकर रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। 1980 से छिंदवाड़ा में राजनीति कर रहे कमलनाथ को लोकसभा चुनाव में भाजपा ने हार का मुंह दिखा दिया था। उनके बेटे नकुलनाथ को भाजपा के विवेक बंटी साहू ने एक लाख से ज्यादा वोटों से करारी शिकस्त दी, लेकिन 44 साल बाद हार का मुंह देखने वाले कमलनाथ के लिए ये राजनीति का अंत नहीं है। यहां अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव उनके लिए वापसी का एक आखिरी मौका साबित हो सकता है। विधानसभा चुनाव के पहले तक मप्र की राजनीति के मुखिया रहे कमलनाथ चुनाव के बाद से पार्टी में हाशिये पर चल रहे थे। हालांकि, उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान छिंदवाड़ा में ही अपने बेटे नकुलनाथ को चुनाव जिताने के लिए फोकस किया था। लोकसभा में मिली हार के बाद कमलनाथ और अलग-थलग पड़ गए हैं और अपना गढ़ न बचा पाने पर उन्हें पार्टी के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में कमलनाथ के सामने खुद को साबित करने के लिए एक और मौका है। अगर अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस चुनाव जीतती है तो यह कमलनाथ के लिए राजनीतिक संजीवनी साबित होगी।

अनावश्यक खर्च पर लगेगी पाबंदी

पूंजीगत कार्यों में मप्र की परफॉर्मेंस बेहतर

उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने केंद्रीय वित्तमंत्री को अवगत कराया कि पूंजीगत कार्यों के लिए निर्धारित मापदंडों की पूर्ति करने में प्रदेश सफल रहा है। वर्ष 2023-24 में भारत सरकार से इस योजना में 12,637 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। योजना के भाग एक के तहत 3,829 करोड़ की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई गई। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि विशेष केंद्रीय सहायता में वर्ष 2024-25 के लिए 10,910 करोड़ रुपए के प्रस्ताव में से 4,318 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। देवड़ा का कहना है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मप्र में अधोसंरचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए पूंजीगत कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में पूंजीगत कार्यों की राशि 60,689 करोड़ रुपए थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह राशि 46,798 करोड़ थी। यह वृद्धि 29 प्रतिशत है। उन्होंने मप्र के प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र से अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने की अपेक्षा की। देवड़ा ने यह भी रेखांकित किया कि मप्र में 2021-22 से लगातार राजस्व आधिक्य की स्थिति है। इसका श्रेय राज्य के कुशल वित्तीय प्रबंधन, विभागीय दक्षता और करदाताओं को जाता है।

मप्र सरकार विकास कार्यों के लिए लगातार कर्ज ले रही है। इस कारण प्रदेश सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में कर्ज का कुल हिसाब-किताब लगाया जाए तो प्रदेश के ऊपर 3 लाख 73 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया है। यानी प्रति व्यक्ति ये कर्ज 47 हजार रुपए हो गया है। ऐसे में अब सरकार की कोशिश है कि अनावश्यक खर्च पर पाबंदी लगाकर प्रदेश को कर्ज से उबारा जाए। इसके लिए सरकार ने अधिकारियों के एक वर्ग को मप्र को कर्ज से उबारने का फॉर्मूला तैयार करने को कहा है। ये अधिकारी खर्च में कटौती कैसे की जाए इसका सुझाव सरकार को देंगे।

गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सरकार ने अलग-अलग किश्तों में 42,500 करोड़ रुपए का कुल कर्ज लिया था। आखिरी बार मोहन यादव सरकार ने 27 मार्च को तीन अलग-अलग तरीके से कुल 5000 करोड़ का कर्ज लिया था। कर्ज में डूबी मप्र सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। मप्र फाइनेंस डिपार्टमेंट ने करीब डेढ़ महीने पहले केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था जिसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने की इजाजत दे दी गई है। ऐसे में अब प्रदेश सरकार आधारभूत संरचना से जुड़े खर्चों के लिए 2000 से 2500 करोड़ का कर्ज इसी महीने में ले सकती है।

प्रदेश सरकार सड़क, पुल जैसे विकास कार्यों और लाड़ली बहना योजना की सुचारू व्यवस्था के लिए जून महीने में कर्ज ले सकती है। लाड़ली बहना योजना का हर महीने का खर्च 1676 करोड़ है। फरवरी महीने में विधानसभा में लेखानुदान 1.45 लाख करोड़ का प्रस्ताव पारित हुआ था। हालांकि इसमें नए करों के प्रस्ताव और नए खर्चों के प्रस्ताव शामिल नहीं थे। इसमें सरकार के 4 महीनों के खर्च की व्यवस्था थी। हालांकि आकस्मिक खर्चों के लिए मार्केट लोन लिया जा सकता है। मार्केट लोन के अलावा गवर्नमेंट बॉन्ड को गिरवी रखकर भी सरकार लोन लेती है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक किसी भी राज्य के एसजीडीपी के 3 प्रतिशत के बराबर राज्य कर्ज ले सकता है। मप्र की एसजीडीपी लगभग 15 लाख करोड़ है, जिसके मुताबिक प्रदेश की कर्ज लिमिट 45,000 करोड़ है। जीएसडीपी में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए ये लिमिट भी लगभग इतनी ही रहेगी।

जानकारी के अनुसार सरकार ने आवक बढ़ाने और गैरजरूरी खर्चों पर कैंची चलाने वाले मॉडल पर काम शुरू किया है। यह कवायद प्रदेश को कर्ज से निकालने के लिए शुरू की गई है। जिम्मेदारी चुनिंदा अधिकारियों को दी है। वे उन खर्चों को सूचीबद्ध करवा रहे हैं, जिन पर राजस्व का बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है। सरकार की मंशा है कि ऐसे खर्चों को सीमित किया जाए, जो जरूरी नहीं, उन्हें भविष्य में बंद भी किया जा सकता है। इससे पहले ऐसे खर्चों का परीक्षण किया जाएगा। देखा जाएगा कि जनता पर इसका असर तो नहीं पड़ेगा। उधर, अधिकारियों की टीम उन स्रोत को खंगाल रही है, जो राजस्व में इजाफा कर सकते हैं लेकिन किसी न किसी कारण उन पर ध्यान नहीं है या लापरवाही बरती जा रही है। सरकार की कवायद में सबसे अहम बात यह सामने आई कि कर्ज के बोझ को कम करने के लिए किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। सरकार के संज्ञान में आया है कि प्रदेश के कुछ व्यापारी इमारती लकड़ी का आयात कर रहे हैं, जिसके कारण राजस्व का बड़ा हिस्सा बाहर जा रहा है। मप्र भी वन वाला राज्य है, जहां भरपूर इमारती लकड़ी है। अब सरकार ने इस क्षेत्र को संज्ञान में लिया है। वन विभाग से रिपोर्ट मांगी है कि मप्र में बाहर से लाई जा रही इमारती लकड़ी का स्टेटस क्या है। ऐसे व्यापारियों को यह कदम क्यों उठाना पड़ रहा है। सरकार जल्द ही व्यापारियों से बात कर स्थानीय इमारती लकड़ी खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अड़चनों को दूर किया जाएगा। इसी तरह के तमाम विकल्पों पर काम किया जा रहा है।

हर साल राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य तय किए जाते हैं। कुछ विभाग अच्छा प्रदर्शन कर लक्ष्य से ज्यादा हासिल करने में सफल हो रहे हैं तो कुछ विभाग पिछड़ रहे हैं। ऐसे विभागों के प्रमुखों को दो टूक कहा गया है कि कमियां दूर करें और लक्ष्य प्राप्ति के लिए काम करेंगे। आने वाले समय में जो अधिकारी इस बात को नहीं समझ पाएंगे, उनकी जिम्मेदारी बदली जाना तय बताया जा रहा है। गौरतलब है कि सरकार पर 3 लाख 73 हजार करोड़ से अधिक का कर्ज है, जो भविष्य में बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खुद इस पर अधिकारियों के साथ कई दौर का मंथन कर चुके हैं। उनका लक्ष्य है कि सरकार की खुद की आवक बढ़ाकर कर्ज के इस बोझ को कम करे। इसके लिए सभी को मैदानी स्तर पर काम करने के लिए कहा गया है। मप्र सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अपनी संपत्तियों को बेचने या फिर किराए पर देने का प्लान कर रही है। इसके लिए वित्त विभाग ने पिछले महीने अन्य राज्यों में स्थित मप्र सरकार की संपत्तियों की जानकारी सभी विभागों से मांगी थी।

● **प्रवीण सक्सेना**

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने 6 माह के कार्यकाल में कई क्रांतिकारी फैसले लिए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने हाल ही में आयकर की दृष्टि से 1972 के नियम में बदलाव करते हुए निर्णय लिया है कि मप्र सरकार मंत्रियों का इनकम टैक्स अब नहीं भरेगी। यानी मुख्यमंत्री और मंत्री उनके वेतन और भत्ते पर लगने वाले टैक्स को खुद ही भरेंगे। सरकार के इस फैसले को आम जनता ने हाथों हाथ लिया है। वहीं अब जनता की मांग है कि माननीयों की पेंशन पर मेहरबानी कब तक जारी रहेगी।

माननीयों की पेंशन पर मेहरबानी क्यों...?

मप्र में सरकार पिछले 52 साल से मंत्रियों का इनकम टैक्स भरती आ रही थी, लेकिन अब प्रदेश सरकार उनका इनकम टैक्स जमा नहीं करेगी। इसका भुगतान अब मंत्री ही करेंगे। मप्र सरकार ने 1972 का नियम बदल दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट ने यह फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि मंत्रियों को मिलने वाले भत्ते पर लगने वाला इनकम टैक्स राज्य सरकार देती है। इसमें सुधार किया जाना चाहिए। इसके बाद सभी ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर सहमति दी और इससे संबंधित अधिनियम समाप्त कर मंत्रियों के भत्ते पर लगने वाला इनकम टैक्स सरकार से जमा कराने की व्यवस्था खत्म करने को कहा है। इसके बाद अब मंत्री खुद इनकम टैक्स भरेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष और राज्यमंत्री का आयकर जमा करने के लिए बजट में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसमें टैक्स योग्य राशि का आंकलन करने के बाद संबंधित वेतन से टैक्स की कटौती के बाद यह राशि विभाग के द्वारा अब तक लौटाई जाती थी।

मंत्रियों का इनकम टैक्स भरने की परंपरा खत्म करने के बाद अब सरकार से मांग की जाने लगी है कि माननीयों की पेंशन भी खत्म की जाए, क्योंकि प्रदेश में कर्मचारियों को भी पेंशन नहीं मिलती है। गौरतलब है कि मप्र में मुख्यमंत्री को 2 लाख रुपए वेतन मिलता है। वहीं, कैबिनेट मंत्रियों को 1.70 लाख रुपए माह वेतन मिलता है। राज्य मंत्रियों को 1.45 लाख रुपए माह और विधायकों को 1.10 लाख रुपए वेतन मिलता है। इसमें बेसिक सैलरी, सत्कार भत्ता, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और दैनिक भत्ता शामिल है। देश के मंत्री, सांसद और विधायक पुरानी पेंशन ले रहे हैं। सरकार खुद कई नेताओं को तो लाखों रुपए पेंशन दे रही है। वहीं, अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को पेंशन नहीं देना चाहती। खुद नेता पुरानी पेंशन लेना चाहते हैं और कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। नई पेंशन स्कीम में सिर्फ ढाई हजार रुपए महीने ही मिलेंगे। जबकि पुरानी पेंशन के अनुसार यह राशि हर महीने 50 हजार रुपए तक होगी। दरअसल, मप्र में विधानसभा चुनाव के बाद ही सरकारी कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन को लेकर एक बार मुद्दा उठ गया है। इसकी मांग तेज हो गई है। जहां सरकार इनको पेंशन देने के लिए वित्त नहीं होने की बात कहती है वहीं, नेता, मंत्री, विधायकों और सांसदों को लाखों की पेंशन मिल रही है।

कर्मचारियों ने कहा कि सरकार नेताओं, सांसदों, विधायकों को पुरानी पेंशन का लाभ दे रही है। कर्मचारियों को नई पेंशन देकर छला जा रहा है। कर्मचारी 35 से 40 साल नौकरी करता है, जबकि नेता 5 साल में ही पेंशन का पात्र हो जाता है। नेताओं के लिए खजाना खोल दिया जाता है, कर्मचारियों के लिए तिजोरी बंद कर दी है। मप्र में एक दिन के लिए भी विधायक बन गए तो हर महीने 20 हजार रुपए की पेंशन फिक्स हो जाती है। इस पेंशन में हर साल 800 रुपए इजाफा भी होता है। छत्तीसगढ़ में विधायकों को हर महीने 35,000 रुपए और सबसे ज्यादा मणिपुर के विधायकों को 70,000 रुपए महीने पेंशन मिलती है। मप्र में पूर्व विधायकों को ऐसी ढेरों सुविधाएं करीब निशुल्क मिलती रहती हैं। अगर कोई विधायक बाद में सांसद बन जाए तो उस

किसे कितना मिलता है वेतन-भत्ता

मुख्यमंत्री- वेतन 50 हजार रुपए, सत्कार भत्ता 55 हजार रुपए, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 50 हजार रुपए, दैनिक भत्ता 45 हजार रुपए राज्य के भीतर और राज्य के बाहर ढाई हजार रुपए प्रतिदिन।

विधानसभा अध्यक्ष- वेतन 47 हजार रुपए, सत्कार भत्ता 48 हजार रुपए, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 45 हजार रुपए, दैनिक भत्ता डेढ़ हजार रुपए प्रतिदिन।

नेता प्रतिपक्ष- वेतन 45 हजार रुपए, सत्कार भत्ता 45 हजार रुपए, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 35 हजार रुपए, दैनिक भत्ता डेढ़ हजार रुपए।

कैबिनेट मंत्री- वेतन 45 हजार रुपए, सत्कार भत्ता 45 हजार रुपए, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 35 हजार रुपए, दैनिक भत्ता राज्य के भीतर 45 हजार रुपए प्रतिमाह और राज्य के बाहर ढाई हजार रुपए प्रतिदिन।

विधानसभा उपाध्यक्ष- वेतन 45 हजार रुपए, सत्कार भत्ता 45 हजार रुपए, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 35 हजार रुपए, दैनिक भत्ता डेढ़ हजार रुपए प्रतिदिन।

राज्यमंत्री- वेतन 40 हजार रुपए, सत्कार भत्ता 34 हजार रुपए, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 31 हजार रुपए, दैनिक भत्ता 45 हजार रुपए प्रतिमाह और राज्य के बाहर ढाई हजार रुपए प्रतिदिन।

नेता को दोनों पेंशन यानि विधायक की भी और सांसद की भी राशि, हर महीने डबल पेंशन मिलती हैं। मप्र के सूचना के अधिकार कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ को मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2020-21 में पूर्व सांसदों के पेंशन के रूप में लगभग 100 करोड़ रुपए (99.22 करोड़) दिए गए हैं। आपको बता दें कि एक दिन के लिए सांसद बनने पर ही हर महीने 25,000 रुपए की पेंशन तय हो जाती है। पूर्व सांसद रेल यात्रा फ्री दी है। जबकि सरकारी कर्मचारी को किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाता है।

संसद के सदस्यों चाहे वह लोकसभा का सदस्य हो या फिर राज्यसभा का, संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम-1954 के तहत पेंशन मिलती है। यह राशि फिलहाल हर महीने 25 हजार रुपए बताई जाती है। इसके अलावा अगर कोई सांसद पांच साल से अधिक समय तक सांसद रहता है यानी जैसे-जैसे कार्यकाल बढ़ता है, उसकी वरिष्ठता का सम्मान करते हुए हर साल 1500 रुपए हर महीने अलग से दिए जाते हैं। यही नहीं, उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे, तो उनकी अगुवाई में बनी कमेटी ने पेंशन की राशि बढ़ाने की सिफारिश की थी। इसे 35 हजार रुपए करने का प्रस्ताव किया गया था। सबसे खास बात यह है कि सांसदों की पेंशन के लिए किसी न्यूनतम कार्यकाल की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। यानी कोई एक दिन के लिए सांसद बने या फिर 80 साल की उम्र तक सांसद रहे, उसे संसद सदस्य न रहने पर आजीवन पेंशन मिलती ही रहेगी। यही नहीं, सांसदों के परिवार के लिए भी पेंशन की सुविधा है। यानी पति, पत्नी या सांसद के आश्रित को पेंशन दी जाती है। किसी सांसद या पूर्व सांसद की मौत होने पर उसके पति, पत्नी या आश्रिम को आधी पेंशन ताउम्र दी जाती है।

इसके अलावा पूर्व सांसदों को मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा भी मिलती है। अगर कोई पूर्व सांसद एक सहयोगी संग ट्रेन में सफर करता है तो दोनों सेकंड एसी में फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। पूर्व सांसद चाहे तो अकेले फर्स्ट एसी में फ्री यात्रा कर सकता है। राज्य विधानसभाओं और विधान परिषद में भी पेंशन का यही नियम लागू होता है। कोई एक दिन

के लिए विधायक चुना जाए या लंबे समय के लिए, उसे पेंशन मिलनी ही मिलनी है। वरिष्ठ विधायकों यानी लगातार कई बार विधायक चुने जाने के बाद मिलने वाली पेंशन राशि में सांसदों की ही तर्ज पर थोड़ी वृद्धि हो जाती है। हालांकि, राज्यों में विधायकों के लिए पेंशन की राशि अलग-अलग है। इन सबसे हटकर पंजाब में एक अलग ही नियम था, जिसे आम आदमी पार्टी के भगवंत मान के मुख्यमंत्री बनने पर खत्म किया गया है। पंजाब में नियम था कि कोई नेता जितनी बार विधायक चुना जाएगा, उतनी बार के लिए उसे अलग-अलग पेंशन मिलेगी। यानी एक बार विधायक बनने पर किसी को कम पेंशन मिलती थी तो 10 बार विधायक रहे नेता को 10 गुना पेंशन मिलती थी। वहां 10 बार विधायक चुने जा चुके नेता की पेंशन 6.62 लाख रुपए महीना तक पहुंच गई थी। भगवंत मान की सरकार ने इस नियम को बदला और अब सभी विधायकों के लिए हर महीने 75 हजार रुपए महीना पेंशन तय की है।

चलते-चलते आइए संसद के लिए चुने गए माननीयों को मिलने वाले वेतन के बारे में भी जान लेते हैं। पीआरएस इंडिया के डाटा से पता चलता है कि भारत में सांसदों को 1 लाख रुपए वेतन मिलता है। ड्यूटी के दौरान प्रतिदिन दो हजार भत्ता अतिरिक्त मिलता है। इनके अतिरिक्त हर महीने 70 हजार रुपए निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता दिया जाता है, जबकि हर महीने 60 हजार रुपए कार्यालय खर्च के लिए दिए जाते हैं। यानी केवल वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और कार्यालय भत्ता मिलाकर ही सांसदों को हर महीने 2.30 लाख रुपए मिलते हैं। प्रतिदिन दो हजार रुपए ड्यूटी भत्ता अलग है। यह भी तय हो चुका है कि 1 अप्रैल 2023 से सांसदों का वेतन और दैनिक भत्ता हर पांच साल बाद कॉस्ट इंफ्लेशन इंडेक्स (लागत मुद्रास्फीति सूचकांक) के आधार पर बढ़ाया जाएगा।

मप्र के कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जिस तरह सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन को खत्म किया है, उसी तरह माननीयों की पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले अन्य भत्तों को खत्म किया जाए। उनका कहना है कि जिस तरह अधिकारी-कर्मचारी जब तक सेवा में रहते हैं, तभी तक ही उन्हें शासकीय सुविधाओं का लाभ मिलता है उसी तरह सांसद और विधायकों के साथ भी होना चाहिए। सरकार एक तरफ समानता की बात करती है, दूसरी तरफ स्थिति यह है कि माननीयों को बड़े-बड़े अधिकारियों से भी अधिक सुविधाएं मिल रही हैं। कर्मचारी संगठन मुख्यमंत्री मोहन यादव को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने इस दिशा में कदम तो उठाया है।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

इनके लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं

बता दें, सरकार करोड़पति मंत्रियों का तो इनकम टैक्स जमा कर रही है, लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी खुद ही अपना इनकम टैक्स जमा कर रहे हैं। ये कर्मचारी 16 हजार रुपए से लेकर 35 हजार रुपए तक टैक्स जमा कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि शासन के पास मंत्रियों के लिए तो नियम हैं, लेकिन कर्मचारियों के लिए कोई नियम नहीं हैं। कर्मचारियों को खुद ही अपना इनकम टैक्स जमा करना होगा। गौरतलब है कि, राजस्थान, पंजाब, उप्र सहित कई राज्यों में सरकार यह व्यवस्था बंद कर चुकी है। इस जुलाई से असम में सभी मंत्री अपना बिजली बिल भी भरेंगे। देश में झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ राज्यों में सरकार माननीयों का इनकम टैक्स भरती है। जानकारों का कहना है कि देश के राष्ट्रपति खुद आयकर चुकाकर जिम्मेदार नागरिक का दायित्व निभाते हैं तो मंत्री क्यों नहीं? मंत्रियों के सरकारी खजाने से कर चुकाने का प्रावधान पूरे देश में खत्म कर देना चाहिए।

5 साल में निगल लिए 53 लाख छायादार पेड़

कभी खेतों में नीम, महुआ, जामुन जैसे पेड़ों की बहार हुआ करती थी, सावन के झूले पड़ा करते थे। लोग महुआ चुनते, उसके पकवान बनते। घंटों नीम, पीपल की पूजा होती, मान-मनुहार होता। जामुन पकती तो पक्षियों और जानवरों का उन्हें खाने के लिए मेला लग जाता। लेकिन कहीं न कहीं पेड़ों के साथ यह सब भी गायब होता जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले पांच वर्षों में भारत के खेतों से 53 लाख छायादार पेड़ गायब हो चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत में कृषि न केवल किसानों बल्कि आम लोगों के लिए भी बेहद जरूरी है। यह किसानों को उनकी पैदावार से आम आदमी को दो वक्त की रोटी देती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह खेती के तौर तरीकों में बदलाव आ रहा है, वो न केवल पर्यावरण बल्कि किसानों के लिए भी हितकारी नहीं है। ऐसे ही बदलावों में से एक है खेतों से नीम जैसे छायादार पेड़ों का गायब होना। हालांकि यह जानते हुए भी कि ये पेड़ पर्यावरण के साथ-साथ खेतों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हैं, फिर भी इनकी निगरानी पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसका मतलब है कि हम इस बारे में ज्यादा नहीं जानते कि वे कहां हैं, इनका प्रबंधन कैसे किया जाता है, या वे जलवायु परिवर्तन और बीमारियों से कैसे प्रभावित होते हैं।

देश का 56 फीसदी हिस्सा कृषि भूमि के रूप में है, वहीं महज 20 फीसदी पर जंगल है। हालांकि, भारत में जंगल और पौधारोपण के बीच अंतर बेहद स्पष्ट नहीं है। लेकिन इतना जरूर स्पष्ट है कि इस भूमि उपयोग में भारत में मौजूद पेड़ों का एक बड़ा हिस्सा शामिल नहीं हैं, जो खेतों से लेकर शहरी क्षेत्रों में बिखरे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कोपेनहेगन विश्वविद्यालय से जुड़े शोधकर्ताओं के नेतृत्व में एक नया अध्ययन किया गया है, जिसके नतीजे अंतर्राष्ट्रीय जर्नल नेचर सस्टेनेबिलिटी में प्रकाशित हुए हैं। अपने इस अध्ययन में शोधकर्तों ने भारतीय खेतों में मौजूद 60 करोड़ पेड़ों का मानचित्र तैयार किया है। इसके मुताबिक जहां देश में प्रति हेक्टेयर पेड़ों की औसत संख्या 0.6 दर्ज की गई। वहीं इनका सबसे ज्यादा घनत्व उत्तर-पश्चिमी भारत में राजस्थान और दक्षिण-मध्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में दर्ज किया गया, जहां पेड़ों की मौजूदगी प्रति हेक्टेयर 22 तक दर्ज की गई। अध्ययन के दौरान इन पेड़ों की दस वर्षों तक निगरानी की गई। हालांकि इनमें वो पेड़ शामिल नहीं थे जिन्हें पौधारोपण के लिए लगाया गया था।

इस अध्ययन के जो नतीजे सामने आए हैं उनसे पता चला है कि 2010-11 में मैप किए गए करीब 11 फीसदी बड़े छतनार पेड़ 2018 तक गायब हो चुके थे। रिसर्च के मुताबिक ज्यादातर क्षेत्रों में खेतों से गायब हो रहे परिपक्व पेड़ों की संख्या आमतौर पर 5 से 10 फीसदी के बीच रही। हालांकि मध्य भारत में, विशेष तौर पर तेलंगाना और महाराष्ट्र में, बड़े पैमाने पर इन विशाल पेड़ों को नुकसान पहुंचा है। इस दौरान कई हॉटस्पॉट ऐसे भी दर्ज किए गए जहां खेतों में मौजूद आधे (50 फीसदी) पेड़ गायब हो चुके हैं। वहां प्रति वर्ग किलोमीटर औसतन 22 पेड़ गायब होने की जानकारी मिली है। इस बीच कुछ ऐसे छोटे हॉटस्पॉट क्षेत्र भी उभरे हैं, जिनमें पेड़ों का काफी नुकसान हुआ है। इनमें पूर्वी मप्र में इंदौर के आसपास का क्षेत्र शामिल है।

इतना ही नहीं 2018 से 2022 के बीच करीब 53 लाख पेड़ खेतों से अदृश्य थे। मतलब कि इस दौरान हर किलोमीटर क्षेत्र से औसतन 2.7 पेड़ नदारद मिले। वहीं कुछ क्षेत्रों में तो हर किलोमीटर क्षेत्र से 50 तक पेड़ गायब हो चुके हैं। बता दें कि इन पेड़ों का मुकुट करीब 67 वर्ग मीटर या उससे बड़ा था। इनमें नीम, महुआ, जामुन, कटहल, खेजड़ी (शमी), बबूल, शीशम, करोई, नारियल आदि जैसे बहुउद्देशीय पेड़ शामिल हैं, जो कई तरह से फायदेमंद होते हैं। यह पेड़ मिट्टी की उर्वरता को बढ़ावा देने के साथ-साथ छाया प्रदान करके पर्यावरण की मदद करते हैं। साथ ही किसानों को फल, लकड़ी, जलावन, चारा, दवा जैसे उपयोगी उत्पाद भी देते हैं। सूखने के बाद इनकों बेचकर अतिरिक्त आय भी अर्जित की जा सकती है।

अपने अध्ययन में शोधकर्ताओं ने इन विशाल पेड़ों के गायब होने की वजहों की भी पड़ताल की है। इसके मुताबिक इन पेड़ों के गायब होने की सबसे बड़ी वजह खेती-किसानी के तौर तरीकों में आता बदलाव है। देखा जाए तो जैसे-जैसे किसानी के तरीकों में बदलाव आ रहा है खेतों में मौजूद इन पेड़ों को फसलों की पैदावार के लिए हानिकारक माना जा रहा है। रिसर्च के नतीजे दर्शाते हैं कि सिंचाई के साधनों में होते इजाफे के साथ विशेषकर धान के खेतों में जगह बनाने के लिए ज्यादातर पेड़ों को काट दिया गया, क्योंकि किसानों को लगता है कि यह पेड़ उनकी फसलों के लिए खतरा हैं। उनके मुताबिक नीम जैसे पेड़ जिनकी छाया बहुत गहरी होती है, वो फसल की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

अधोसंरचना विकास के नाम पर काट दिए 3 लाख पेड़

राजधानी भोपाल में अधोसंरचना विकास के नाम पर बीते सात वर्षों में तीन लाख से अधिक पेड़ काट दिए गए। जिससे शहर में 30 प्रतिशत से अधिक हरित क्षेत्र कम हो गया है। इधर पेड़ों के कम होने से सड़कों में धूल और जलाशयों में प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। इसका बुरा असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है, लेकिन शहर में विकास के लिए जिम्मेदार एजेंसियों के अधिकारी हरियाली को संरक्षण देने की बजाय इसे बर्बादी की ओर धकेल रहे हैं। पर्यावरणविद् सुभाष सी पांडे ने बताया कि हाल ही में किए एक सर्वे में सामने आया है कि बीते 10 सालों में निर्माण कार्यों को लेकर जिस प्रकार पेड़ काटे गए हैं, उससे भोपाल की हरियाली में 30 फीसदी की कमी आई है। चौकानें वाली बात है कि बीते पांच वर्षों में इसमें 20 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। व्यापक स्तर पर पेड़ों की कटाई वाले नौ स्थानों पर 225 एकड़ हरित क्षेत्र के सफाए के बाद वहां कांक्रीट के जंगल बना दिए गए। इससे गर्मियों के दिनों में शहर में भीषण गर्मी पड़ती है। क्योंकि इसी वजह से यहां औसत तापमान पांच से सात डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। शहर के पर्यावरण को सर्वाधिक नुकसान वर्ष 2014 से 2021 के बीच हुआ है। इसी समय लगभग 80 फीसदी पेड़ काटे गए। जबकि 20 फीसदी पेड़ों की कटाई 2009 से 2013 के बीच हुई है।

बुंदेलखंड जातियों के अपने-अपने कुएं

आजादी के 75 साल बाद भी देश में कई तरह की समाजिक बुराइयां बनी हुई हैं। रुढ़िवादी सोच के लोग आज भी जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं। छुआछूत जैसी समस्या से तथाकथित छोटी और बड़ी जातियों के बीच संघर्ष देखने को मिलता रहता है। मप्र के टीकमगढ़ में भी कुछ इसी तरह की घटना सामने आई है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले में छुआछूत की परंपरा आज भी कायम है। यहां जाति के आधार पर पानी का बंटवारा होता है। टीकमगढ़ जिले के सुजानपुरा गांव में 3 जातियों के लिए अलग-अलग कुएं बनवाए गए हैं। यहां के लोग अपनी जाति के लिए बने कुएं पर ही पानी भर सकते है। यहां सामान्य और पिछड़ी जाति के लिए एक कुआं, दूसरा कुआं अहिरवार समाज के लिए जबकि तीसरा कुआं बंशकार समाज के लोगों का है। यह लोग कभी भी एक-दूसरे के कुएं से पानी नहीं भरते, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए। यहां के लोगों का साफ कहना है कि वह छुआछूत मानते हैं, इसलिए एक-दूसरे के कुएं से पानी नहीं भरते हैं।

टीकमगढ़ जिले के सुजानपुरा गांव में आज भी अंधविश्वास और छुआछूत की परंपरा कायम है। यहां छुआछूत का डास अक्सर निचली जाति के लोगों को भुगतना पड़ता है। चुनाव के समय मंत्री विधायक और सांसद गांव के लोगों से वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन समरसता की बात आज तक किसी ने नहीं की। आजादी के 70 साल बाद भी इस तरह की समाजिक बुराई का होना देश के लिए शर्म की बात है। टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत सुजानपुरा जहां पर संविधान ने भले ही समाज को तीन भागों में बांट दिया हो, जिसमें सवर्ण, पिछड़ा वर्ग और हरिजन है। इसी तरह इस ग्राम पंचायत में पानी पीने के लिए तीन कुएं, बनाए गए हैं। यह व्यवस्था आज से नहीं बल्कि ब्रिटिशकालीन से है जो आज भी जारी है। जिसमें सवर्ण, पिछड़ा वर्ग और हरिजन के लिए इस ग्राम पंचायत में अलग-अलग कुएं खोदे गए हैं और तीनों एक साथ एक ही स्थान पर हैं। किसी की क्या मजाल कि पिछड़े वर्ग का कुआं खाली हो और हरिजन उस पर पानी भरने के लिए चला जाए। यहां तक की हरिजन हरिजन के कुएं से पानी नहीं भर सकता है।

सामाजिक वर्ण व्यवस्था को बीते कई साल गुजर गए और आजादी मिले 75 साल, लेकिन इस ग्राम पंचायत में पानी के लिए जो कुएं बनाए गए हैं, वह वर्ण व्यवस्था पर आज भी आधारित है। एक लाइन में तीन कुएं, जिसमें सामान्य, पिछड़ा वर्ग का एक कुआं और हरिजन के लिए अलग-अलग 2 कुएं हैं। भले ही यहां का तापमान 46 डिग्री हो और तीनों कुओं पर सुबह से पानी के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन दोपहर होते-होते इन कुओं पर पानी लेने वालों की संख्या कम हो जाती है। अगर हरिजन के कुएं पर भीड़ है और सामान्य पिछड़ा का कुआं खाली पड़ा है तो वह कुएं से पानी नहीं भर सकता है। गांव के रहने वाले राजेश वंशकार कहते हैं कि हरिजनों के लिए 2 कुएं खोदे गए थे। वह खंडहर हो चुके हैं, ऐसे में वह लोग अन्य कुएं से पानी नहीं भर सकते हैं। यहां तक कि वंशकार समाज के लोग अहिरवार समाज के कुएं से पानी नहीं भर सकते, इसके लिए उन्हें गांव से 2 किलोमीटर दूर पानी लाना पड़ता है। गांव के ही रहने वाले राजकिशोर कहते हैं कि यह व्यवस्था आज से नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही है। इसको लेकर ना तो किसी समाज या जाति में गिलानी है ना ही कभी भेदभाव होता है। यह व्यवस्था तो हजारों साल पुरानी है। ग्राम पंचायत में सभी समाज जाति के लोग सौहार्द पूर्वक निवास करते हैं। सरपंच प्रतिनिधि रामसेवक यादव कहते हैं कि ग्राम पंचायत में अलग-अलग जातिगत मोहल्लों ने कुएं की व्यवस्था बना ली थी जो आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। आज तक ना तो पंचायत में कोई विवाद हुआ है और ना ही इस तरह की समस्या कभी सामने आई है।

वहीं उप्र के बुंदेलखंड के सूखे इलाकों में कुएं और तालाब सूख गए हैं, नदियां बुरी तरह सिकुड़ गई हैं। उप्र के इस इलाके में पानी की कमी आम बात है। इस साल बारिश की कमी ने इसे और बदतर बना दिया है। जलसंकट के समय में जातिगत समस्याएं उभरने से जलसंकट और भी बढ़ गया है। पानी के टैंकर ऊंची जाति की बस्तियों में भेजे जा रहे हैं, जबकि दलित गांवों को आसानी से दरकिनार किया जा रहा है। दलित जातियों के लोगों को ऊंची जाति के गांवों में लगे चालू हैंडपंपों को छूने तक की अनुमति नहीं है। तेंदुरा गांव की रितु कुमारी का कहना है कि यदि वे (उच्च जाति के लोग) दयालु हैं, तो वे हमें पानी से भरा एक बर्तन दे सकते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। उनके अनुसार, गांव के दलितों को दलित क्षेत्र में लगे हैंडपंप से पानी लाने के लिए सात से आठ किलोमीटर पैदल चलकर दूसरे गांव जाना पड़ता है। उन्होंने कहा, वहां भी हमें एक बाल्टी से अधिक पानी लाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि पंप सूख रहा है। ऊंची जाति के गांवों में कुओं और हैंडपंपों की सुरक्षा लाठीधारी लोग उत्साहपूर्वक कर रहे हैं। मनीष शुक्ला कहते हैं कि यह पानी की चोरी रोकने के लिए है। अज्ञात लोग (यानी दलित) यहां पानी चुराने आते हैं और हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पहले से ही पानी की कमी है।

● **सिद्धार्थ पांडेय**

सामाजिक न्याय मंत्री केंद्र में इसी लोकसभा से

भारत सरकार में सामाजिक न्याय केंद्रीय मंत्री निवर्तमान वीरेंद्र कुमार खटीक टीकमगढ़ लोकसभा से हैं, जिसमें यह ग्राम पंचायत आती है। गांव के रहने वाले जग्गू अहिरवार कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक-दूसरे के कुएं से पानी भर लेता है तो लड़ाई-झगड़े हो जाते हैं और मामला पुलिस तक पहुंच जाता है, इसलिए सभी समाज के लोग अपनी-अपनी मर्यादा में रहते हैं। सामाजिक न्याय केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि अनुराग वर्मा कहते हैं कि अभी इस तरह का मामला उनके सामने नहीं आया है अगर ऐसी व्यवस्था है तो वह इस मामले को संज्ञान में लेंगे। टीकमगढ़ जिला समाज न्याय के संचालक राजेंद्र पस्तोर कहते हैं कि मामला संज्ञान में आया है। निश्चित ही प्रशासन द्वारा वहां पर कैंप करके सामाजिक समरसता के लिए काम किया जाएगा।

नीट फर्जीवाड़े की जांच कर रही सीबीआई नर्सिंग फर्जीवाड़े में फंसी

मप्र के व्यापमं फर्जीवाड़े से भी बड़ा फर्जीवाड़ा है नीट पेपर लीक

मप्र में हुए व्यापमं फर्जीवाड़े के बाद देश में नीट-यूजी और मप्र में नर्सिंग फर्जीवाड़ा सामने आया है। देशभर में जहां नीट फर्जीवाड़े को लेकर हंगामा मचा हुआ है, वहीं मप्र में नर्सिंग फर्जीवाड़े से एक बार फिर लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। हालांकि नीट फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद देशभर में ताबड़तोड़ कार्यवाही हो रही है। वहीं सबसे चिंताजनक बात तो यह है कि जो सीबीआई नीट फर्जीवाड़े की जांच कर रही है, वही एजेंसी मप्र में नर्सिंग फर्जीवाड़े में फंसी हुई है।

● राजेंद्र आगाल

फरवरी 2022 में जब रूस और यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ तो वहां डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हजारों भारतीय छात्रों को बीच में ही पढ़ाई छोड़कर भारत आने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसा पहली हुआ है, लेकिन भारत में पढ़ाई कर रहे छात्रों को तो हर साल सिस्टम की खामी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हालिया मामला नीट-यूजी परीक्षा के पेपर लीक और मप्र में नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के रूप में सामने आया है। किस तरह शिक्षा माफिया, सफेदपोश, अधिकारी आदि मिलकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका नीट और नर्सिंग फर्जीवाड़ा साक्षात प्रमाण है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस जांच एजेंसी सीबीआई को सबसे विश्वसनीय मानकर सरकार बड़ी-बड़ी जांच की जिम्मेदारी सौंपती है, उसी एजेंसी के अधिकारी मप्र में नर्सिंग फर्जीवाड़े के सूत्रधार बन जाते हैं। हालांकि अब केंद्र और मप्र सरकार ने फर्जीवाड़े पर सख्ती दिखाई है।

बीते 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणामों के साथ एक और नतीजा आया। दोनों नतीजे अप्रत्याशित थे। फर्क बस इतना था कि अंडरग्रेजुएट राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) के परिणामों को कायदे से 10 दिन बाद आना था। डॉक्टर बनने का सपना पाले लाखों अभ्यर्थियों की किस्मत का डिब्बा समय से पहले भले खुल गया, लेकिन उसमें से ऐसे चौंकाने वाले आश्चर्य निकलकर आए कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंचने में हफ्ताभर भी नहीं लगा। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण से पहले ही उसके ऊपर परचा लीक से लेकर तमाम किस्म की अनियमितताओं का ग्रहण लग गया।

पूरा देश जब दो महीने तक आम चुनाव में व्यस्त था और तीन चरण का मतदान हो चुका था, यह घोटाला उसी समय बिहार और गुजरात में खुल गया था। दोनों सूबों की पुलिस ने 5 मई को आयोजित हुई परीक्षा के बाद पाई गई अनियमितताओं के संदर्भ में एफआईआर भी दर्ज कर ली थी, गिरफ्तारियां भी हुई थीं। कुछ गिरफ्तारियां दिल्ली, नोएडा आदि जगहों पर छापे मारकर दिल्ली पुलिस ने की थी। फिर सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा परिणामों को रोकने के लिए एक याचिका भी लगाई गई, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि चुनाव संपन्न होने और परिणाम जारी होने के बाद दर्जनभर याचिकाएं फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गईं। अब मामला और संगीन था।

ग्रेस मार्क का खेल

नीट के परिणामों में पहले स्थान पर 67 अभ्यर्थी पाए गए जिन्हें 720 में से 720 अंक मिले थे। कुछ ऐसे परीक्षा केंद्र सामने आए जहां से अकेले छह अभ्यर्थी पहले स्थान पर थे। न सिर्फ इन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक, बल्कि खुद परीक्षार्थी भी सकते में थे कि ऐसा कैसे हो गया। इसके पीछे अनुग्रह अंक (ग्रेस मार्क) का अजीब खेल सामने आया जो एनटीए ने समय की क्षतिपूर्ति करने के लिए 1563 छात्रों को दे दिया था। इसी के कारण नतीजे भी अजीबोगरीब निकले थे। एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले एक शिक्षक के अनुसार, आज तक एनटीए के इतिहास में कभी भी किसी को ग्रेस मार्क नहीं दिए गए हैं। एनटीए कह रहा है कि उसने 2018 के क्लैट मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के आधार पर ग्रेस मार्क देने का निर्णय लिया है, लेकिन वह मामला तो ऑनलाइन परीक्षा से जुड़ा था, जहां किसी बच्चे के साथ क्या तकनीकी खामियां आईं हैं वह तुरंत पता चल जाता है। ऑफलाइन परीक्षा में उस फैसले के आधार पर ग्रेस मार्क क्यों दिए गए यह समझ से परे है।

ग्रेस मार्क ने ऐसा जादू किया है कि कुछ अभ्यर्थियों के अंक 719 और 718 भी आए हैं (पूर्णांक 720 में से) जो कि अंक देने की स्कीम के हिसाब से नामुमकिन था। एनटीए ने इसका ठीकरा भी ग्रेस मार्क पर ही फोड़ दिया। उसने दलील दी कि यह समय की क्षतिपूर्ति के लिए किया गया है। इस तरह सारा मामला एनटीए, पेपर लीक और घोटाले से हटकर केवल ग्रेस मार्क पर केंद्रित हो गया। मामला अलग-अलग याचिकाओं के रास्ते सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जिसमें कई किस्म के आरोप लगाए गए थे। याचिका डालने वालों में पीड़ित छात्रों से लेकर कोचिंग संस्थान तक सब थे और कठघरे में खड़ी थी परीक्षा करने वाली राष्ट्रीय एजेंसी एनटीए, जो शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त इकाई है। दिलचस्प है कि सारा मामला भ्रष्टाचार से हटकर केवल ग्रेस मार्क पर केंद्रित हो जाने के कारण खुद परीक्षा करवाने एजेंसी ही अपने किए कृत्य की उपचारक बन बैठी। एजेंसी ने प्रस्ताव दिया कि जिन 1563 अथ्यर्थियों को ग्रेस मार्क दिए गए हैं उनमें से 23 जून को अधिकांश ने दोबारा परीक्षा दी।

लीक पर राजनीति

नीट पेपर लीक मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस नीट परीक्षा की शीर्ष न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परिणामों पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि केवल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में फोरेंसिक जांच ही लाखों युवा छात्रों के भविष्य की रक्षा कर सकती है। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान और एनटीए के माध्यम से नीट घोटाले को ढंकना शुरू कर दिया है। उन्होंने सवाल खड़ा किया, अगर नीट में पेपर लीक नहीं हुआ था तो बिहार में 13 आरोपियों को क्यों गिरफ्तार किया गया? क्या पटना पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने पेपर के बदले शिक्षा माफिया और रैकेट में शामिल संगठित गिरोहों को 30 लाख से 50 लाख रुपए के भुगतान का पर्दाफाश नहीं किया? क्या सरकार लोगों को मूर्ख बना रही है? इस संदर्भ में सजप का कहना है कि विवादित नीट के परिणाम ही अपने आप में अनियमितताओं का ठोस साक्ष्य प्रदान कर देंगे। शैक्षणिक-सांख्यिकी के सामान्य मानक औजारों से अगर गत वर्षों के परिणामों के साथ इस बार के परिणाम का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए, तो यह सामने आएगा कि परीक्षा से पहले प्रश्न जान जाने वाले परिक्षार्थियों के अंक ग्राफ में चोटी की जगह पठार का निर्माण करेंगे। परीक्षार्थियों की आम मेधा एक साल से दूसरे साल में असाधारण रूप से नहीं बदल सकती, इस सामान्य परिकल्पना के आधार पर सरकार सरल सांख्यिकीय औजारों की मदद से किए गए विश्लेषण द्वारा परीक्षा रद्द करने के नतीजे पर पहुंच सकती है। असल सवाल सरकार की नीयत का है क्योंकि प्रश्नपत्र लीक कराने वाले, सांठगांठ करके उसे कोचिंग माफिया को बेचने वाले आदि के निहित स्वार्थों को परीक्षा रद्द किए जाने से धक्का लगेगा।

एनटीए की भूमिका संदिग्ध

जब मामला बढ़ा और बिहार में पकड़े गए एक शख्स ने अपना कबूलनामा दे दिया और एनटीए ने भी उन 9 छात्रों के साक्ष्य पुलिस को मुहैया करवा दिए जिन्हें पकड़ा गया था। पहली बार शिक्षा मंत्री बने धर्मेंद्र प्रधान को मानना पड़ा कि कम से कम दो अनियमितताएं तो नीट परीक्षा में हुई ही हैं। उन्हें कहना पड़ा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सवाल है कि लाखों छात्रों-युवाओं के जीवन से खिलवाड़ करने वाले दोषी कौन हैं जिन्हें नहीं बख्शने की बात केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं? हरियाणा, गुजरात और बिहार से निकले तथ्य बताते हैं कि अब तक पहचाने और पकड़े गए नीट पेपर लीक के मुख्य आरोपियों में एक खुद एनटीए का जिला संयोजक है (गुजरात), दूसरा भाजपा की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के टिकट पर पिछला विधानसभा चुनाव लड़ चुकी एक महिला नेता का पति है (बिहार), तो तीसरा खुद भाजपा का नेता है (हरियाणा), जिसके बारे में सामने आया है कि

नीट-यूजी घोटाला व्यापमं-2

यह देश का पहला मामला नहीं है जब किसी परीक्षा में धांधली को लेकर सवाल उठे हैं। कुछ मामले पूरे देश को बरसों तक झकझोरते रहे हैं तो अधिकतर मामले ऐसे ही दब गए। मप्र में सामने आने वाला व्यापमं घोटाला भला कौन भूल सकता है, जिसमें न केवल मामले को उजागर करने वालों बल्कि एक टीवी पत्रकार की भी रहस्यमय मौत हो गई थी? इस मामले में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा और करीब एक सौ से अधिक अन्य राजनेताओं पर धांधली के आरोप लगे थे। यह मुद्दा आज भी राजनीतिक गलियारों में गूंजता रहता है। व्यापमं परीक्षा घोटालों के लिए अब मुहावरा बन चुका है। कांग्रेस ने नीट घोटाले को व्यापमं-2 का नाम दिया है। इस बार संयोग यह है कि नीट-यूजी के मौजूदा घोटाले के दो मुख्य स्रोत गुजरात और बिहार हैं। भूलना नहीं चाहिए कि केंद्र की सरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहयोग से टिकी हुई है। स्वयं नीतीश ने घोषणा की है कि प्रश्नपत्र लीक न हो, इसके लिए विधानसभा में उनकी सरकार अगले ही सत्र में सख्त कानून लाएगी। इसके अलावा ओडिशा, झारखंड और कर्नाटक तक के अभ्यर्थियों से पेपर बेचने के लिए पैसे लिए जाने के साक्ष्य गुजरात पुलिस ने बरामद किए हैं। बिहार पुलिस ने तो 5 मई को हुई परीक्षा के बाद ही प्रकरण दर्ज करके एक विशेष जांच टीम बना दी थी। अब तक उसने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। पर्चा लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा संजीव नाम का शख्स कई राज्यों में परीक्षाओं के घोटाले से जुड़ा पाया गया है।

उसने पर्चे भरे बक्से को आरी से काट दिया था। नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में पेपर लीक अगर होता है, तो सवाल है कि खामियां कहां हैं? इस पर एक शिक्षक का कहना है कि पेपर के साथ खिलवाड़ वितरण के स्तर पर हो रहा है। हर केंद्र पर पेपर दो दिन पहले ही आ जाते हैं और अब इन दो दिनों में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता है। ऐसा भी नहीं है कि जो चाहे उसे पेपर पहले ही दिखा दिया जाएगा। इसके लिए भी मोटा पैसा लगता है। जो धांधली करते हैं वे 50 लाख से एक करोड़ रुपए तक वसूलते हैं। एनटीए को कठघरे में खड़ा करते हुए वे कहते हैं कि बड़े स्तर पर कोई जरूर इसमें शामिल है, नहीं तो जो नतीजा 14 जून को आना था वह 4 जून को क्यों आया जब पूरा देश चुनावी नतीजों में व्यस्त था? वे कहते हैं, उन्हें लगा कि ये मामला दब जाएगा। पर्चा लीक का मामला ऐसा है कि ज्यों-ज्यों दवा की त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता गया। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार जब पर्चा लीक विरोधी कानून लेकर आई तो कानून लागू होने के 8 महीनों के भीतर फिर से सरकारी परीक्षा का पर्चा लीक हो गया। बिलकुल इसी तरह केंद्र सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में इसी फरवरी 2024 में पर्चा लीक विरोधी केंद्रीय कानून लोकसभा से पारित किया था। कानून आते ही पर्चे लीक होने शुरू हो गए। बिहार में शिक्षक भर्ती, उप्र में सिपाही भर्ती के बाद अब नीट का कांड ऐसे कानूनों की उपयोगिता पर सवाल खड़े कर रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में सबसे प्रमुख पांच ऐसी सरकारी भर्ती परीक्षाएं रही हैं जिनके पर्चे लीक हुए पहली 2011 में हुई ऑल इंडिया पीएमटी की परीक्षा थी, जिसका पर्चा हरियाणा में लीक हुआ था। उससे पहले 1997 में आईआईटी-जेईई की परीक्षा का पर्चा लखनऊ में लीक हुआ था। यह परीक्षा उस समय सीबीएसई करवाती थी। दोबारा 2021 में यही पर्चा फिर लीक हुआ। 2018 में एसएससी की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षाओं के पर्चे में अनियमितता की बातें सामने आई थीं। हाल का सबसे बड़ा घोटाला 2023 के जून में होने वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में 3055 नर्सिंग ऑफिसर भर्ती से जुड़ा था। इसका पर्चा सोशल मीडिया पर लीक हो गया था। इस सिलसिले में अब तक का सबसे बड़ा परीक्षा घोटाला मप्र का व्यापमं रहा है, जिसमें दर्जनों रहस्यमयी मौतें हुई हैं और इससे जुड़े कई केस अब तक अदालतों में लंबित हैं। सीबीआई ने अपनी जांच 2019 में पूरी कर 31 लोगों को इस घोटाले में दोषी करार दिया था।

साल दर साल पर्चे लीक

भारत में पिछले 7-8 साल में 70 से ज्यादा परीक्षाओं के पर्चे लीक हो चुके हैं। ऐसा तकरीबन हर राज्य में हुआ है। कुल मिलाकर डेढ़ करोड़ के आसपास रोजगार और उच्च शिक्षा का सपना पाले युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है। ये युवा हर तबके, धर्म और आय वर्ग के हैं। अकेले उप्र में हाल ही में यूपीपीएससी रिव्यू ऑफिसर-असिस्टेंट, रिव्यू ऑफिसर (आरओ, एआरओ) की परीक्षा पर्चा लीक के चलते रद्द कर दी गई। इसी तरह उप्र पुलिस की भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक होने पर उसे भी रद्द किया गया। इससे पहले 2017 में सब-इंस्पेक्टर, 2018 में यूपीपीसीएल, 2019 में ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, 2020 में शिक्षक भर्ती परीक्षा, 2021 में बीएड प्रवेश परीक्षा, 2021 में ही यूपीटेट और अनुदानित स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की भर्ती परीक्षा के पर्चे लीक हुए। बीते करीब 10 साल के दौरान राजस्थान में पर्चा लीक की घटनाएं इतनी हुई हैं कि इसे पर्चा लीक की राजधानी तक कहा जाने लगा था। 2015 में एलडीसी, 2018 में सिपाही भर्ती, 2019 में पटवारी भर्ती, 2019 में लाइब्रेरियन परीक्षा, 2020 में जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा, 2021 में सब-इंस्पेक्टर और आरईईटी (रीट) भर्ती परीक्षा के पर्चे लीक हो चुके हैं। इस तरह 2015 से लेकर 2023 के बीच कम से कम 14 पर्चा लीक के मामले राजस्थान में सामने आए हैं। इसके अलावा राजस्थान वनरक्षक भर्ती, महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण भर्ती, गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड भर्ती, उप्र पुलिस कांस्टेबल भर्ती, तेलंगाना लोक सेवा आयोग भर्ती, बिहार कर्मचारी चयन समिति भर्ती जैसे परीक्षाओं में भी धांधली की खबरें आईं हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 15 राज्यों में करीब 41 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। इससे करीब डेढ़ करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं। पेपर लीक का मामला सिर्फ सरकारी परीक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक, प्री-इंजीनियरिंग और प्री-मेडिकल, विश्वविद्यालय प्रवेश और विश्वविद्यालय परीक्षाओं तक फैला हुआ है। इसी तरह गुजरात में भी 2015 के बाद से दर्जनभर से ज्यादा सरकारी परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए। 2015 में जीपीएसएसबी का पर्चा लीक हुआ, फिर 2018 में टेट का पर्चा और उसी साल मुख्य सेविका का पर्चा लीक हुआ। अगले साल 2019 में क्लर्क भर्ती का पर्चा घोटाला सामने आया। 2021 में हेड क्लर्क भर्ती और सब-ऑडिटर भर्ती, 2022 में वन गार्ड भर्ती और 2023 में गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड में कनिष्ठ लिपिक भर्ती के परचे लीक हुए।

पेपर लीक का खतरनाक ट्रेंड

पेपर लीक कराने के लिए ऐसे होती है प्लानिंग

खेल सिर्फ नीट परीक्षा के साथ नहीं हुआ है बल्कि देश में जो भी परीक्षा हो रही है, उसका पेपर लीक जरूर कराया जाता है। देश में पेपर लीक माफियाओं का एक बड़ा नेटवर्क है जो सेंट्रल, स्टेट हर परीक्षा में गड़बड़ी करने पर तुला हुआ है। अगर कोई बड़ी परीक्षा होने वाली होती है तो यह सभी माफिया एकसाथ मिलकर पेपर को लीक करने की प्लानिंग में लग जाते हैं। अगर एनटीए पेपर कराने का टेंडर किसी कंपनी को देती है तो यह लोग सबसे पहले उस कंपनी के बारे में पता लगाते हैं। इसके बाद यह देखा जाता है कि कंपनी यह पेपर कहां से छपवा रही है, इसके लिए प्रिंटिंग प्रेस का पता लगाया जाता है। अब यकीनन प्रिंट होने के बाद पेपर को बैंक तो पहुंचाना है ही। ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पेपर लीक को अंजाम दिया जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि पेपर को बंद बॉक्स में अच्छे से सेवन लेयर में सील पैक करके रखा जाता है। इसके बावजूद माफियाओं के लिए इस बॉक्स को तोड़ना बेहद आसान है, क्योंकि बॉक्स को तोड़ने के लिए एक अलग शख्स आता है। बता दें कि यूपीएसटीएफ की टीम ने बीत दिनों सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में शुभम मंडल को पकड़ा था। स्टिंग ऑपरेशन में पता चला कि नीट पेपर के बॉक्स तुड़वाने के लिए शुभम को उप्र से बिहार बुलाया गया था।

पेपर लीक को लेकर नीट परीक्षा विवादों के घेरे में है। सड़क से लेकर संसद तक इस पर बवाल मचा हुआ है। छात्र से लेकर राजनेता इस मामले को लेकर हल्ला कर रहे हैं और परीक्षा रद्द कर फिर से कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले की अब सीबीआई जांच भी शुरू हो गई है। उधर, ईओयू की जांच में पहली बार पेपर लीक माफिया साइबर अपराधियों का गठजोड़ सामने आया है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया गिरोह के तार साइबर अपराधियों से जुड़े हैं। साइबर अपराधियों ने संजीव मुखिया गिरोह के लोगों को सिम कार्ड और शेल्टर मुहैया कराया था। इसके बाद पेपर लीक माफिया ने फर्जी तरीके से लिए गए सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था। नीट पेपर गड़बड़ी मामले में अब तक दो दर्जन से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं। इनमें से 13 लोगों को बिहार के पटना, झारखंड के देवघर से 5, गुजरात के गोधरा से 5, महाराष्ट्र के लातूर से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है।

भारत में पिछले 7 सालों में 15 राज्यों में 70 से अधिक परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। इनमें भर्ती परीक्षाएं और बोर्ड परीक्षाएं शामिल हैं। पेपर लीक से 1.7 करोड़ अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। हाल ही में हुए नीट-यूजी 2024 पेपर लीक की जांच में जो सबूत मिल रहे हैं, उससे पता लगता है कि भारत में परीक्षाओं पर पेपर लीक माफिया का नियंत्रण किस हद तक मजबूत है। अनियमितता की जानकारी मिलने के बाद यूजीसी-नेट 2024 परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। नीट-यूजी पेपर लीक के बीच यूजीसी-नेट परीक्षा में अनियमितता की बात सामने आने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ईमानदारी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सही तरीके से परीक्षाएं कराना निश्चित रूप से एक चुनौती बन गई है। बड़े राज्य जैसे राजस्थान, उप्र, मप्र, तेलंगाना और गुजरात बड़े पैमाने पर पेपर लीक से प्रभावित हैं। चुनावों में भी पेपर लीक का मुद्दा उठता है, लेकिन चुनाव खत्म होने के साथ ही यह मुद्दा गायब हो जाता है।

राजस्थान पिछले कुछ वर्षों से पेपर लीक के मामलों को लेकर कुख्यात है। राज्य में 2015 और 2023 के बीच विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की 14 घटनाएं सामने आईं। दिसंबर 2022 में सरकारी स्कूल शिक्षकों की भर्ती के लिए सामान्य ज्ञान परीक्षा का पेपर लीक हुआ। इसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। गुजरात में भी पिछले सात वर्षों में 14 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। इनमें जीपीएससी चीफ ऑफिसर परीक्षा, तलाती परीक्षा, टीचर्स एप्टीट्यूड टेस्ट और मुख्य सेविका, नायब चिटनिस जैसी अन्य परीक्षाएं शामिल हैं।

उप्र में 2017 से 2024 के बीच 9 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। इनमें इंस्पेक्टर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट टेस्ट, यूपीटीईटी, बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, नीट-यूजी जैसी परीक्षाएं शामिल हैं। 2024 में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक से 48 लाख से अधिक आवेदक प्रभावित हुए। बंगाल, तमिलनाडु, मप्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार में भी पेपर लीक के ऐसे ही मामले सामने आए हैं। नीट-यूजी और यूजीसी-नेट परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जांच के बीच देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है। पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ ये कानून इसी साल फरवरी में पारित हुआ था। इस कानून में परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले व्यक्तियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। कानून के तहत परीक्षा में नकल करने वाले छात्रों से लेकर पेपर लीक में शामिल अधिकारियों या धांधली में शामिल समूहों के खिलाफ तीन से लेकर 10 वर्ष तक की सजा और एक करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस नए कानून के तहत, परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को कम से कम तीन वर्ष की कैद की सजा हो सकती है। इस सजा को बढ़ाकर 5 वर्ष तक किया जा सकता है, साथ ही 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नकल कराने का दोषी पाए जाने वाले सेवा प्रदाताओं पर एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, परीक्षा संचालन का खर्च भी उनको भरना पड़ेगा। ऐसे सेवा प्रदाता अगले चार वर्ष तक किसी भी परीक्षा का संचालन नहीं कर पाएंगे।

यदि जांच में पता चलता है कि परीक्षा में धांधली या गड़बड़ी, किसी डायरेक्टर, सीनियर मैनेजमेंट या सेवा प्रदाता फर्म के प्रभारी व्यक्ति की मिलीभगत से की गई है तो ऐसे व्यक्तियों को 3 से 10 वर्ष की कैद हो सकती है और एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये कानून उन लोगों को सुरक्षा भी देता है, जो ये साबित कर पाएंगे कि धांधली उनकी जानकारी के बिना हुई है और उन्होंने गड़बड़ी रोकने के लिए पर्याप्त जरूरी सावधानियां बरती थीं।

सिस्टम की खामी...भुगत रहे छात्र

व्यापमं के बाद मप्र में नर्सिंग घोटाला चर्चा का विषय बना हुआ है। यह वह घोटाला है, जिसमें जांच करने वाले अधिकारी ही बिक गए... इस कारण एक लाख से अधिक छात्रों का भविष्य दांव पर है। वैसे तो मामला 2021 से जानकारी में आया था, लेकिन सीबीआई अफसरों की संलिप्तता के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। हालांकि अब पूरे सरकारी सिस्टम की पोल खुल गई है और सरकार गिन-गिन कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन वर्षों से इस सिस्टम की खामी का खामियाजा भुगत रहे छात्रों के अच्छे दिन कब लौटेंगे?

मान्यता की कसौटी पर खरे न उतरने वाले नर्सिंग कॉलेजों को हर स्तर पर अफसरों ने खुली छूट दी। कॉलेजों की जांच के लिए राज्य व स्थानीय स्तर के साथ नर्सिंग काउंसिल के तीन मुख्य चेक प्वाइंट बने हैं। लेकिन तीनों स्तर पर अफसरों का ऐसा गठजोड़ रहा कि सब जानते हुए वे आंखें मूंदें रहे। नतीजा, नर्सिंग कॉलेज घोटाला हो गया। जिम्मेदारों ने हजारों विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ किया। कहने को सरकार ने पारदर्शिता के लिए ऑफलाइन व्यवस्था खत्म कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनाई। फिर स्क्रूटनी और भौतिक सत्यापन के लिए बनी टीम में राज्य से लेकर स्थानीय स्तर तक सदस्य रखे। फिर भी नर्सिंग काउंसिल ने बिना भवन, शिक्षक और अस्पताल के कॉलेजों को मान्यता दी। सवाल है कि आखिर किस स्तर पर चूक हुई। भौतिक सत्यापन करने वाली टीम ने काउंसिल को गलत रिपोर्ट दी या फिर काउंसिल ने सब जानते हुए नियम ताक पर रखकर मान्यता दी। इतना ही नहीं, काउंसिल की मान्यता के बाद डायरेक्ट्रेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन ने कैसे अपनी मुहर लगा दी। इन सवालों के जवाब सीबीआई की जांच से मिल रहे हैं। घोटाले की जांच कर रही सीबीआई टीम भी कॉलेज माफिया से गठजोड़ कर बैठी और अपनी रिपोर्ट में ही अनसूटेबल कॉलेजों को सूटेबल बता दिया।

फर्जी तरीके से मान्यता हासिल करने के लिए ज्यादातर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज किराए की बिल्डिंग में चल रहे थे। दोबारा सीबीआई जांच के डर से कई कॉलेज संचालक बिल्डिंग छोड़कर भाग गए हैं। यही वजह है कि कॉलेज अपने पते पर नहीं मिल रहे हैं। इसको लेकर एनएसयूआई ने अब सीबीआई डायरेक्टर को पत्र लिखा है। इन कॉलेजों के हर दस्तावेज की जांच बारीकी से करने की मांग की है। प्रदेश के 600 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजों की जांच दोबारा होना है। इससे पहले हाईकोर्ट के निर्देश पर 308 नर्सिंग कॉलेजों की जांच हुई थी। इस जांच में सीबीआई की मिलीभगत पकड़ में आई। इसके बाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी नर्सिंग कॉलेजों की दोबारा जांच के निर्देश दिए हैं। इस बार जांच में वीडियोग्राफी भी होगी। उधर, सरकार प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों को गलत तरीके से मान्यता देने वाले हर स्तर के अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। एनएसयूआई ने सीबीआई डायरेक्टर को लिखे पत्र में बताया है कि प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज मान्यता लेने के लिए किराए से लैब तक के उपकरण लाते थे। निरीक्षण के समय इनमें फैकल्टी रखे जाते थे। फैकल्टी कागजों में ही होते थे।

मप्र आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय ने बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, पीबीबीएससी फर्स्ट ईयर और एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी किया है। इसमें पीबीबीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के एग्जाम 6 अगस्त से शुरू होकर 2 सितंबर तक चलेंगे। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के एग्जाम 8 अगस्त से शुरू होकर 27 अगस्त तक चलेंगे। वहीं, एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के एग्जाम 13 अगस्त से शुरू होकर 27 अगस्त तक चलेंगे। इसके अलावा नर्सिंग एग्जाम का कैलेंडर भी जारी किया गया है। इस परीक्षा में करीब 35 से 40 हजार छात्र इस परीक्षा में बैठेंगे, वहीं दूसरी तरफ मप्र आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा यह भी इस टाइम टेबल में साफ नहीं किया गया है कि इस परीक्षा में क्या सूटेबल, अनसूटेबल है और डिफिशिएंसी वाले कॉलेज स्टूडेंट्स का क्या होगा। क्योंकि इस टाइम टेबल में यह कहीं भी नहीं लिखा गया है कि यह किन कॉलेजों के लिए है या सभी कॉलेजों के लिए है। सभी को मिलाकर कुल 500 के करीब कॉलेज इसमें शामिल हैं।

50 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ विभागीय जांच

नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता में हुए फर्जीवाड़े के बाद इनके निरीक्षण में शामिल 50 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। सीबीआई जांच में अपात्र पाए गए 66 कॉलेजों को मान्यता देने की अनुशंसा करने वाले इन अफसरों के निलंबन की तैयारी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में पहली बार एक साथ इतने लोगों की विभागीय जांच होगी। दरअसल, अपात्र कॉलेजों का निरीक्षण करने वाले 111 में से 90 डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को नोटिस जारी किया गया था। इनमें से 50 ही अपना जवाब दे पाए। सूत्रों के अनुसार, इनके जबाव से सरकार संतुष्ट नहीं है।

इसके चलते इनके खिलाफ विभागीय जांच के लिए 3 से 15 दिन में आरोप पत्र जारी करने के लिए सभी मेडिकल कॉलेजों के डीन को पत्र लिखा गया है। हालांकि, आरोप पत्र जारी होने के बाद विभागीय जांच शुरू होती है तो उससे पहले संबंधित व्यक्ति को निलंबित करना जरूरी होता है। ऐसे में जल्द इनके निलंबन की कार्रवाई हो सकती है। अभी ये सभी डॉक्टर्स और नर्स मूल विभाग सहित अन्य जगह प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त तरुण पिथोड़े के अनुसार, निरीक्षण में शामिल ऐसे डॉक्टर्स व नर्सिंग स्टाफ जिन्होंने गोलमोल जवाब दिए हैं या जवाब ही नहीं दिए हैं, उनके खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है।

तपते टापू बनते शहर

पर्यावरण में जहर घोलने से बढ़ी जानलेवा गर्मी

प्रकृति से जुड़ी गर्मी सौ-डेढ़ सौ वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहर बरपा रही है। दिल्ली का पारा 50 डिग्री से तो ज्यादा ही रहा है। यह एक तरह का प्राकृतिक आपातकाल है। हीटवेव या यों कहें कि लू के थपेड़ों ने जनजीवन को मौत के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। लू या हीटवेव या तापघात के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में मौत के समाचार भी आ रहे हैं। तस्वीर का एक पहलू यह है कि अभी तक सही मायने में हमारे देश में हीटवेव को डिजास्टर मैनेजमेंट में पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया है। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि शहरों में हीट आइलैंड बन रहे हैं, जिसके लिए मुख्य रूप से सीमेंट-तारकोल और कृत्रिम वातानुकूलित (एसीवाली) जीवनशैली जिम्मेदार है। कांक्रीट और तारकोल के जंगलों का विस्तार करने को जब तक हम अपनी जरूरत समझते रहेंगे तब तक हरे-भरे जंगलों को कटने से कोई नहीं रोक सकेगा। दुनियाभर में अगले 20 साल के भीतर कूलिंग सिस्टम्स यानी एयरकंडीशन की मांग में कई गुना बढ़ी है। सुविधावादी जीवनशैली एवं तथाकथित आधुनिकता ने पर्यावरण के असंतुलन को बेतहाशा बढ़ाया है। तापमान में भी साल-दर-साल बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जहां तापमान ने नए रिकॉर्ड्स बनाने शुरू कर दिए हैं, वहीं भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बन रहे हैं।

उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। क्योंकि लू के दिनों की संख्या इस बार दोगुनी से ज्यादा हो गई है। आंकड़े बता रहे हैं कि लू की चपेट में आने से अब तक दर्जनों लोगों की जान चली गई है। वैसे तो ऐसा हर साल मई और जून के महीनों में होता आया है, लेकिन अब जलवायु परिवर्तन से स्थिति साल दर साल और गंभीर ही होती जा रही है, जो सार्वजनिक और सामूहिक चिंता की बात है। इस स्थिति से निबटने के लिए सरकार और सामाजिक संगठनों, दोनों को जागृत होना पड़ेगा, अन्यथा जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों तय किए जाने की मांग भी जोर पकड़ेगी, जो जायज होगी।

जानकारों के मुताबिक, देश के कुछेक शहर अब तपते टापू यानी हीट आइलैंड प्रतीत हो रहे हैं। सामान्य शब्दों में हीट आइलैंड का मानक 44 डिग्री और उससे ऊपर का तापमान है। चूंकि यह सामान्य से 4 डिग्री अधिक होता है। इसलिए हीट आइलैंड का शिकार हो रहे शहरों में लू का प्रकोप भी भयावह हो जाता है। इससे शहर की गतिविधियां लगभग ठप पड़ जाती हैं। अमूमन हर साल मई और जून के महीनों में इन शहरों में तापमान 45 से 49 डिग्री तक पहुंच चुका है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो उठता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अंधाधुंध विकास की आंधी में झुलस रहे इन शहरों की मौजूदा स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है और इससे बचने का सही रास्ता क्या है, जिसे सुझाने में सरकार भी लापरवाही बरत रही है!

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के साथ उपयुक्त और अनुपयुक्त भूमि के बिगड़ते संतुलन, शहरों में कांक्रीट के बढ़ते जंगल, वातानुकूलित (एयर कंडीशनर) इमारतें, वाहन और उद्योगों के उगलते धुओं के चलते व्याप्त गर्मी से जगह-जगह पर हीट आइलैंड बन रहे हैं। गांवों की अपेक्षा कांक्रीट वाले शहर इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। वहीं, जिन इलाकों में पेड़-पौधे कम होते हैं और कांक्रीट के भवन, घनी आबादी और एसी ज्यादा होते हैं, वहां पर हीटलैंड बन जाते हैं। वहां पर अन्य जगहों के मुकाबले 2 से 3 डिग्री अधिक तापमान देखने को मिलता है। इससे स्पष्ट है कि हीट आइलैंड बनने के वास्ते किसी भी शहर में जो स्थानीय कारण हैं, उनमें बढ़ते भवनों की संख्या, पौधों का कटना, एसी की संख्या बढ़ना, वाहन बढ़ना, घनी आबादियां आदि शामिल हैं। इनका सीधा असर जलवायु परिवर्तन पर पड़ता है, इसलिए इस नजरिए से भी चिंतन जरूरी है।

चिकित्सक बताते हैं कि हीटवेव का असर हीट आइलैंड पर ज्यादा होता है। इसके चलते हृदय रोगियों के साथ मस्तिष्काघात (ब्रेन स्ट्रोक) के मामले भी बढ़ रहे हैं। वहीं अनिंद्रा से तनाव-बेचैनी के साथ लोगों की दिनचर्या भी स्पष्ट तौर पर प्रभावित हुई है। इससे गंभीर बीमारियां भी बढ़ रही हैं। किसी को त्वचा संबंधी सर्वाधिक बीमारियां हो रही हैं तो कोई घमौरियों से परेशान महसूस कर रहा है। वहीं, काम की गति कम होने से शहर के विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हीटवेव का वनस्पतियों और फसलों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिससे सब्जियों पर महंगाई के बादल मंडराने लगे हैं। वहीं, ऐसे शहरों में लोग बिजली व पानी के संकट के भी शिकार हो रहे हैं। दैनिक मजदूरों के लिए संकट तो आम बात है। वहीं, पशु-पक्षी तक इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए इन सबके लिए एहतियाती उपाय करना राज्य प्रशासन की जिम्मेदारी है।

कुछ शोध रपट बताते हैं कि मकानों में लगाए जा रहे वातानुकूलन संयंत्र (एसी) अंदर तो ठंडक का एहसास करा रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत वातावरण के बढ़ते तापमान से चुकाई जा रही है। वहीं, सेंसर आधारित शोध में कांक्रीट की इमारतों का तापमान मिट्टी की दीवारों की तुलना में पांच से छह डिग्री तक ज्यादा पाया गया है। वहीं, एक अध्ययन बताते हैं कि हीट आइलैंड बन चुके शहरों में कम बारिश हो रही है, जिसके चलते मौसम की उग्रता बढ़ रही है। खास बात यह है कि प्राकृतिक तौर पर ठंडक बनाए रखने की प्रणाली (नेचुरल कूलिंग सिस्टम) की भी ऐसे शहरों में कमी दिख रही है। इससे शहर के भीतर और बाहर के तापमान में बड़ा अंतर आया है। इसलिए सरकार को चाहिए कि ऐसे शहरों के लिए वह विशेष रिहायशी व औद्योगिक नीति बनाए, ताकि पर्यावरण और आधुनिकता में एक समन्वय स्थापित हो सके। जनजीवन की रक्षा के लिए ऐसा करने की नितांत आवश्यकता है। विशेषज्ञों की मानें तो विभिन्न प्रदेशों में हीट आइलैंड चित्रित करने का कोई तंत्र नहीं है, लेकिन लू की स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। जबकि बिहार-झारखंड, उप्र-उत्तराखंड, दिल्ली-हरियाणा-पंजाब, राजस्थान-मप्र के हीट आइलैंड बन चुके कतिपय शहरों में इन्हें चित्रित करने का तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। क्योंकि हीटवेव का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव ऐसे लोगों पर पड़ा है जो सड़क के किनारे रोजगार चलाते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक, दिल्ली में 49 फीसदी स्ट्रीट वेंडरों का कहना है कि लू के चलते उनकी आय में कमी हुई है।

● **डॉ. जय सिंह सेंधव**

दाग अच्छे हैं!

राजनीतिक दलों का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ सत्ता प्राप्त करना रह गया है। इसके लिए बेशक संगीन अपराधों के आरोपियों को ही टिकट देकर क्यों न जिताना पड़े। अपराध के आरोपियों को टिकट देने के लिए राजनीतिक दल जितने जिम्मेदार हैं, उतने ही उन लोकसभा क्षेत्रों के मतदाता भी जिम्मेदार हैं। देश में 18वीं लोकसभा चुनी जा चुकी है, मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और रिकॉर्ड संख्या में मतदाता होने के गर्व करने वाली स्थितियां हैं। वहीं चिंताजनक, विचलित एवं परेशान करने वाली स्थितियां भी हैं।

राजनीतिक दलों में चाहे जितने भी वैचारिक और सैद्धांतिक मतभेद हों किंतु एक मुद्दे पर देश के सभी राजनीतिक दलों में मौन सहमति है। यह चुप्पी है आपराधिक पृष्ठभूमि के सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों के चुने जाने को लेकर। लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भी राजनीतिक दल ने लोकतंत्र की पवित्रता को बचाए रखने के लिए आपराधिक रिकार्ड वाले प्रत्याशियों को दरकिनार करना तो दूर बल्कि सत्ता का समीकरण बिठाने के लिए बढ़-चढ़कर टिकट दिए। सत्ता का स्वार्थ इस कदर हावी है कि इस मुद्दे पर कोई चर्चा तक नहीं करना चाहता। यही वजह रही कि लोकसभा के चुनाव में अपराध और राजनीति चुनावी मुद्दा नहीं बन सका। राजनीतिक मंचों से दलों ने एक-दूसरे पर कई तरह के आरोप लगाए, किंतु आपराधिक आरोपों के नेताओं को टिकट देने के मामले में सब के सब मौन रहे। 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल 543 सीटों में से 251 नवनिर्वाचित सांसद ऐसे हैं, जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। हत्या, बलात्कार, लूट और डकैती जैसे अपराध के गंभीर आरोपों से नेताओं का दामन दागदार है। ऐसे में देश में अपराध और भय से मुक्ति दिलाने की सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है।

दागी उम्मीदवार सभी पार्टियों को प्रिय

सभी राजनीतिक दलों ने ही दागी उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। जो राजनीतिक दलों की कथनी और करनी के भारी अंतर को ही उजागर करता है। सवाल है कि देश के लिए नीति निर्धारण करने वाले ऐसे दागी लोग हमारे भाग्यविधाता बने रहेंगे तो हमारा भविष्य कैसा होगा? क्या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद हमारी कानून-व्यवस्था को प्रभावित नहीं करेंगे? क्या होगा हमारे समाज व व्यवस्था का भविष्य? क्यों तमाम आदर्शों की बात करने वाले और दूसरे दलों के नेताओं की कारगुजारियों पर सवाल उठाने वाले नेता राजनीति को अपराधियों के वर्चस्व से मुक्त कराने की ईमानदार पहल नहीं करते? क्यों सभी राजनीतिक दल भारतीय लोकतंत्र में शुचिता एवं पवित्रता के लिए सहमति नहीं बनाते? निश्चित रूप से यदि समय रहते इस दिशा में कोई गंभीर पहल नहीं होती तो आने वाले वर्षों में दागियों का यह प्रतिशत लगातार बढ़ता ही जाएगा। इसके साथ ही बड़ा संकट यह भी है कि देश के निचले सदन में येन-केन-प्रकारेण करोड़पति बने नेताओं का वर्चस्व बढ़ता ही जा रहा है। इस बार संसद में चुनकर आए सांसदों में 504 करोड़पति हैं। ऐसे में क्या उम्मीद की जाए कि अपनी मेहनत की कमाई से जीवनयापन करने वाला आम आदमी कभी सांसद बनने की बात सोच सकता है? दागी एवं अपराधी राजनेता लोकतंत्र की एक बड़ी विडंबना एवं विसंगति बनते जा रहे हैं। बात लोकसभा की ही नहीं है, विभिन्न राज्यों की सरकारों में भी कैसा विरोधाभास एवं विसंगति है कि एक आपराधिक छवि वाला नेता कानून मंत्री बन जाता है, एक अनपढ़ या कम पढ़े-लिखे प्रतिनिधि को शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है।

आपराधिक आरोपों के विजयी उम्मीदवारों में भाजपा सबसे आगे है। भाजपा के 240 विजयी उम्मीदवारों में से 63 सांसदों पर हर तरह मामले विचाराधीन हैं। कांग्रेस के 99 विजयी उम्मीदवारों में से 32 सांसदों, सपा के 37 विजयी उम्मीदवारों में से 17 सांसदों और तृणमूल कांग्रेस के 29 विजयी उम्मीदवारों में से 7 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। लोकसभा चुनाव में 170 विजयी उम्मीदवारों ने बलात्कार, हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध आदि से संबंधित मामलों सहित गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। अपराधी छवि के जीतने वाले उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में 539 सांसदों में से 233 सांसदों ने अपने विरूद्ध आपराधिक मामले घोषित किए थे। इनमें से 159 सांसदों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

पिछली लोकसभा में जहां कुल सदस्यों के 43 फीसदी अर्थात् 233 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे थे, तो अब नई 18वीं लोकसभा में 46 फीसदी के साथ ये संख्या 251 हो गई है। इसमें तीन फीसदी का इजाफा हो गया है, लेकिन 2009 से मुकाबला करें तो 15 साल में इसमें 55 फीसदी का इजाफा

हुआ है। इस लोकसभा में 170 गंभीर आरोपियों में 27 सांसद सजायाफ्ता हैं, वहीं 4 पर हत्या के मामले हैं। 15 सांसदों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के इल्जाम हैं, जिनमें से 2 पर रेप का आरोप है। अपराधी पृष्ठभूमि वाले 43 सांसद हेट स्पीच के आरोपी हैं।

वोट बैंक की राजनीति इस हद तक नीचे गिर गई है कि आपराधिक कृत्यों के आरोपों में न तो प्रत्याशी में कोई शर्म बाकी रह गई और न ही राजनीतिक दलों में। दूसरे शब्दों में कहें तो राजनीतिक दलों में सत्ता की प्रतिस्पर्धा से अपराधी छवि वाले प्रत्याशी जीतकर देश और राज्यों को चलाने के लिए संसद और विधानसभाओं तक पहुंच रहे हैं। लोकतंत्र में शुचिता और पारदर्शिता की मिसाल पेश करने के बजाय नेता और राजनीतिक दल उल्टी गंगा बहा रहे हैं। सार्वजनिक तौर बिना झिझक माफियाओं से गलबहियां डालना और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर नेताओं के संवेदना दिखाकर वोट बटोरने का प्रयास करने का सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया की जागरूकता के इस दौर में यह प्रवृत्ति कांग्रेस और भाजपा में कम नजर आती है, किंतु अन्य दलों में जरा भी लोकलाज नहीं बची है।

उप्र में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ऐसे दुर्दांत अपराधियों के खात्मे के बजाय उल्टे आरोप लगाए। यादव ने ट्वीट किया था कि उप्र में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है और अपराधियों के हौंसले बुलंद हैं। सपा सांसद रहे दिवंगत डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क ने इस माफिया के अपराधी भाई अतीक अशरफ के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने पर ट्वीट कर कहा था कि देश में कोर्ट-कचहरी और थानों में ताले लग जाने चाहिए। कानून-व्यवस्था को मिट्टी में मिला दिया। उप्र के ही माफिया मुख्तार अंसारी की बीमारी से हुई मौत को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश ने मुस्लिमों की संवेदनाएं बटोरने और उन्हें उकसाने में कसर नहीं छोड़ी। अंसारी के परिवार की मिजाजपुर्सी के लिए पहुंचे अखिलेश ने कहा था परिवार का दुख बांटने आया हूं, जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए। यादव ने अंसारी के आपराधिक कृत्यों पर पर्दा डालते हुए कहा था कि जो व्यक्ति इतने वर्षों जेल में रहा हो और उसके बाद भी जनता जिता रही हो तो इसका मतलब परिवार और उस व्यक्ति ने जनता का दुख-दर्द बांटा है। अंसारी के खिलाफ 60 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। बाहुबली अतीक अहमद और शहाबुद्दीन का नाम लेकर वोट की अपील करने पर मुकदमा दर्ज होने से बौखलाए उप्र की संभल सीट पर सपा की टिकट पर सांसद चुने गए जियाउर्रहमान बर्क ने मंच से चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को धमकी भरे तेवर दिखाए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग आचार संहिता का उल्लंघन करें तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन हम दायरे में रहकर भी सही बात करें तो मुकदमा दर्ज कर देते हैं। जियाउर्रहमान ने मंच से ही चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से धमकी भरे अंदाज में कहा था कि याद रखना हमेशा एक जैसे दिन नहीं रहते हैं क्योंकि कभी दिन बड़ा होता है तो कभी रात बड़ी होती है, लेकिन जिस दिन वक्त बदलेगा तो हम इन चीजों को भूलने वाले नहीं हैं। उप्र की तरह बिहार में भी आपराधिक रिकार्डधारी आरोपियों और उनके परिवार के सदस्यों को गले लगाने के लिए राजनीतिक दल आतुर रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में बिहार में पांच बाहुबलियों ने अपनी पत्नियों को मैदान में उतारा था, इनमें तीन को हार का सामना करना पड़ा। जबकि दो को जीत मिली। हत्या के मामले में दोषी और डॉन आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने जेडीयू के टिकट पर शिवहर से चुनाव जीता है। सिवान से जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीतने वालीं विजयलक्ष्मी देवी बाहुबली नेता रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी हैं। रमेश का ताल्लुक माओवादी संगठन से संबद्ध सीपीआई एमएल से रहा है और वे शिवजी दुबे हत्याकांड में जेल भी जा चुके हैं।

राजनीतिक दलों का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ सत्ता प्राप्त करना रह गया है। इसके लिए बेशक संगीन अपराधों के आरोपियों को ही टिकट देकर क्यों न जिताना पड़े। अपराध के आरोपियों को टिकट देने के लिए राजनीतिक दल जितने जिम्मेदार हैं, उतने ही उन लोकसभा क्षेत्रों के मतदाता भी जिम्मेदार हैं। मतदाता जात-पात, धर्म, ऊंच-नीच और प्रचार के दौरान किसी न किसी रूप में फायदा मिलने के लालच में ऐसे प्रत्याशियों को जिताने में पीछे नहीं रहते हैं। हालांकि विगत में होने वाले चुनावों में बाहुबली और माफियाओं के चुनाव जीतने की कहानी अब भले ही इतिहास हो चुकी है पर पूरी तरह से सफाई नहीं हुई है। माफियाओं के लिए बदनाम रहे उप्र और बिहार में काफी हद तक इनका खात्मा हो चुका है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में आपराधिक पृष्ठभूमि के नेताओं का चुनाव जीतना इस बात का द्योतक है कि देश में विशुद्ध तौर पर लोकतंत्र आने में अभी दशकों का वक्त लगेगा।

● **विपिन कंधारी**

चरित्र एवं नैतिकता का महत्व नहीं

राजनीति में चरित्र एवं नैतिकता के दीये की रोशनी मंद पड़ गई है, तेल डालना होगा। दिल्ली सरकार में मंत्रियों के घरों पर सीबीआई के छापे और जेल की सलाखें हो या बिहार मंत्री परिषद के गठन में अपराधी तत्वों की ताजपोशी, ये गंभीर मसले हैं, जिन पर राजनीति में गहन बहस हो, राजनीति के शुद्धिकरण का सार्थक प्रयास हो, यह नया भारत-सशक्त भारत की प्राथमिकताएं होनी ही चाहिए। सभी अपनी-अपनी पहचान एवं स्वार्थपूर्ति के लिए दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कोई पैसे से, कोई अपनी सुंदरता से, कोई विद्वता से, कोई व्यवहार से अपनी स्वतंत्र पहचान के लिए प्रयास करते हैं। राजनीति की दशा इससे भी बदतर है कि यहां जनता के दिलों पर राज करने के लिए नेता अपराध, भ्रष्टाचार एवं चरित्रहीनता का सहारा लेते हैं। जातिवाद, प्रांतवाद, साम्प्रदायिकता को आधार बनाकर जनता को तोड़ने की कोशिशें होती हैं। पर हम कितना भ्रम पालते हैं। पहचान चरित्र के बिना नहीं बनती। बाकी सब अस्थायी है। चरित्र एक साधना है, तपस्या है। जिस प्रकार अहं का पेट बड़ा होता है, उसे रोज कुछ न कुछ चाहिए। उसी प्रकार राजनीतिक चरित्र को रोज संरक्षण चाहिए और यह सब दृढ़ मनोबल, साफ छवि, ईमानदारी एवं अपराध-मुक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। राजनीति में चरित्र-नैतिकता संपन्न नेता ही रेस्पेक्टेबल (सम्माननीय) हो और वही एक्सेप्टेबल (स्वीकार्य) हो।

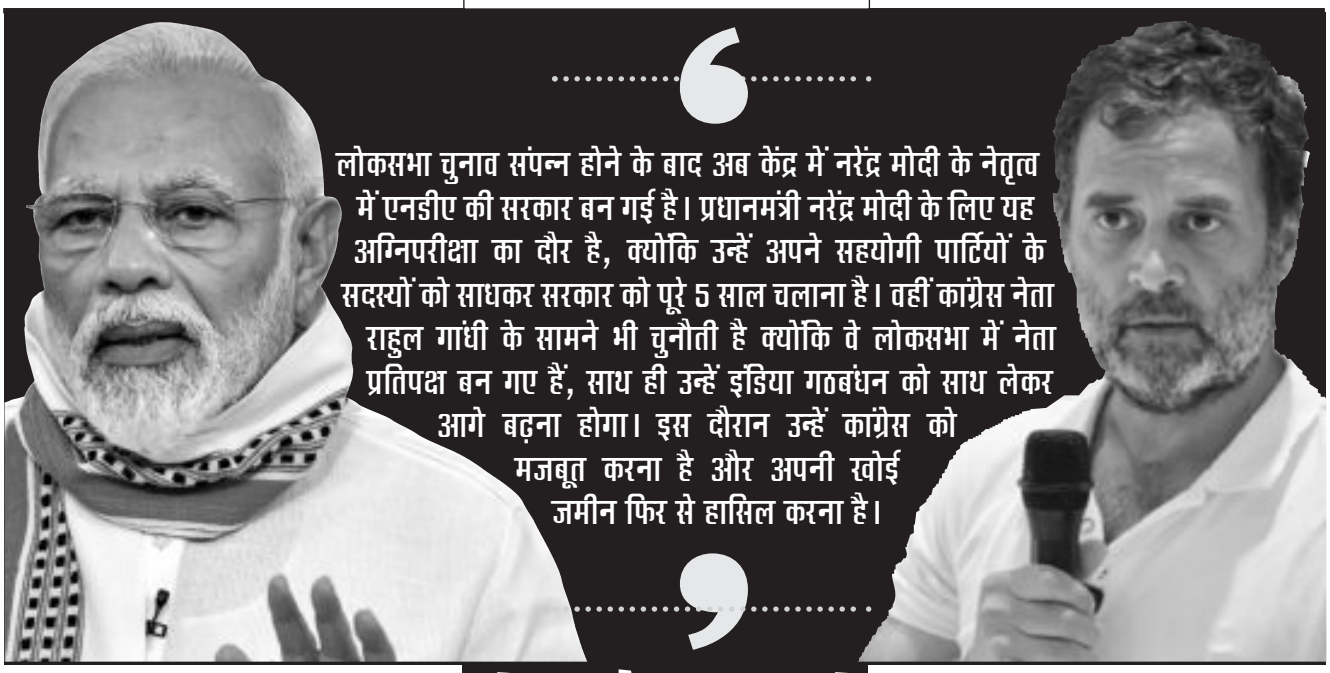

> लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह अग्निपरीक्षा का दौर है, क्योंकि उन्हें अपने सहयोगी पार्टियों के सदस्यों को साधकर सरकार को पूरे 5 साल चलाना है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामने भी चुनौती है क्योंकि वे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, साथ ही उन्हें इंडिया गठबंधन को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। इस दौरान उन्हें कांग्रेस को मजबूत करना है और अपनी खोई जमीन फिर से हासिल करना है।

मोदी और राहुल को देनी होगी अग्निपरीक्षा

लोकसभा चुनावों में चाहते न चाहते, जाने अनजाने आखिरकार मुकाबला मोदी बनाम राहुल हो गया और अब आगे की राजनीति भी मोदी बनाम राहुल ही होगी। क्योंकि जिस तरह का जनादेश जनता ने दिया है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दोनों को ही लोकतंत्र की अग्निपरीक्षा देनी होगी। जहां प्रधानमंत्री मोदी को अब गठबंधन सरकार को सफलतापूर्वक चलाने की चुनौती है तो राहुल गाधी के सामने विपक्षी इंडिया गठबंधन को एकजुट बनाए रखते हुए सरकार को घेरने की अहम जिम्मेदारी है। ये दोनों अग्निपरीक्षाएं भारतीय राजनीति के इन दोनों शीर्ष नेताओं को अलग-अलग देनी हैं। लेकिन जिस तरह 18वीं लोकसभा चुनकर आई है उसमें देश की राजनीति में दो नेताओं की भूमिका बेहद अहम हो गई है। सत्तापक्ष में राजनाथ सिंह सरकार के संकट प्रबंधक बनकर उभरे हैं तो विपक्ष में मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका एक अभिभावक नेता की बनती जा रही है। जहां मोदी और राहुल एक-दूसरे पर पहले की तरह आक्रामक रहेंगे, वहीं इन दोनों नेताओं पर पक्ष-विपक्ष के बीच भड़कने वाली सियासी आग पर पानी डालने और अपने-अपने खेमों को एकजुट बनाए रखने की जिम्मेदारी होगी। 18वीं लोकसभा की पहली परीक्षा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष बनवाकर बाजी मार ली है।

केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाकर नरेंद्र मोदी ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर ली है। लेकिन फर्क ये है कि नेहरू ने तीसरी बार भी अपनी पार्टी कांग्रेस के लिए प्रचंड बहुमत जुटाया था और उनके सामने विपक्ष इतना मजबूत नहीं था जितना अब है। लेकिन मोदी की सरकार में उनके दल भाजपा को अकेले बहुमत नहीं है और सरकार बनाने और चलाने के लिए भाजपा की चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, पवन कल्याण, जीतनराम मांझी, एकनाथ शिंदे, अजित पवार के दलों वाले एनडीए पर निर्भरता है। मोदी राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं और पहले करीब 13 साल गुजरात और फिर पिछले दस साल केंद्र में सफल सरकार चलाने का उन्हें अनुभव है। लेकिन गुजरात से लेकर केंद्र तक मोदी ने अभी तक अपने दल के पूर्ण बहुमत वाली सरकारें अपनी हनक और धमक से चलाई हैं। उन्हें गठबंधन सरकार चलाने का तजुर्बा नहीं है। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए की गठबंधन सरकार के वक्त वह पहले दिल्ली में भाजपा के महासचिव और फिर गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए उनके रिश्ते भाजपा के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार तब भी वाजपेयी सरकार के हिस्से थे। इसलिए उनके साथ संवाद और संपर्क में मोदी को कोई समस्या नहीं है।

हालांकि, अभी तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की कार्यशैली एक मजबूत और धमक वाले ऐसे नेता की रही है जिसके सामने पार्टी और सरकार में बाकी सारे नेता बौने हो जाते हैं। जबकि अटल बिहारी

संघ के प्रति कम होता मोदी का समर्पण भाव

संभवतः यह पहला चुनाव था, जिसमें भाजपा आलाकमान ने प्रत्याशियों के चयन से लेकर चुनावी रणनीति तैयार करने तक में कहीं भी संघ से विचार-विमर्श करना उचित नहीं समझा। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी भाजपा लीडरशिप से मिलने के लिए अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की। लोकसभा चुनाव में भाजपा की उप्र में जो फजीहत हुई है, उसका ठीकरा एक-दूसरे के सिर फोड़ने की राजनीति के चलते राज्य में भाजपा नेताओं के बीच आपसी वैमस्यता और गुटबाजी बढ़ती जा रही है। गुटबाजी का आलम यह है कि यह किसी एक स्तर पर नहीं, नीचे से लेकर ऊपर तक तो दिखाई पड़ ही रही है, इसके अलावा इसकी तपिश से दिल्ली भी नहीं बच पाया है। बल्कि राजनीति के कई जानकार और पार्टी से जमीनी स्तर से जुड़े नेता और कार्यकर्ता भी इस बात से आहत हैं कि अबकी बार टिकट वितरण में खूब मनमानी की गई, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। बात यहीं तक सीमित नहीं है, सूत्र बताते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी टिकट बंटवारे के तौर-तरीकों से आहत दिखाई दे रहा है। बस फर्क यह है कि यह लोग सार्वजनिक रूप से ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं जिससे विपक्ष को हमलावर होने का मौका मिल जाए। लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें जीतने का दावा करने वाली भाजपा आधी सीटें भी नहीं जीत पाई। भाजपा की करारी हार के पीछे भले ही कई कारण गिनाए जा रहे हों, पर संघ से दूरी भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है।

वाजपेयी की कार्यशैली में समावेशिता का पुट ज्यादा था और वह सत्ता के विकेंद्रीकरण और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण में भरोसा रखते थे। इसके विपरीत मोदी सरकार सत्ता के केंद्रीयकरण और मोदी द्वारा सबकुछ अपने ऊपर ले लेने के लिए जानी जाती रही हैं। इसीलिए नोटबंदी, लॉकडाउन, सीएए, अनुच्छेद 370, जीएसटी जैसे फैसले तमाम अवरोधों के बावजूद सरकार ले सकी। नोटबंदी और लॉकडाउन जैसे फैसले जिस तरह अचानक घोषित किए गए वो किसी गठबंधन सरकार में मुमकिन नहीं हैं। ऐसे किसी भी फैसले के लिए जिसमें किसी भी तरह के विवाद की संभावना हो उसे लेने से पहले सहयोगी दलों से परामर्श करना और उनकी सलाह के मुताबिक उसमें फेरबदल करने के लिए तैयार रहना गठबंधन सरकार की कामयाबी की पहली शर्त होती है। सरकार बिना किसी अवरोध के चले इसके लिए भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सहयोगी दलों खासकर तेलुगू देशम और जनता दल (यू) की भावनाओं और संवेदनाओं का ध्यान रखना होगा।

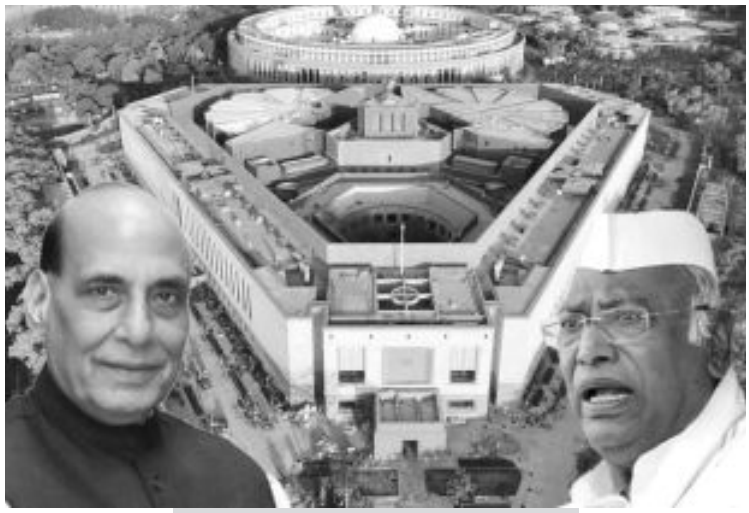

इसके लिए जरूरी है कि सहयोगी दलों के साथ निरंतर संवाद बना रहे और या तो टकराव की स्थिति पैदा न होने दी जाए या फिर ऐसी स्थिति होने पर कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके। इसके लिए भाजपा में राजनाथ सिंह से बेहतर कोई दूसरा नेता नहीं है। वरिष्ठता अनुभव और परिपक्वता से भरपूर राजनाथ सिंह राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी के समावेशी राजनीतिक स्कूल से आते हैं। उनका राजनीतिक विकास वाजपेयी, आडवाणी और जोशी के अनुयायी बनकर हुआ है। उनकी मृदुभाषिता और मैत्रीपूर्ण व्यवहार की प्रशंसा विपक्षी दल भी करते हैं। इसीलिए सरकार बनने के बाद सहयोगी दलों के साथ-साथ विपक्षी नेताओं को भी साधे रखने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ टिकी है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव बिना किसी अवरोध के निर्विरोध हो जाए इसके लिए राजनाथ सिंह ने सभी दलों से संवाद किया था, किंतु कांग्रेस ने के सुरेश को प्रत्याशी बनाया था। लेकिन ओम बिरला को अध्यक्ष चुन लिया गया।

गठबंधन सरकार की दूसरी बड़ी चुनौती है सहयोगी दलों का दबाव। यह दबाव सरकार गठन के समय से ही शुरू हो जाता है। भले ही प्रकट तौर पर कहा जाए कि सहयोगी दलों ने बिना शर्त समर्थन दिया है लेकिन परदे के पीछे की सच्चाई है कि सारी बातें तय होने के बाद ही सहयोगी दल समर्थन देते हैं। किस दल को कितने मंत्री पद मिलेंगे, स्पीकर किसका होगा, विभाग कौन से मिलेंगे, यह सब कुछ प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण से पहले काफी हद तक तय हो चुका होता है। जाहिर है कि इस बार भी सत्ता की साझेदारी से जुड़े इन मुद्दों पर कुछ सहमति बन चुकी थी, इसलिए मंत्री पद के बंटवारे में कोई झंझट नहीं हुआ। सहयोगी दलों की प्राथमिकता उनके राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत करने की होती है और इसके लिए वो केंद्र सरकार से अपने राज्यों के लिए ज्यादा से ज्यादा संसाधन, रियायतें और विकास परियोजनाओं की मांग करके अपना दबाव बनाते रहते हैं। इस मामले में चंद्रबाबू नायडू को काफी दिग्गज माना जाता है और वाजपेयी सरकार से अपने समर्थन की राजनीतिक कीमत वसूलते रहने के लिए की जाने वाली सियासी सौदेबाजी के किस्से राजनीति और मीडिया के गलियारों में आजतक चर्चित हैं। चर्चा है कि चंद्रबाबू ने आंध्र प्रदेश के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग रख दी है। जबकि नीतीश कुमार ने हमेशा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को अपना सियासी मुद्दा बनाया, लेकिन अभी तक उसे हासिल नहीं कर पाए हैं। क्या इस बार वह केंद्र पर इसका दबाव बनाएंगे और मोदी इससे कैसे निपटेंगे, क्योंकि बिहार को यह दर्जा देते ही देश के अनेक और राज्य इस मांग को लेकर केंद्र के दरवाजे पर दस्तक देंगे। इनमें नया-नया भाजपा शासित उड़ीसा भी शामिल होगा।

हमेशा गैर भाजपा दलों जिनमें तेलुगू देशम और जदयू भी शामिल हैं पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाने वाली भाजपा के सामने इन दोनों दलों की मुस्लिम राजनीति से तालमेल बिठाना भी एक चुनौती होगी। जिस मुस्लिम आरक्षण के विरोध को लोकसभा चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर भाजपा अपने पक्ष में हिंदू ध्रुवीकरण करने की कोशिश में थी, तेलुगू देशम ने उसे आंध्रप्रदेश में लागू करने का चुनावी वादा कर रखा है। तेलुगू देशम के घोषणा पत्र में मुसलमानों को अलग से चार फीसदी आरक्षण देने और कई तरह के लाभ मुस्लिमों को दिए जाने की घोषणाओं पर जब चंद्रबाबू नायडू की सरकार अमल करेगी तब भाजपा की प्रतिक्रिया क्या होगी यह देखना भी दिलचस्प होगा। क्योंकि चंद्रबाबू के पुत्र और तेलुगू देशम में नंबर दो की हैसियत रखने वाले नारा लोकेश ने इस बात को दोहराया है कि तेलुगू देशम सरकार आंध्रप्रदेश में अपने सारे चुनावी वादों को पूरा करेगी और अपने घोषणापत्र को अमल में लाएगी। भाजपा इस सरकार में शामिल है और जब आंध्र सरकार अपने मुस्लिम एजेंडे को लागू करेगी तब भाजपा उस सरकार में क्या शामिल रह पाएगी। और अगर भाजपा राज्य सरकार से बाहर आती है तो केंद्र में भाजपा और तेलुगू देशम के संबंधों पर इसका क्या असर पड़ेगा।

● इन्द्र कुमार

आक्रामकता बनी है राहुल की पहचान

कांग्रेस में भले ही दो यात्राओं और लोकसभा चुनावों ने राहुल गांधी को सर्वमान्य सर्वोच्च नेता बना दिया हो लेकिन सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आक्रामकता उनकी पहचान बन चुकी है, जिसके जारी रहने की पूरी संभावना है। अब राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष बन गए हैं, तो सरकार के साथ विपक्ष का टकराव और बढ़ेगा इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो भले ही राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, की जिम्मेदारी और भूमिका निसंदेह बढ़ जाएगी। बुजुर्ग खड़गे उम्र और अनुभव के साथ साथ मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता रह चुके हैं और उनके प्रधानमंत्री मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह समेत भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से संवाद और सहयोग के रिश्ते रहे हैं। अब कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने जिस तरह पार्टी और विपक्षी इंडिया गठबंधन की अगुवाई की है उससे राजनीति में उनका कद काफी बढ़ा है। विपक्ष के लगभग सभी नेता खड़गे का सम्मान करते हैं और अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की संभावना होती तो बहुत मुमकिन था कि खड़गे को ही प्रधानमंत्री पद के लिए आगे किया जाता।

कांग्रेस में होगी बड़ी सर्जरी...

जल्द ही पार्टी करेगी बड़े बदलाव

विधानसभा चुनाव 2023 में पार्टी को करारी हार मिलने के बाद से ही ये बदलाव हो जाने थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते बदलाव नहीं हो पाया। लेकिन अब जल्द ही पार्टी बड़े बदलाव करेगी। नई नियुक्तियों के लिए नेताओं के लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव के परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। छ महीने पहले दीपक बैज ने कहा था कि लोकसभा चुनाव में नई ऊर्जा और नई टीम के साथ जाएंगे। अब चुनाव के बाद देखना होगा कि पार्टी की नई टीम कैसी होगी? ऐसी चर्चा है कि रायपुर शहर-ग्रामीण, कवर्धा, दुर्ग, महासमुंद, बलौदाबाजार, कोरिया, बलरामपुर, रामानुजगंज, सरगुजा, कोरबा, बैकुंठपुर, राजनांदगांव ग्रामीण, सक्ती, बिलासपुर सहित कई जिलों के अध्यक्ष बदल सकते हैं। कांग्रेस को इन सभी जिलों में हार का सामना करना पड़ा है। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से पार्टी इस बात की समीक्षा कर रही है। जिला अध्यक्षों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

पहले विधानसभा और अब लोकसभा चुनाव में पराजय का दंश झेल रहे कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट है। प्रदेश संगठन से लेकर जिला अध्यक्षों के साथ आनुषांगिक संगठनों में भी बड़ा बदलाव किया जा सकता है। इसमें जिले के तीनों जिला अध्यक्ष भी शामिल बताए जा रहे हैं। प्रदेश संगठन से जुड़े बड़े नेता की माने तो पार्टी आलाकमान मैदानी स्तर पर बड़ी सर्जरी कर संगठन को कांग्रेस सत्ता से पहले जैसी मजबूत स्थिति में लाने पर जोर दे रही हैं। इसमें सक्रिय युवा नेताओं को मौका देने पर जोर दिया जा रहा है।

कांग्रेस संगठन में दुर्ग शहर के जिला अध्यक्ष का दायित्व पूर्व महापौर गया पटेल, दुर्ग ग्रामीण का दायित्व भिलाई-3 के महापौर निर्मल कोसरे और भिलाई जिला अध्यक्ष का पद मुकेश चंद्राकर संभाल रहे हैं। विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनाव में तीनों ही जिला अध्यक्षों का परफार्मेंस अच्छा नहीं रहा। शहर जिला अध्यक्ष गया पटेल की नियुक्ति ज्यादा सक्रिय व क्षमतावान कई नेताओं को दरकिनार कर पूर्व शहर विधायक अरुण वोरा की अनुशंसा पर की गई थी। विधानसभा चुनाव से पहले ही शहर अध्यक्ष पटेल की सक्रियता को लेकर विवाद हुआ था। इधर चुनाव में शहर में कांग्रेस को तगड़ी पराजय का सामना करना पड़ा। यही हाल ग्रामीण जिला अध्यक्ष कोसरे से संबद्ध विधानसभाओं का रहा। ग्रामीण जिला अध्यक्ष निर्मल कोसरे खुद विधानसभा के चुनाव मैदान में थे और पराजित हो गए। ग्रामीण संगठन जिले के 5 में से 3 विधानसभा में कांग्रेस को जबरदस्त पराजय का सामना करना पड़ा। भिलाई अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर भी विधानसभा में वैशाली नगर में खुद बड़े अंतर से पराजित हो गए थे।

विधानसभा चुनाव में पराजय के कारण लोकसभा से पहले ही जिला अध्यक्षों को बदले जाने की खबर आई थी। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को हटाया भी गया, लेकिन जिला अध्यक्ष बच गए। तब माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन में सुधार का प्रयास किया जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में पराजय का गड्ढा और बड़ा हो गया। इसके बाद से अब तीनों जिला अध्यक्षों को बदले जाने की मांग उठने लगी है। प्रदेश संगठन से जुड़े एक बड़े नेता की मानें तो प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी संगठन की मजबूती और सभी अहम जिम्मेदारियां समर्पित और ऊर्जावान युवाओं को देने के पक्ष में हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अब नगरीय निकाय चुनावों से पहले प्रदेश स्तर पर मुहिम चलाकर क्षमतावान व सक्रिय युवाओं की तलाश की जाएगी। बताया जा रहा है कि नए पदाधिकारियों के लिए पांच साल का रोडमैप भी तय किया जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को हटाकर दीपक बैज को जिम्मेदारी दी गई है। बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष बैज विधानसभा चुनाव से पहले ही संगठन में बदलाव के मूड में थे, लेकिन लोकसभा चुनावों में संभावित असंतोष को देखते हुए इसे रोककर रखा गया था, लेकिन अब चुनाव निबट चुका है और चुनाव में पराजय के चलते बदलाव की मांग भी उठने लगी है।

भले ही देश में भाजपा की सीटें कम हो रही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में पार्टी एक सीट बढ़ाने में कामयाब रही। 11 में से 10 सीटों पर भाजपा को जीत मिली है। दरअसल यह जीत भाजपा से ज्यादा मोदी के चेहरे की है। कोरबा एकमात्र ऐसी सीट है, जिसे कांग्रेस ने बरकरार रखा है। वर्तमान सांसद ज्योत्सना महंत ने भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडेय को हराकर यहां से जीत हासिल की। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में कई जगह एकदम नए प्रत्याशी उतारे। बस्तर में महेश कश्यप पार्टी के ही लोगों के लिए नया नाम था। महासमुंद में साहू फैक्टर से किनारा करते हुए इस बार रूपकुमारी चौधरी को टिकट दिया। कांग्रेस से भाजपा में आए चिंतामणि महाराज को सरगुजा से उतारा। राधेश्याम राठिया को राजपरिवार की मेनका सिंह के खिलाफ उतारा। जाजंगीर में शिव डहरिया के खिलाफ कमलेश जांगड़े को उतारा गया। ये ऐसे चेहरे हैं, जिन्होंने या तो कांग्रेस से भाजपा में आकर चुनाव लड़ा, जिसका मलाल भाजपा के लोगों को भी था, या तो एकदम नए थे। सभी को विश्वास था, तो सिर्फ इतना कि मोदी के चेहरे पर जीत जाएंगे। छत्तीसगढ़ में हुआ भी यही।

छत्तीसगढ़ में मोदी फैक्टर चलने की बड़ी वजह यह है कि हाल ही में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। कांग्रेस सरकार का चेहरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे। भूपेश सरकार में बड़े घोटालों और भ्रष्टाचार का आरोप लगा। इसमें महादेव ऐप घोटाला, ट्रांसफर उद्योग, कोल लेवी स्कैम, शराब घोटाला, पीएससी घोटाला और इस तरह के कई मामलों के आरोप लगते रहे। मोदी ने चुनावों में इसे जमकर इस्तेमाल किया। विधानसभा में जिन कारणों से भाजपा ने चुनाव जीता, वही कारण लोकसभा के चुनाव में भी नेता दोहराते रहे। यह कांग्रेस के निगेटिव पॉइंट थे, जिनका फायदा भाजपा ने उठाया। दूसरी तरफ सरकार आने के बाद महतारी वंदन योजना की चर्चा घर-घर में हो गई। भाजपा ने करीब 70 लाख महिलाओं को हर महीने 1000-1000 रुपए खातों में पहुंचाए। इसका बड़ा असर रहा। मोदी ने अपनी हर सभा में इसे दोहराया। चुनाव से पहले ये चर्चा काफी तेज थी कि कांग्रेस के नेता चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। इस फेहरिस्त में भूपेश बघेल का भी नाम था। हालांकि इन चर्चाओं को उस समय विराम लग गया, जब नामों की घोषणा हुई। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री समेत दिग्गज पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों को चुनावी समर में उतारा। कारण शायद ये भी हो सकता है कि चर्चित नामों को उतारने से पब्लिक के बीच ज्यादा मेहनत की जरूरत न हो।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

गठबंधनों में बढ़ती दरार

लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। दावा किया जा रहा है कि राज्य में एक बार फिर से सियासी उठापठक हो सकती है। इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव की सभी दलों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन सताधारी महायुति और विपक्षी महाविकास आघाडी (इंडी) गठबंधनों में दरार बढ़ती जा रही है। दोनों गठबंधनों में टूट की अटकलें तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र में इस समय एक तरफ भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी का गठबंधन (महायुति) है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी), शरद पवार की एनसीपी (एसपी) और कांग्रेस का गठबंधन है। लोकसभा चुनाव में महायुति ने 48 में से 17 और महाविकास आघाड़ी ने 30 सीटों पर जीत हासिल की है। महायुति में अजित पवार को लेकर अनबन की खबरें तेज हैं तो महायुति में कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) की नहीं बन रही है।

महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में महायुति को मिली कम सीटों को लेकर बयानबाजी जारी है। भाजपा, शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी कारणों की तलाश में जुटी है। साथ ही तीनों ही दल विपक्ष पर संविधान को लेकर झूठा प्रचार करने का आरोप लगा रही है। इस बीच आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गनाइजर में कहा गया है कि महाराष्ट्र में भाजपा की लोकसभा चुनाव में हार का एक कारण उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के साथ गठबंधन था। ऐसे में अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि भाजपा अजित पवार के साथ संबंध तोड़ देगी। भाजपा और शिवसेना मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ सकती है।

दरअसल, लोकसभा चुनाव में जीत के बाद उद्धव ठाकरे और कांग्रेस में खटपट शुरू हो गई थी। इसकी वजह मुंबई और सांगली की सीट मानी जा रही है। साथ ही दोनों दलों में विधान परिषद की सीट को लेकर भी विवाद है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो सभी 288 सीटों पर तैयारी शुरू कर दें। लोकसभा की दस सीट पर चुनाव लड़कर आठ पर जीत हासिल करने वाले शरद पवार ने अब खुलकर राज्य की राजनीतिक पिच पर खेलना शुरू कर दिया है। वह राज्य की बागडोर संभालने को तैयार है। अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए पवार कहते हैं कि अगले तीन या चार महीने में राज्य विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मेरा प्रयास राज्य की कमान संभालने का होगा और इसे हासिल करने के लिए हमें विधानसभा चुनाव जीतना होगा। शरद पवार ने इस दौरान याद दिलाया कि वह चार बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, एक दशक तक केंद्रीय कृषि मंत्री और दो साल तक रक्षा मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह सब तभी संभव हो सकता है जब आपके पास सामूहिक शक्ति हो।

राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने भी आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 सीट में से 225-250 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कह रही है। मनसे ने लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को समर्थन देने की घोषणा की थी। राज ठाकरे ने एनडीए के लिए प्रचार भी किया। हालांकि, उनकी पार्टी कहीं भी मैदान में नहीं थी। मनसे का गठन 2006 में हुआ था और उसने अपना पहला विधानसभा चुनाव 2009 में लड़ा था। इस चुनाव में उसने 13 सीट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि, 2014 और 2019 के राज्य चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन फीका रहा और दोनों बार उसे केवल एक-एक सीट पर जीत हासिल हुई।

आरएसएस से जुड़ी पत्रिका में की गई भाजपा-एनसीपी गठबंधन की आलोचना के सवाल को अजित पवार टालते हुए नजर आए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि उनका ध्यान विकास और महाराष्ट्र में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव पर है। गौरतलब है कि आरएसएस के करीबी माने जाने वाले साप्ताहिक ऑर्गनाइजर में लिखे गए एक लेख में लोकसभा चुनाव परिणामों का विश्लेषण किया गया था, जिसमें अति आत्मविश्वास को कमजोर प्रदर्शन का कारण माना गया था और भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए इसे रिएलिटी चेक बताया गया था। इसमें महाराष्ट्र का भी संदर्भ था, जहां भाजपा की सीटों की संख्या 2019 के मुकाबले 23 से घटकर 9 हो गईं। लेख में महाराष्ट्र में हुए एनडीए गठबंधन की भी आलोचना की गई थी, जिसमें एनसीपी और शिवसेना शिंदे गुट शामिल है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार से जब इस विषय पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे टालते हुए कहा कि उनका ध्यान आगामी चुनाव पर है। राकांपा अध्यक्ष ने कहा कि वह इस समस्या पर बोलना नहीं चाहते हैं। उन्होंने पुणे में मीडिया से बातचीत में कहा, चुनाव के बाद बहुत सारे नेता अपने विचार और राय व्यक्त कर रहे हैं। लोकतंत्र में, अपनी राय व्यक्त करना उनका अधिकार है और मैं उन पर प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता। मैंने खुद को विकास पर केंद्रित किया है, हम अतिरिक्त सहायता कैसे प्रदान कर सकते हैं और अधिक विकास कार्यों को पूरा करें। मेरा प्रयास यह होगा कि हम, महायुति के रूप में, नई ऊर्जा के साथ राज्य विधानसभा चुनावों का सामना कैसे कर सकते हैं।

● **बिन्दु माथुर**

शरद पवार खेमे में भी विवाद

महाराष्ट्र की राजनीति में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नए सिरे से राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। एक तरफ भाजपा में खींचतान और झगड़े शुरू हुए हैं तो दूसरी ओर विपक्षी खेमे में एनसीपी के दोनों गुटों में विवाद शुरू हो गया है। अजित पवार खेमे में कई नेता नाराज हैं और पाला बदलकर शरद पवार के खेमे में लौटना चाहते हैं तो शरद पवार के गुट में अलग झगड़ा छिड़ा है। यह विवाद शरद पवार के पोते और पार्टी के विधायक रोहित पवार और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के बीच है। गौरतलब है कि अजित पवार ने जब पार्टी तोड़ी थी तब जयंत पाटिल ने शरद पवार का साथ नहीं छोड़ा था और उनकी बड़ी ताकत बने थे। लेकिन अब उनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। पिछले दिनों 10 जून को जब पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, उसी दिन से विवाद ने जोर पकड़ा है। वैसे पहले से यह विवाद चल रहा था लेकिन उस दिन रोहित पवार ने खुलकर जयंत पाटिल पर निशाना साधा और कहा कि किसी को अपने आप को कमांडर नहीं समझना चाहिए। उसी कार्यक्रम में जयंत पाटिल ने रोहित पवार को जवाब दिया और कहा कि उनको अगले तीन चार महीने शांति से काम करने दिया जाए।

पीएम सूर्य घर योजना सफलता से दूर

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य आवासीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इस योजना का लक्ष्य देशभर में 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। राजस्थान में अधिकारियों की अड़ियल रवैये के चलते लोग पीएम सूर्य घर योजना का लाभ चाहकर भी नहीं उठा पा रहे हैं। राजस्थान में, फरवरी 2024 में उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री दीया कुमारी द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट में पांच लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। हालाकि, राज्य की बिजली कंपनियों (डिस्कॉम) के मौजूदा प्रयासों और प्रदर्शन को देखते हुए यह लक्ष्य सतही और अप्राप्य प्रतीत होता है। 6 मई, 2024 को एक वेबिनार में आरईसी लिमिटेड द्वारा बताए गए आंकड़ों ने योजना की प्रगति में महत्वपूर्ण विसंगतियों को उजागर किया। आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 1,33,717 आवेदन आए, जिसमें 26,012 यानी 19.45 प्रतिशत स्थापित हो चुके थे, जबकि राजस्थान में 72,671 आवेदन आए, लेकिन उसमें से केवल 1,275 यानी 1.75 प्रतिशत सोलर प्लांट ही स्थापित हो पाए।

गुंजाइश होने के बावजूद राजस्थान में गुजरात की तुलना में केवल 50 प्रतिशत आवेदन मिले हैं और स्थापित सोलर प्लांटों की संख्या तो बहुत ही कम है। इस विसंगति को देखते हुए राजस्थान में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के वांछित परिणामों के लिए तत्काल ध्यान देने और हस्तक्षेप की आवश्यकता है। लेकिन कई मुद्दे हैं जो इसके कार्यान्वयन में बाधा डालते हैं। पहला मुद्दा, सहायक अभियंता (एईएन) कार्यालयों का रूखा व्यवहार है। डिमांड साइड मैनेजमेंट सेल के प्रयासों के बावजूद बिजली वितरण कंपनी (डिस्कॉम) के अधिकारियों के व्यवहार में बदलाव नहीं आ रहा है। यहां तक कि कई एईएन कार्यालय रूफटॉप सोलर और इसके प्राथमिकता के बारे में नवीनतम आदेशों से अनभिज्ञ हैं। इससे उपभोक्ता और विक्रेता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक और बड़ा मुद्दा, नेट मीटरिंग की समयसीमा का पालन न करना है। हालांकि विक्रेता मात्र दो से तीन दिन के भीतर छतों पर सोलर प्लांट लगा देते हैं, लेकिन सरकारी प्रक्रिया में देरी के कारण प्लांट कमीशनिंग में एक महीने से अधिक समय लग जाता है। डिस्कॉम द्वारा निर्धारित नेट मीटरिंग की समयसीमा मूल रूप से 80 दिन थी, जिसे 27 फरवरी, 2024 के आदेश द्वारा घटाकर 18 दिन कर दिया गया था। लेकिन आदेश के तीन महीने बीत जाने के बावजूद, किसी भी एईएन कार्यालय ने संशोधित समयसीमा का पालन नहीं किया है। लोड एक्सटेंशन में लगने वाला समय एक और चिंता का विषय है। लगभग 70 प्रतिशत उपभोक्ताओं को अपनी सौर प्लांट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोड बढ़ाने की आवश्यकता होती है। लेकिन मौजूदा प्रक्रिया, जो अक्सर कागजी कार्रवाई में उलझी रहती है, को पूरा होने में महीनों लग सकते हैं, भले ही साइट पर केबल या मीटर में कोई बदलाव आवश्यक न हो। जिन उपभोक्ताओं ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत मार्च 2024 की शुरुआत में लोड एक्सटेंशन के लिए आवेदन किया था, वे डिस्कॉम से मंजूरी मिलने के लिए लंबित हैं। सौर प्रतिष्ठानों के लिए मांग पत्र तैयार होने और जमा करने के बावजूद यह देरी जारी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा गंभीर है, जहां एईएन कार्यालय के अधिकारी अक्सर ट्रांसफार्मर क्षमता पर्याप्त न होने के कारण लोड एक्सटेंशन के अनुरोधों को सीधे खारिज कर देते हैं। लोड एक्सटेंशन में ये प्रक्रियात्मक देरी राजस्थान में पीएम सूर्य घर योजना की सफलता में सबसे बड़ी बाधा साबित हो रही है। आखिरी बाधा पीएम सूर्य घर पोर्टल में गड़बड़ियां हैं। पिछले दो महीनों से, पोर्टल में कई तरह की गड़बड़ियां आ रही हैं, जिसका असर उपभोक्ताओं, विक्रेताओं और डिस्कॉम अधिकारियों पर काफी पड़ रहा है। हालांकि हाल ही में किए गए सुधारों ने उपभोक्ताओं के लिए समस्याओं को आंशिक रूप से हल कर दिया है, जिससे वे आवेदन जमाकर सकते हैं, लेकिन एईएन कार्यालय इन आवेदनों को आगे बढ़ने में अनिच्छुक हैं, क्योंकि पोर्टल पर पहुंच संबंधी समस्याएं हैं। ऐसे कारणों की वजह से ही पीएम सूर्य घर योजना के तहत सौर परियोजनाओं की समय पर स्थापना और कमीशनिंग में बाधा उत्पन्न कर रही है।

भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रयासों ने न सिर्फ थर्मल पावर प्लांट्स से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद की है, बल्कि आर्थिक विकास को गति दी है। इन प्रयासों ने बिजली की पहुंच और आपूर्ति को भी बेहतर बनाया है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, बड़े जल विद्युत संयंत्रों को छोड़कर स्थापित क्षमता के मामले में भारत अब वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है, जिसकी क्षमता 145 गीगावाट है। जैव ऊर्जा, पवन और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वालीं सरकारी योजनाओं ने इस तरक्की में अहम भूमिका निभाई है। इस विकास को बनाए रखने के लिए, भारत को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में आने वालीं रुकावटों का गहन मूल्यांकन करने की जरूरत है। इस दौरान हर क्षेत्र में कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों पर ध्यान देना होगा। साथ ही, पवन, सौर और जैव ऊर्जा के लिए मांग पर आधारित बाजार बनाने और पूरे वैल्यू चेन को कवर करने वाले घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

सूर्य ऊर्जा को विश्वसनीय और किफायती बनाने की जरूरत

पिछले दशक में भारत ने सौर ऊर्जा के विकास में काफी तरक्की की है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में सौर ऊर्जा से स्थापित क्षमता 1.2 गीगावाट से बढ़कर 2023-24 में 82 गीगावाट हो गई है। दूसरे शब्दों में, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के आंकड़ों के अनुसार, एक दशक पहले कुल ऊर्जा मिश्रण में सौर ऊर्जा का योगदान 0.4 प्रतिशत से भी कम था, जो अब बढ़कर 6.5 प्रतिशत हो गया है। मौजूदा विकास दर को बनाए रखने के लिए, सरकार को उन चुनौतियों को दूर करने की जरूरत है जो परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, ग्रिड में एकीकरण करने और बिजली खरीद परिपाटियों में देरी का कारण बनती हैं।

जाटलैंड बनाने की कोशिश पड़ी भारी

केंद्र में दो बार भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाने वाला उप्र 2024 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ है। खुद नरेंद्र मोदी की बनारस सीट पर जीत का अंतर बहुत कम हो गया। तीन बार गुजरात के मुख्यमंत्री और दो बार प्रधानमंत्री बनने तक नरेंद्र मोदी बहुमत की सरकार चलाते आए हैं। पहली बार मोदी के गले में गठबंधन सरकार की हड्डी अटकी है। सवाल उठ रहे हैं कि भाजपा के लिए सबसे ज्यादा उम्मीदों वाले उप्र का नतीजा इतना हतप्रभ करने वाला कैसे हो गया। दरअसल, इस हार के कारण तो कई हैं, जो लंबे अर्से से मौजूद थे, लेकिन जीत के जश्न में नजर नहीं आ रहे थे। हार के बाद अब सारे रोग सतह पर आने शुरू हो चुके हैं, जिसमें भितरघात से लेकर नेताओं का अहंकार और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा भी शामिल है।

उप्र में भाजपा की हार का सबसे बड़ा कारण प्रदेश संगठन का निरंकुश हो जाना रहा है। जब तक पार्टी सत्ता से बाहर रही, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं में समन्यवय बना रहा। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक फोन पर उपलब्ध थे, लेकिन सत्ता के बाद वाले अध्यक्षों की उपलब्धता अपने कार्यकर्ताओं के लिए बेहद सीमित हो गई। पार्टी में पराक्रम की जगह परिक्रमा वाले नेताओं की पूछ बढ़ गई। बाहर से आने वाले कैडर नेताओं पर भारी पड़े। भाजपा कार्यकर्ताओं का वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मिलना तो और मुश्किल हो गया। पूरे प्रदेश को संभालने के लिए अध्यक्ष बनाए गए भूपेंद्र चौधरी केवल पश्चिमी उप्र और जाटों के अध्यक्ष बनकर रह गए, जो चुनाव में भाजपा को भारी पड़ गया।

आखिर मोदी-योगी फैक्टर और अमित शाह की चुनावी रणनीति के बावजूद भूपेंद्र चौधरी वैसा रिजल्ट क्यों नहीं दे पाए, जैसा केंद्रीय नेतृत्व को अपेक्षित था। भाजपा को जाटलैंड में ही सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। वह भी तब, जब जाटों के सबसे बड़े नेता रहे चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करके उनके पोते जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल से गठबंधन किया गया था। पहले चरण से खराब हुआ माहौल आखिरी चरण तक जारी रहा। दरअसल, भाजपा ने भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जाट के साथ पिछड़ों को भी साधने की रणनीति तैयार की थी, लेकिन भूपेंद्र चौधरी शीर्ष नेतृत्व की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने प्रदेशभर के भाजपा कार्यकर्ताओं का अध्यक्ष बनने के बजाय अपनी पूरी ऊर्जा पश्चिमी उप्र के बड़े जाट नेता बनने में खपा दी, जिसमें संजीव बालियान की महत्वाकांक्षा का भी बड़ा रोल रहा। भाजपा ने भी अपनी रणनीति का फोकस हिंदुत्व के बजाय जातीय समीकरण पर कर दिया, जिसने हिंदू वोटरों को जातियों में बांट दिया। केंद्रीय नेतृत्व को जब इस बात का एहसास हुआ कि भूपेंद्र चौधरी को अध्यक्ष बनाने के बावजूद जाट भाजपा के साथ नहीं है, तब तक देर हो चुकी थी। भाजपा ने अपनी गलती दुरुस्त करने के लिए जयंत चौधरी को भी साथ जोड़ा, लेकिन यह गठबंधन भी फलदायी साबित नहीं हुआ। इस चुनाव से जाटलैंड का नैरेटिव भी ध्वस्त हो गया। पश्चिमी उप्र में जाटों के अलावा सैनी, गुर्जर, क्षत्रिय, दलित, ब्राह्मण, त्यागी भी हैं, जो रिजल्ट प्रभावित करते हैं, लेकिन लगातार जाटों को महत्व देने से अन्य जातियां भाजपा से छिटक गईं। बीते विधानसभा चुनाव में कई सांसदों ने विभिन्न कारणों से अपने क्षेत्र के कई विधायकों को जानबूझकर हराने की साजिश रची। प्रदेश संगठन को इसकी जानकारी थी, लेकिन इस मामले में कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई, जिसका नतीजा लोकसभा चुनाव में भी दिखा।

इस बार कई विधायक अपने सांसदों को हराने को तैयार बैठे थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने स्वयं इस मामले को सुलझाने के बजाय सबकुछ केंद्रीय नेतृत्व के जिम्मे छोड़ दिया। समय रहते ऐसे मामलों को सुलझा लिया गया होता या केंद्रीय नेतृत्व को इसकी सही जानकारी दी गई होती तो नतीजा बेहतर हो सकता था। दूसरे, कई सांसदों के खिलाफ जनता में बेहद नाराजगी थी, लेकिन प्रत्याशी चयन करते समय इसका ध्यान नहीं रखा गया। कम से कम दो दर्जन सीटों पर जनता उम्मीद कर रही थी कि भाजपा प्रत्याशी बदल देगी, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। उन्हीं प्रत्याशियों को रिपीट कर दिया गया। राज्य स्तर पर हुए कई सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ था कि कई मौजूदा सांसद हार जाएंगे, लेकिन प्रदेश ईकाई ने इसकी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को नहीं दी।

बीते दो लोकसभा चुनावों में रणनीतिक बिसात बिछाने वाले अमित शाह को भी प्रदेश नेतृत्व ने प्रत्याशियों की छवि को लेकर अंधेरे में रखा। मुजफ्फरनगर सांसद संजीव बालियान, कैराना से प्रदीप चौधरी, एटा से राजवीर सिंह, बुलंदशहर से भोला सिंह, अलीगढ़ से सतीश गौतम, इटावा से डॉ. राम शंकर कठेरिया, कौशांबी से विनोद सोनकर, प्रतापगढ़ से संगमलाल गुप्ता, मोहनलालगंज से कौशल किशोर, मछलीशहर से बीपी सरोज, चंदौली से डॉ. महेंद्रनाथ पांडेय, बस्ती से हरीश द्विवेदी, लालगंज से नीलम सोनकर, फैजाबाद से लल्लू सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी, कन्नौज से सुब्रत पाठक जैसे सांसदों से मतदाता नाराज था, लेकिन शीर्ष नेतृत्व को इस बात की रिपोर्ट नहीं दी गई।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

पहली बार भाजपा का कोर वोटर भी छिटका

90 के दशक के बाद पहली बार भाजपा का कोर वोटर भी उससे दूर छिटका है। कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य, ब्राह्मण जैसी जातियां तो अतीत में सपा और बसपा के साथ साझीदार रही हैं, लेकिन लोध, सैनी, क्षत्रिय, पासी, वाल्मिकी भाजपा का कोर वोटर रहा है। इस बार भाजपा के कोर वोटर का बड़ा हिस्सा भी उससे दूर हो गया। लोधी वोटर कल्याण सिंह के भाजपा से अलग होने के बावजूद बड़ी संख्या में भाजपा से जुड़ा रहा, लेकिन इस बार उसका ठीक ठाक हिस्सा इंडी गठबंधन को गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर एवं संजय निषाद के भाजपा गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद इन जातियों का वोट भाजपा से ज्यादा सपा-कांग्रेस गठबंधन को गया। भाजपा में भी स्वतंत्रदेव सिंह जैसा कुर्मी नेता तथा अनुप्रिया पटेल से गठबंधन के बावजूद कुर्मी वोटर भाजपा को छोड़कर अपनी जाति के प्रत्याशियों की ओर गया। पूर्वांचल की कई सीटों पर प्रभाव होने का दावा करने वाले ओम प्रकाश राजभर की वापसी भी भाजपा के लिए मुफीद साबित नहीं हुई।

आरक्षण की राजनीति

आरक्षण की राजनीति भाजपा के लिए नासूर बनने वाली है। भाजपा की आमतौर पर छवि सवर्णों की पार्टी के रूप में रही है। बड़ी मुश्किल से पार्टी ने अपनी छवि पिछड़ों की पार्टी के रूप में बनाई थी, पर राजनीतिक माहौल कुछ ऐसा बन रहा है कि पार्टी मुश्किल में फंस गई है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को झटका देते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और के लिए कोटा बढ़ाने वाले नवंबर 2023 के कानून को रद्द कर दिया। इस कानून के तहत सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) 50 प्रतिशत से 65 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान करता है। सुप्रीम कोर्ट इसके पहले भी 50 प्रतिशत के ऊपर दिए गए आरक्षण को रद्द करता रहा है। पर इस फैसले ने बिहार की राजनीति को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा कर दिया है। विशेषकर भाजपा के लिए बहुत समस्या खड़ी हो गई है। हालांकि भाजपा भी इस कानून के खिलाफ कोर्ट जाने के नीतीश सरकार के फैसले का समर्थन ही कर रही है। पर उसके लिए यह समर्थन इतना आसान नहीं है। आइए देखते हैं क्यों भाजपा के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली हालात पैदा हो गई है।

इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि बिहार में सवर्णों का वोट भाजपा को मिलता रहा है। पार्टी के कोर वोटर्स ब्राह्मण-ठाकुर-भूमिहार-कायस्थ-बनिया आदि हैं। पर पिछड़ी जाति और दलित वोटों का दबाव इतना है कि पार्टी अपनी छवि पिछड़ा समर्थक ही रखना चाहती है। शायद यही कारण है कि विधानसभा में जेडीयू से अधिक सीट होने के बावजूद भाजपा का प्रदेश में उपमुख्यमंत्री ही होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कम विधायकों के बावजूद पूरी स्वतंत्रता के साथ अपना कार्यकाल एन्जॉय कर रहे हैं। चूंकि भाजपा जानती है कि बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट की गारंटी नीतीश कुमार ही हैं। भाजपा को बिहार लोकसभा चुनावों में जो सफलता मिली है उसके पीछे भी नीतीश कुमार का बहुत बड़ा रोल है। चूंकि आरक्षण बढ़ाने वाला यह कानून नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है इसलिए भाजपा इसको नजरंदाज भी नहीं कर सकती है। हालांकि जातिगत जनगणना को भी भाजपा ने सपोर्ट किया था। पर यह सभी जानते हैं कि भाजपा की प्राथमिकता में ये दोनों ही नहीं हैं। न जातिगत जनगणना और न ही आरक्षण का कोटा बढ़ाना। अगर भाजपा की प्राथमिकता में ये दोनों चीजें होतीं तो वो भी अपने मेनिफेस्टो में इसका प्रावधान करता पर ऐसा नहीं है। भाजपा की मजबूरी ये है कि जाति जनगणना और आरक्षण का कोटा बढ़ाना इन दोनों ही बातों का बिहार में उसे समर्थन करना होगा। हालांकि भाजपा इन दोनों मुद्दों पर समर्थन के बाद भी पार्टी पिछड़े वोटों में कितना सेंध लगा पाएगी यह अनिश्चित ही है। फिर भी पिछड़ा समर्थक छवि बनाए रखने के लिए पार्टी सर्वोच्च न्यायालय में बिहार उच्च न्यायालय के फैसले का विरोध करने जा रही है।

भाजपा पिछले कई सालों से लगातार दलितों और पिछड़ों के लिए वो सब कर रही है जो कभी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या आरजेडी ने नहीं किया होगा। जैसे एससी-एसटी कानून जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से थोड़ा डाइल्यूट हुआ तो भाजपा सरकार ने विधेयक पास कर कानून के पुराने स्वरूप को जिंदा किया। इसी तरह जब प्रमोशन में आरक्षण का विरोध समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने किया, भाजपा मजबूती के साथ प्रमोशन में आरक्षण के साथ खड़ी रही। इसके बावूजद लोकसभा चुनावों में संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ के नाम पर इंडिया गठबंधन के दलों ने भाजपा को मिलने वाले दलित और पिछड़े वोटों में सेंध लगा दी। ऐसा क्यों हुआ? यह विचारणीय तथ्य है। दरअसल भाजपा तो दलितों और पिछड़ों के लिए संरक्षण के लिए हर तरह से खड़ी रहती है। जिसमें आरक्षण का समर्थन भी शामिल है। पर भाजपा के अभिभावक संगठन आरएसएस हो या दक्षिणपंथी यूट्यूबर गैंग सभी आरक्षण के विरोध में आग उगलते रहे हैं।

आरएसएस ने हालांकि अपनी विचारधारा को बदला है पर 2015 में संघ प्रमुख के आरक्षण विरोधी बयान का भूत गाहे बगाए उठता ही रहता है। घोर दक्षिणपंथी हैंडल दिनभर भाजपा के समर्थन में एजेंडा चलाते रहते हैं पर जब आरक्षण की बात होगी तो वो भाजपा को भी कोसने लगते हैं। चर्चित यूट्यूबर अजीत भारती जो राइट विंग इन्फ्लुएंसर हैं, ये भी आरक्षण का जमकर विरोध करते रहे हैं। बिहार में आरक्षण का कोटा बढ़ाने वाले कानून के रद्द होने पर सरकार के सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का विरोध किया है।

● **विनोद बक्सरी**

9वीं अनुसूची में ले जाने की होगी मांग

भाजपा के सामने मुश्किल यह होगी कि केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण भागीदार जेडीयू बिहार में पास हुआ आरक्षण का कोटा बढ़ाने वाले कानून को नौंवी अनुसूची में डालने की मांग करेगी। नौंवी अनुसूची संविधान का वह हिस्सा है जिसमें किसी कानून को रख देने से उस कानून को कोर्ट में चैलेंज करना मुश्किल हो जाता है। बिहार में 12 लोकसभा सीटें जीतकर, जेडी(यू) राष्ट्रीय मंच पर भी एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरी है, क्योंकि मोदी सरकार की निर्भरता जेडीयू और एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी (16 सीटें) पर आश्रित है। नीतीश ने पहली बार बिहार कोटा वृद्धि कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की थी जब वह विपक्षी इंडिया गुट का हिस्सा थे। वह भाजपा के एक प्रमुख भागीदार के रूप में फिर से ऐसा करने की मांग करेंगे। जद(यू) के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि जब केंद्र ईडब्ल्यूएस कोटा लाया तो आरक्षण 50 प्रतिशत का आंकड़ा पार कर गया। तमिलनाडु और कई अन्य राज्यों में भी आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक है। जैसे इन सभी कानूनों को कोई चैलेंज नहीं कर पा रहा है, उसी तरह के जो जरूरी कदम होंगे हम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इसे नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि आगे कोई इसे चुनौती न दे सके। हम समाज के वंचित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे।

तो बढ़ेंगी मोदी की चुनौतियां!

लोकसभा के चुनाव नतीजों में कम से कम तीन प्रदेशों पर निगाह रखना बेहद जरूरी है। जम्मू-कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा संवेदनशील राज्य पंजाब हो गया है। जहां जम्मू-कश्मीर में एक पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी जीत गया है। वहीं पंजाब में दो अलगाववादी चुनाव जीत गए हैं। जम्मू-कश्मीर की बारामूला सीट से अब्दुल रशीद शेख जीता है, जो इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर है। वह आतंकवादियों को फंडिंग के आरोप में 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, जेल में रहते हुए ही वह चुनाव जीत गया है। इंजीनियर रशीद ने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया है। इंजीनियर रशीद की जीत के बाद उसके समर्थन में जोरदार प्रदर्शन हुआ है। पंजाब में भी एक खालिस्तानी अमृतपाल सिंह असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद रहते हुए चुनाव जीत गया है। अमृतपाल सिंह के अलावा इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह का बेटा सरबजीत सिंह खालसा भी फरीदकोट से चुनाव जीत गया है। पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की नीतियों के कारण पंजाब में अलगाववादियों के हौंसले बुलंद हुए हैं।

अमृतपाल सिंह और सरबजीत खालसा की जीत के बाद पंजाब में कई जगहों पर खालिस्तान के झंडों के साथ जोरदार प्रदर्शन हुए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार की नाक के नीचे सैंकड़ों लोगों ने खालिस्तानी झंडों के साथ प्रदर्शन किया। तीन अलगाववादियों के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भारत विरोधी ताकतें एक बार फिर सिर उठाने की कोशिशें कर रही हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रानौत को जिस महिला कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मारा था, उसके समर्थन में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। कंगना रानौत को थप्पड़ मारने की घटना से यह विस्फोटक खुलासा हुआ कि केंद्रीय सुरक्षा बलों में भी पंजाब के अलगाववादियों की घुसपैठ है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी में तैनात जवान ने सरकार के खिलाफ हुए किसानों के प्रदर्शन और धरने में हिस्सा लिया था और केंद्रीय सुरक्षा बलों की गुप्तचर एजेंसी को उसका पता ही नहीं चला। यह देश के लिए बहुत ही गंभीरता की बात है। जम्मू-कश्मीर और पंजाब के बाद तीसरा प्रदेश है तमिलनाडु, वहां भी अलगाववाद सिर उठा रहा है। चुनावों से पहले ही तमिलनाडु से अलगाववाद की आवाज उठी थी। दक्षिणी राज्यों को भारत से अलग करने की आवाज भी उठी, जिसे द्रमुक के बड़े नेता भी उठा रहे थे। अपनी अलगाववादी आवाजों के कारण द्रमुक बहुत मजबूत हो चुकी है। जिसकी झलक लोकसभा चुनाव नतीजों में दिखाई दी है।

चुनाव के बाद भी एक घटना ऐसी हो गई है कि जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तमिलनाडु के एक संगठन फादर पेरियार द्रविड़ कषगम ने कंगना रानौत को थप्पड़ मारने वाली कुलविंदर कौर को सोने की अंगूठी से सम्मानित करने का फैसला किया है। तमिलनाडु की यह संस्था अलगाववाद की आवाज उठाती रही है। यह संस्था दलितों और अल्पसंख्यकों को हिंदुओं और भारत के खिलाफ खड़ा करने का कोई मौका नहीं चूकती। फिल्म इंडस्ट्री में पनप रहे अलगाववादियों पर निगाह रखना भी जरूरी हो गया है। संगीतकार विशाल ददलानी ने कहा है कि कंगना को थप्पड़ मारने वाली कुलविंदर कौर को अगर सरकारी नौकरी से निकाला जाता है, तो वह उसकी नौकरी का इंतजाम करेगा। विशाल ददलानी आम आदमी पार्टी की टोपी पहन चुके हैं। वे शाहीन बाग के धरने में बैठ चुके हैं। किसान आंदोलन में हिस्सा ले चुका है। नरेंद्र मोदी की तुलना नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग से करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कितने लोग पाकिस्तान की साजिश का मोहरा बने हुए हैं, उसका इतिहास भरा पड़ा है। हाल ही के सालों के दो उदाहरण गौर करने लायक हैं। पहला उदाहरण मुंबई पर हुए आतंकी हमले का है। पाकिस्तान समर्थक बुद्धिजीवियों ने 26/11 के आतंकी हमले को आरएसएस की साजिश बताने की कोशिश की थी। अजीज बर्नी ने एक किताब लिखी थी- आरएसएस की साजिश 26/11। इस किताब के विमोचन में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के साथ फिल्म निर्देशक महेश भट्ट भी शामिल थे। जबकि बाद में जांच में पता चला कि महेश भट्ट का बेटा ही डेविड हेडली को उन सभी जगहों पर लेकर गया था, जहां की रेकी करके हेडली ने पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को कहां-कहां हमला करना है, इसकी पूरी जानकारी दी थी।

किसान आंदोलन के दौरान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए दीप संधू ने लाल किले पर खालिस्तान का झंडा लगा दिया था। दीप संधू ने पंजाब में अलगाववाद को हवा देने के लिए वारिस पंजाब दे नाम से एक संगठन खड़ा किया था। दीप संधू की एक एक्सीडेंट में मौत के बाद खालिस्तानी अमृतपाल सिंह उसी वारिस पंजाब दे संस्था का मुखिया है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने से जितनी निराशा इंडी एलायंस को है, उससे ज्यादा निराशा पाकिस्तान और चीन को है। चुनाव नतीजों के बाद 72 घंटों में जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की तीन वारदातें हो गईं।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

राष्ट्र की सुरक्षा की भी चुनौतियां

आतंकवाद की नई घटनाओं के बाद फारूख अब्दुल्ला ने राग पाकिस्तान शुरू कर दिया है। उनके बेटे उमर अब्दुल्ला को पाकिस्तान की तरफ से टेरर फंडिंग करने वाले इंजीनियर रशीद ने हरा दिया है। इशारा साफ है कि पाकिस्तान अब्दुल्ला परिवार से खुश नहीं है। पाकिस्तान को खुश करने के लिए फारूख अब्दुल्ला फिर से पाकिस्तान से बातचीत की दुहाई देने लगे हैं। इसका मतलब है कि वह यह मानते हैं कि यह सब पाकिस्तान करवा रहा है। यह लोकल आतंकवाद नहीं है। यह पहली बार हुआ है कि अब्दुल्ला परिवार का कोई सदस्य लोकसभा में नहीं पहुंचा। जब-जब परिवार हारता है, अब्दुल्ला परिवार की भाषा बदल जाती है। फारूख अब्दुल्ला ने कहा है कि मिलिट्री ऑपरेशन से आतंकवाद की समस्या का हल नहीं निकलेगा। ये सब लोग जो भारत सरकार की नीति के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, ये सब पाकिस्तान के स्लीपर सेल हैं। इसलिए मोदी के सामने इस बार की चुनौतियां सिर्फ राजनीतिक नहीं है, राष्ट्र की सुरक्षा की भी चुनौतियां हैं। और मिलीजुली चुनौतियां हैं, क्योंकि जैसे ही केंद्र सरकार पंजाब के अलगाववादियों पर कार्रवाई करेगी, फारूख अब्दुल्ला की तरह कांग्रेस के नेता भी यह बयान देने लगेंगे कि यह कानून व्यवस्था का मामला नहीं है। नक्सलवादियों के खिलाफ कार्रवाई पर भी कांग्रेस के नेताओं का हमेशा यही स्टैंड रहा है। इसलिए इस बार मोदी के सामने ज्यादा गंभीर चुनौतियां हैं।

चीनी चुनौतियों का मुकाबला कर सकता है भारत

दुनिया की सात सबसे बड़ी और विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के समूह जी-7 के शिखर सम्मेलन में चीन के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंधों के संकल्प प्रस्ताव को जो मंजूरी दी गई है, उसके वैश्विक मायने स्पष्ट हैं। इन संकल्पों के वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। हालांकि रूस, चीन और अरब देशों के ईरान-तुर्किये समर्थित एक धड़े की तिकड़ी के सामने वो कितने टिकेंगे, यह तेजी से बदलता हुआ वक्त बताएगा। खासकर भारत और उसके पीछे लामबंद तीसरी दुनिया के देश यदि तटस्थ हो गए, तब क्या होगा, यह समझना भी जरूरी है। वैसे तो जी-7 शिखर सम्मेलन में इस प्रस्ताव पर भी सहमति जताई गई कि उन चीनी कंपनियों के खिलाफ भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जिन्होंने यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद की है। खासतौर पर चीन के उन वित्तीय संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिन्होंने रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए हथियार हासिल करने में मदद की है। संभवतया भारत भी उनमें से एक हो सकता है, क्योंकि उसका रूसी प्रेम जगजाहिर है।

वहीं, शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन जी-7 में शामिल मेजबान इटली के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और कनाडा ने चीन के खिलाफ जिन दो संकल्पों को मंजूरी दी, वो भी निकट भविष्य में अपना असर जरूर दिखाएंगे। क्योंकि इनमें उन संस्थाओं के खिलाफ भी प्रतिबंध लगाने का वादा किया गया है, जिन्होंने धोखाधड़ी से तेल की ढुलाई करके रूस को प्रतिबंधों से बचने में मदद की है। स्वाभाविक है कि भारत भी उनमें से एक हो सकता है, क्योंकि उसने रूस से बड़े पैमाने पर सस्ते कच्चे तेल की खरीदारी की और उसे यूरोपीय बाजारों तक पहुंचाकर भारी मुनाफा कमाया। वहीं, जी-7 के नेताओं ने एक साझा वक्तव्य में कहा कि वे यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद करने वाली तीसरे देशों की संस्थाओं और व्यक्तियों को अपनी वित्तीय प्रणालियों तक पहुंच से प्रतिबंधित करेंगे। इसमें भी शक की सुई भारत और उसके समर्थक तीसरी दुनिया के देशों की ओर घूम सकती है। लेकिन भारत पर निशाना साधने से पश्चिमी देशों का खेल गड़बड़ा सकता है, इसलिए उन्होंने रणनीतिक रूप से चीन पर निशाना साधा है, जो रूस का सबसे बड़ा और भरोसेमंद वैश्विक रणनीतिक पार्टनर बन चुका है। यही वजह है कि जी-7 देशों ने चीन के अनुचित व्यापारिक व्यवहार के खिलाफ भी कार्रवाई का संकल्प लिया है। खासतौर पर चीन के साथ व्यापार घाटे को कम करने पर जोर देने की बात कही है। इसके अलावा, चीन को निर्यात नियंत्रण के जरिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करने से परहेज करने की भी चेतावनी दी गई है, खासतौर पर चिप व इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण में काम आने वाले अहम खनिजों पर एकतरफा निर्यात प्रतिबंधों को अनुचित करार दिया। वहीं, जी-7 ने चीन की कुटिल चालों से अपने व्यवसायों की रक्षा करने और चीन के साथ व्यापार में संतुलन लाने के लिए कार्रवाई करने की बात की है। इसके अलावा, अपने मसौदा बयान में कहा है कि हम दक्षिण चीन सागर में चीन के सैन्य बल और समुद्री मिलिशिया के खतरनाक इस्तेमाल और देशों की गहरे समुद्रों में नौवहन की स्वतंत्रता में बार-बार बाधा डालने, बलपूर्वक एवं धमकाने वाली गतिविधियों का विरोध करना जारी रखेंगे। इसके अलावा, जी-7 देश तब तक यूक्रेन के पीछे खड़े रहेंगे, जब तक जरूरत होगी। यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए समूह पूरी मदद देता रहेगा।

अब गौर करने वाली बात यह है कि जी-7 देश जहां रूस समर्थक चीन को ललकार रहे हैं, वहीं रूस के भरोसेमंद मित्र भारत को पुचकार रहे हैं। तभी तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली सात देशों के संगठन जी-7 का सदस्य न होने के बावजूद इसकी शिखर बैठकों में पिछले कई सालों से भारत को महत्व दिया जा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की बढ़ती धमक को ही दर्शाता है।

गोया, इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा के तौर पर जी-7 देशों के सम्मेलन में शिरकत करने के लिए इटली पहुंचे हैं, जिसके अपने खास मायने हैं, जो स्पष्ट हैं। खासकर ऐसे वक्त में जब यूक्रेन युद्ध अपने तीसरे वर्ष में पहुंच गया है, इजरायल-हमास युद्ध भी खत्म होता नहीं दिख रहा है और यूरोपीय देशों के चुनावों में राजनीति का चेहरा बदलता दिख रहा है, दुनिया की सर्वाधिक उन्नत अर्थव्यवस्थाएं मिलकर आगे की रणनीतियों पर विचार कर रही हैं, तब अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया-प्रशांत के बारह विकासशील देशों को भी इस चर्चा में शामिल करने का अर्थ स्पष्ट है कि उनका कोई भी सार्थक मकसद इनके सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए कि भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देश जी-7 के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये तीनों ही देश जी-7 के प्रबल प्रतिद्वंद्वी रूस और चीन के साथ ब्रिक्स समूह का भी हिस्सा हैं। वहीं, संयुक्त राष्ट्र जिस तेजी से अपनी प्रासंगिकता खो रहा है, और चतुरसुजान देशों द्वारा उसे खोने दिया जा रहा है, उसे देखते हुए वैश्विक व्यवस्था में जी-7 जैसे क्षेत्रीय संगठनों का महत्व बढ़ा है।

● **कुमार विनोद**

जी-7 अब उतना मजबूत नहीं दिखता

यह भी एक तल्ख सच्चाई है कि जी-7 भी अब उतना मजबूत नहीं दिखता है, जितना पहले दिखता था। क्योंकि 1980 के दशक में जी-7 देशों का जीडीपी वैश्विक जीडीपी का करीब 60 फीसदी था, जो अब घटकर 40 फीसदी रह गया है। वहीं, पिछले एक दशक में भारत को देखने का दुनिया का नजरिया बदला है, तो जिसकी साफ वजहें भी हैं। ऐसे समय में जब ज्यादा देशों की अर्थव्यवस्थाएं स्थिर बनी हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक मान रही हैं। इसके अतिरिक्त, भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) ब्रिटेन के बराबर है, तो फ्रांस, इटली और कनाडा जैसे देशों से कहीं ज्यादा है। लेकिन भारत को मिलने वाले महत्व की एक बड़ी वजह यह भी है कि भारत जहां दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो जी-7 भी लोकतांत्रिक देशों का समूह है। लिहाजा, यह भारत की कूटनीतिक कामयाबी ही है कि आज अमेरिका, रूस और यूक्रेन, तीनों भारत से नजदीकी संबंध चाहते हैं। वैश्विक आयोजनों में भारत की बढ़ती भागीदारी, वैश्विक चुनौतियों को हल करने में भारत के महती प्रयासों की बढ़ती मान्यता को ही दर्शाती है। इसलिए भारत को अपनी गुटनिरपेक्ष नीतियों पर चलते हुए वैश्विक संघर्ष को संतुलित करने की दिशा में अपना अहम योगदान देना चाहिए। चीनी कुटिल चालों का यही सुलझा हुआ जवाब भी होगा।

धरती के इस छोर से उस छोर तक
मुट्ठी भर सवाल लिए मैं
छोड़ती-हांफती-भागती
तलाश रही हूं सदियों से निरंतर
अपनी जमीन, अपना घर
अपने होने का अर्थ!

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति

भारतीय समाज की नारी की स्थिति को बखूबी बयां करती निर्मला पुतुल की ये पंक्तियां पूरे समाज की व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करती हैं। भले ही आज हम यह कहकर अपनी पीठ थपथपा लें कि आजादी के 75 सालों में हमारी महिलाएं चांद पर पहुंच गई हैं, फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, ओलंपिक में पदक जीत रही हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियां चला रही हैं या राष्ट्रपति बनकर देश की बागडोर संभाल रही हैं, लेकिन व्यावहारिक तौर पर देखें तो यह संख्या महिलाओं की आबादी का अंशमात्र ही है। हमारे समाज की महिलाओं का एक बड़ा तबका आज भी सामाजिक बंधनों की बेड़ियों को पूरी तरह से तोड़ नहीं पाया है; उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है या यूं कहें कि हमारा पितृसत्तात्मक समाज उन्हें जन्म से ही ऐसे सांचे में ढालने लगता है कि वे अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए पुरुषों का सहारा ढूंढती हैं। वहीं यह भी सत्य है कि जब-जब कोई स्त्री अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है तब-तब न जाने कितने रीति-रिवाजों, परंपराओं, पौराणिक आख्यानों की दुहाई देकर उसे गुमनाम जीवन जीने पर विवश कर दिया जाता है। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर भारत में शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व आर्थिक स्तर पर महिलाओं ने अब तक कितनी दूरी तय की है।

भारत में आज भी बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं, जो शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। वहीं, पढ़ाई-लिखाई के दौरान बीच में ही स्कूल छोड़ देने वाली लड़कियों की संख्या भी लड़कों की संख्या से बहुत ज्यादा है क्योंकि लड़कियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे घर के कामकाज में मदद करें। वहीं, उच्च शिक्षा की बात करें तो बहुत सी लड़कियां सिर्फ इसलिए उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं क्योंकि उनके परिवार वाले पढ़ाई के लिए उन्हें घर से दूर नहीं भेजते हैं, जिसके चलते उनका अधिकतर समय घरेलू कामों में खर्च होता है और महिलाओं व पुरुषों के बीच समानता का अंतराल बढ़ता चला जाता है। इससे इस मिथक को बढ़ावा मिलता है कि, शिक्षा-दीक्षा लड़कियों के किसी काम की नहीं है क्योंकि अंत में उन्हें प्राथमिक रूप से घर ही संभालना है, शादी करनी है और पति व बच्चों की सेवा करनी है। इतना ही नहीं, लड़कियों को शादी कब करनी है, किससे करनी है, बच्चे कब पैदा करने हैं? ये सबकुछ भी हमारी पितृसत्ता तय करती है।

आंकड़ों पर नजर डालें तो, साल 1951 में भारत की साक्षरता दर केवल 18.3 फीसदी थी जिसमें से महिलाओं की साक्षरता दर 9 फीसदी से भी कम थी। वहीं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के डाटा के अनुसार साल 2021 में देश की औसत साक्षरता दर 77.70 प्रतिशत थी जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 84.70 प्रतिशत, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 70.30 प्रतिशत थी। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि आजादी के बाद से अब तक महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। निम्नलिखित पंक्तियां देश की बेटियों को एक बार फिर से उठ खड़े होने का जज्बा प्रदान करती हैं-

आओ उड़ाने भरें
पंख भी हैं, खुला आकाश भी है
फिर ये न उड़ पाने की मजबूरी कैसी
लगता है, आत्मा पर जंग लगे संस्कारों की
कील ठोंक दी गई है
कि पंख बस
यूं ही फड़फड़ाएं और रह जाएं

भारत के रसोइघरों से महिलाओं की सामाजिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। आज भी घर की बेटी, बहू, मां व पत्नी चाहे कितनी भी पढ़ी-लिखी क्यों न हो; कितने ही बड़े पद पर काम क्यों न कर रही हो; घर के सभी सदस्यों के लिए खाना पकाने व परोसने की उम्मीद सिर्फ महिला सदस्य से ही की जाती है। इसी वजह से भारतीय समाज में लड़कियों को बचपन से ही रसोईघर के काम सिखाने शुरू कर दिए जाते हैं, जबकि लड़कों को रसोई से दूर रखा जाता है। जिससे आगे चलकर वे लड़के, जिनसे कभी रसोई के काम नहीं करवाए गए; जिन्होंने कभी अपने पिता को मां के साथ खाना बनाते या अन्य घरेलू कामों में मदद करते नहीं देखा, वे भी अपने बच्चों को वैसा ही बनाते हैं जैसा उन्होंने अपने परिवार में देखा होता है।

● **ज्योत्सना**

धर्मों में भी महिलाओं का स्थान निम्न

भारत जैसे पितृसत्तात्मक देश में शिक्षा, मीडिया, कानूनी संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं सभी पूरी तरह से पितृसत्तात्मक हैं। यहां तक कि, सभी धर्म भी पितृसत्तात्मक हैं। अधिकांश धर्म महिला को अपना मुख्य आराध्य नहीं मानते। चूंकि धर्मों में पितृसत्ता को सर्वोच्च दिखाया गया है इसलिए महिलाओं को हमेशा से धर्म के नाम पर दबाने का प्रयास किया जाता है, और महिलाएं बिना बराबरी का अधिकार मांगे अपने पति को परमेश्वर, स्वामी मानने लगती हैं। वह इस बात पर जरा भी विचार नहीं करतीं कि पति-पत्नी में अगर एक मालिक है तो दूसरा कौन होगा? वह आसानी से अपने आपको गुलाम मान लेती हैं क्योंकि उनका प्राइमरी स्कूल जो कि उनका परिवार होता है, उसमें उन्हें बचपन से ही ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है। आज भी महिलाओं की अधिकांश समस्याओं का कारण आर्थिक रूप से परनिर्भरता है। यह बेहद चिंताजनक है कि देश की कुल आबादी में 48 फीसदी महिलाएं हैं जिसमें से मात्र एक तिहाई महिलाएं रोजगार में संलग्न हैं। इसी वजह से भारत की जीडीपी में महिलाओं का योगदान केवल 18 फीसदी है। यदि परिवार के भीतर और बाहर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभावों को समाप्त कर पुरुषों के समान अर्थव्यवस्था में भागीदारी करने के अवसर प्रदान किए जाएं तो अन्य महिलाएं भी गीता गोपीनाथ, इंद्रा नुई, किरण मजूमदार शॉ की तरह सशक्त होंगी, साथ ही देश भी आर्थिक मोर्चे पर तेजी से प्रगति करेगा।

साधु चरित सुभ चरित कपासू...

रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी ने वाणी विनायक, देवताओं और पंचदेवों की वंदना की। उसके पश्चात श्री गुरु वंदना की। आज हम लोग तुलसी बाबा के द्वारा विप्र वंदना के विषय को जानेंगे। विप्र पद यानी ब्राह्मण पद की वंदना करते हैं।

बंदउं प्रथम महीसुर चरना।
मोह जनित संसय सब हरना।।
सुजन समाज सकल गुन खानी।
करउं प्रनाम सप्रेम सुबानी।।

पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों का समाधान करने वाले हैं। फिर सब गुणों के भंडार संत-समाज को प्रेम पूर्वक सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं।

साधु चरित सुभ चरित कपासू।
निरस बिसद गुनमय फल जासू।।
जो सहि दुख परछिद्र दुरावा।
बंदनीय जेहिं जग जस पावा।।

संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय होता है। जैसे कपास की डोडी नीरस होती है उसी प्रकार संत-चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है; कपास उज्ज्वल व सफेद होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के तन को ढ़कता है उसी प्रकार संत स्वयं दुःख सहकर दूसरों के दोषों को ढ़कता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है।

मुद मंगलमय संत समाजू।
जो जग जंगम तीरथराजू।।
राम भक्ति जहं सुरसरि धारा।
सरसइ ब्रह्म बिचार प्रचारा।।

संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता-फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहां उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्मविचार का प्रचार सरस्वती जी हैं।

बिधि निषेधमय कलिमल हरनी।
करम कथा रबिनंदनि बरनी।।
हरि हर कथा बिराजति बेनी।
सुनत सकल मुद मंगल देनी।।

विधि अर्थात् वेदों में जिन कर्मों को करने की आज्ञा है यानी ग्रहण करने लायक कर्म और निषेध जो प्रतिबंधित है, जिनकों त्यागना है। ऐसे कर्मों की कथा कलियुग के पापों को हरने वाली सूर्य की पुत्री यमुना जी हैं। भगवान विष्णु और

शंकर जी की कथा रूपी भूमि में गंगा, यमुना और सरस्वती रूपी भक्ति त्रिवेणी का संगम है। जो सुनते ही सब आनंद और मंगलों को देने वाली हैं।

बटु बिस्वास अचल निज धरमा।
तीरथराज समाज सुकरमा।।
सबहि सुलभ सब दिन सब देसा।
सेवत सादर समन कलेसा।।

उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज प्रयाग का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयाग राज सब देशों में, सब समय, सभी को, सहज ही प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक ग्रहण करने से दुखों व संकटों को नष्ट करने वाला है।

अकथ अलौकिक तीरथराऊ।
देइ सद्य फल प्रगट प्रभाऊ।।

वह तीर्थराज अलौकिक यानि लोक से परे जिसकी तरह कोई वस्तु इस लोक में नहीं है और अकथनीय यानी जो कहा न जा सके। इसका प्रभाव प्रसिद्ध है कि यह तुरंत फल देता है।

सुनि समुझहिं जन मुदित
मन मज्जहिं अति अनुराग।
लहहिं चारि फल अछत
तनु साधु समाज प्रयाग।।

जो लोग इस संत-समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेमपूर्वक इसमें स्नान करते हैं। इस प्रयाग के स्नान की सुनना, समझना, आनंद तीन सीढ़ियां हैं। जो भक्त इनमें डुबकी लगाता है वह इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाता हैं।

तुलसीदास जी ने भले और बुरे लोगों के गुण और अवगुण को अद्भुत तरीके से बताया है। दोनों ही इस संसार में जन्म लेते हैं किंतु किसी में गुण और किसी में अवगुण व्याप्त हो जाता है। तुलसी बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से इसकी तुलना कमल व जोंक से की है।

बंदउं संत असज्जन चरना।
दुखप्रद उभय बीच कछु बरना।।
बिछुरत एक प्रान हरि लेहीं।
मिलत एक दुख दारुन देहीं।।

अब मैं संत व असंत के चरणों की वंदना करता हूं, भले-बुरे दोनों ही लोग दुख देने वाले होते हैं, इनका समान रूप से वर्णन किया है। तुलसीदास जी कहते हैं- दुख तो दोनों ही देते हैं लेकिन उनमें अंतर यह है कि संत जाते समय दुख देते हैं और असंत यानी बुरे लोग आते समय दुख देते हैं। संत लोगों का वियोग कभी न हो और वह सदा सत्संग भगवान के चरित्र का अमृत पान कराते रहें और दुष्ट या बुरे लोग जब जीवन में आते हैं तो बहुत सारे दोष देते हैं और भगवत चर्चा से दूर करते है इसलिए वे कष्ट देते हैं।

उपजहिं एक संग जग माहीं।
जलज जोंक जिमि गुन बिलगाहीं।।
सुधा सुरा सम साधु असाधू।
जनक एक जग जलधि अगाधू।।

संत और असंत इसी संसार में ही पैदा होते हैं लेकिन कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग-अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है, दोनों को उत्पन्न करने वाला संसार रूपी समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है।

भल अनभल निज निज करतूती।
लहत सुजस अपलोक बिभूती।।
सुधा सुधाकर सुरसरि साधू।
गरल अनल कलिमल सरि ब्याधू।।
गुन अवगुन जानत सब कोई।
जो जेहि भाव नीक तेहि सोई।।

भले और बुरे अपनी-अपनी करनी के अनुसार यश और अपयश पाते हैं। साधु अमृत, चंद्रमा और गंगा जी के समान है। दुष्ट विष, अग्नि और कलियुग के पापों की नदी अर्थात् कर्मनाशा और हिंसा करने वाले लोगों के समान है। इनके गुण-अवगुण सब कोई जानते हैं किंतु जिसे जो भाता है, उसे वही अच्छा लगता है।

● **ओम**

अंजाम

आंगन में प्रवेश करते ही मनोहर चिल्लाते हुए बोले-अपने लाड़ले को समझाओ! नहीं तो एक दिन लेने के देने पड़ जाएंगे। हम साधारण लोग हैं और साधारण ढंग से ही रहना चाहिए।

मनोहर जी गुस्से से भरकर पत्नी शिखा को देखते रहे- सब तुम्हारे लाड़, प्यार का नतीजा है जो इतना लापरवाह सा हो गया है। दिनभर घूमता-फिरता रहता है। उन सभी का क्या, मामला पैसे देकर निबटा लेगें। मैं कहां से लाऊंगा... ?

अरे! अब बच्चा अपने दोस्तों के साथ ही तो घूमेगा-फिरेगा न। क्या कहूं उसे! घर में ही बैठा रह।

तुम्हें मालूम भी है कुछ! आजकल इस उम्र के बच्चे क्या-क्या कर रहे हैं। इतने सयाने हो गए हैं कि कुछ टेर नहीं लगने देते।

क्या हो गया, कुछ साफ-साफ कहेंगे तो न मैं समझूं। जवान बच्चा है उसे हमेशा कुछ-कुछ कहना क्या अच्छा लगता है... ?

जिन लड़कों के साथ रहता है उनके चाल-चलन बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। कल मैंने अपनी आंखों से देखा, कैसे अपनी हाथों में सूई चुभो रहा था।

तुम तो बेकार में ही शक करते हो। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। जवान है, समझदार भी है। समझा दूंगी उसे। तुम हमेशा उसके पीछे मत पड़े रहो।

ठीक है! फिर भुगतना अंजाम। जवान है तभी तो चिंता होती है। मैं नहीं चाहता कि उसकी जवानी सलाखों के पीछे कटे।

- सपना चन्द्रा

बेटी

सुबह-सुबह अय्यर साहब समाचार पत्र को घोंट रहे थे, तभी पीछे से दो कोमल सी गुलाब की पंखुड़ियों जैसे स्पर्श ने आंखे बंद कर दी।

समझकर भी अनजान बनते हुए बोले, कौन हो भई?

पप्पा, मैं तुम्हारी लाडली, रीवा। रोज सुबह से मेरे लिए व्यस्त रहते हो, कभी स्कूल, कभी स्विमिंग, कभी डांसिंग, कभी कराटे क्लास पहुंचाते हो। आज मम्मा से पूछ कर मैंने, इडली, डोसा, चटनी सांभर, हलवा भी बनाया है, डाइनिंग टेबल पर चलो।

और अय्यर साहब देख दंग रह गए, टेबल पर फादर्स-डे का उपहार और ब्रेकफास्ट सजा हुआ है। उन्होंने रीवा को बड़े प्यार से गले लगाया और गाने लगे- जिनको हैं बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में हम तो रहते हैं!!

- भगवती सक्सेना गौड़

हम

मत कहो अंधेरा है जग में,
कहने से कब उजियार हुआ।
इक दीप जला जब-जब भू पर,
जगमग-जगमग संसार हुआ।।

अंधियारा हारा है बेशक,
लघु कीटों से, लघु दीपों से।
बस तनिक परिश्रम कर,
देखो, मिलते हैं मोती सीपों से।।

आंधी से भी लड़ना सीखो,
टकरा जाओ तूफानों से।
अज्ञान-अंधेरा जहां दिखे,
मेटो दृढ़ शुचि अभियानों से।।

हमने शावक के गिने दांत,
सूरज को लीला बचपन में।
इतराया जब सागर हमसे,
पीया-बांधा था पलभर में।।

दुनिया के शून्य प्रदाता हम,
इंद्रासन के रखवाले हैं।
शरणागत के रक्षार्थ स्वयं,
रघु, शिवि, दधीचि, मतवाले हैं।।

हम सगर भगीरथ से उद्यत,
गंगा को भू पर ले आते।
हम वनवासी, हम संन्यासी,
हम नीलकंठ भी कहलाते।।

हम ग्रामदेवता, कर्मवीर,
हम अर्जुन-भीम प्रतिज्ञा हैं।
दशरथ मांझी के अटल परशु,
हम पंचसती की संज्ञा हैं।।
हम संस्कार, हम संस्कृति भी,
हम जगत गुरु, धर्मोन्नायक।
हम वसुधा-कुल, सर्वे सुखिनः,
जैसे मंत्रों के परिचायक।।
हम वन में गृही, गृही वन में,
वन-गृह में मेल सर्जना हैं।
हम अतिथि, प्रकृति, सद्कर्म व्रती,
मानवता हेतु बंदना हैं।।
हे दीनबंधु! अवधेश सुनो,
हम सियाराम अनुगामी है।
फिर रामराज्य लाने वाले,
हम दृढ़ प्रतिज्ञ जग नामी हैं।।

- डॉ. अवधेश कुमार अवध

इंडिया चोकर्स नहीं, चैंपियन है

11 साल से कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती, हर कोई बोल रहा था हम चोकर्स हैं। हम चोकर्स नहीं... चैंपियन हैं। 2011 के बाद इंडिया ने 5 फाइनल खेले, पिछले वनडे वर्ल्डकप में तो जीतते-जीतते हार गए। इस बार रोहित की टीम ने ऐसा फाइनल जीता, जिस फाइनल में हर कोई सोच रहा था कि इंडिया जीत नहीं सकती। टी-20 में 30 बॉल पर 30 रन होते क्या हैं, लेकिन इंडियन गेंदबाजों ने, इंडियन फील्डर्स ने, रोहित की कप्तानी ने ये साबित कर दिया कि जीत के लिए रन नहीं, जज्बा चाहिए।

भारत ने 2007 में पहला ही टी-20 वर्ल्डकप अपने नाम किया, टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 रन से हराकर ट्रॉफी जीती। इसके बाद टीम ने 7 और टी-20 वर्ल्डकप खेले। 3 बार टीम नॉकआउट स्टेज यानी सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंची, लेकिन खिताब से चूक गई। 2014 में भारत ने साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में हराया, लेकिन श्रीलंका से फाइनल गंवाना पड़ा। 2016 में अपने ही घरेलू मैदान पर भारत नॉकआउट में पहुंचा, लेकिन वेस्टइंडीज से सेमीफाइनल हार गई। 2022 में टीम आखिरी बार नॉकआउट में पहुंची, लेकिन इस बार इंग्लैंड ने 10 विकेट से हरा दिया। इस बीच 2009, 2010, 2012 और 2021 में टीम ग्रुप स्टेज भी पार नहीं कर सकी। अब इसी फॉर्मेट के वर्ल्डकप में भारत ने तीसरा फाइनल खेला और इस बार ट्रॉफी जीतकर अपने आईसीसी खिताब का सूखा भी खत्म कर दिया।

2011 के बाद आंखें तरस गई थीं कि कोहली या रोहित वर्ल्डकप ट्रॉफी उठाएं। 13 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ। रोहित की टीम ने साउथ अफ्रीका से टी-20 वर्ल्डकप छीन लिया। ऐसा फाइनल जीता, जिसे हर कोई हारा हुआ मान बैठा था। पूरे वर्ल्डकप जमकर बल्लेबाजी कर रहे रोहित फाइनल में नहीं चले, पर कोहली अड़ गए। 76 रन बनाए। अक्षर और शिवम ने भी पूरा जोर लगाया। 177 रन का टारगेट दिया। साउथ अफ्रीका बल्लेबाजी के लिए उतरी। 14 ओवर तक उनके बल्लेबाज तेजी से जीत की तरफ बढ़ रहे थे। इसके बाद जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंड्या गेंदबाजी के लिए लौटे और इंडिया की मैच में वापसी हुई। सूर्यकुमार यादव रन नहीं बना पाए थे, लेकिन एक कैच से मैच पलट दिया। आखिरी ओवर तक इंडिया लड़ती रही और जीत छीन ली। 177 रन चेज कर रही साउथ अफ्रीका को 169 पर रोक दिया। 7 रन से हरा दिया। 32 साल से चोकर्स कही जा रही साउथ अफ्रीका इस बार भी दाग लेकर ही लौटी।

अब बात साउथ अफ्रीका की। पहला फाइनल मैच हाथ में ही था। क्लासन 27 बॉल पर 52 रन बना चुके थे, सबसे खतरनाक फिनिशर डेविड मिलर भी क्रीज पर थे। साउथ अफ्रीका ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था, लेकिन बुमराह-अर्शदीप के 2-2 और हार्दिक के 3 ओवर बाकी थे। तीनों ने हार को जीत में बदल दिया। 32 साल बाद उम्मीद थी कि साउथ अफ्रीका माथे से चोकर्स का दाग धो डालेगी, लेकिन टीम 177 रन का टारगेट चेज नहीं कर पाई। 7 रन से हार गई। उसका इतिहास बदला नहीं, पहले भी चोकर्स थी, आज भी वही साबित हुई। साउथ अफ्रीका ने आईसीसी का बैन हटने के बाद 1992 में पहली बार वनडे वर्ल्डकप खेला। टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल में जगह बनाई, लेकिन इंग्लैंड से हार गए। 1996 से 2015 तक टीम 6 में 5 बार नॉकआउट राउंड में पहुंची, लेकिन कभी क्वार्टर फाइनल तो कभी सेमीफाइनल हारकर बाहर हो गई। 2003 और 2019 में टीम नॉकआउट राउंड में नहीं पहुंच सकी। 2023 में साउथ अफ्रीका ने फिर कमबैक किया और सेमीफाइनल खेला, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हार गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम ने यह वनडे वर्ल्डकप तीसरा सेमीफाइनल गंवाया था। इसके अलावा टीम 2 बार न्यूजीलैंड और एक-एक बार वेस्टइंडीज और इंग्लैंड से नॉकआउट हारी है। टीम ने एकमात्र नॉकआउट मैच 2015 में जीता, तब साउथ अफ्रीका ने क्वार्टर फाइनल में श्रीलंका को हराया था।

1998 में आईसीसी ने पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी के रूप में अपना दूसरा 50-ओवर टूर्नामेंट शुरू किया। इसका नाम कभी विल्स इंटरनेशनल तो कभी नॉकआउट ट्रॉफी हुआ, लेकिन अब इसे चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से पहचाना जाता है। साउथ अफ्रीका ने इसमें शानदार प्रदर्शन किया और लगातार 3 नॉकआउट मैच जीतकर ट्रॉफी भी उठाई। जैक्स कैलिस प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। यह साउथ अफ्रीका की सीनियर क्रिकेट टीम का पहला और आखिरी आईसीसी खिताब रहा। इसके बाद टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी में 7 बार हिस्सा लिया, लेकिन खिताब तो दूर फाइनल में पहुंचना भी नसीब नहीं हुआ। टीम ने 2000 और 2002 में भारत से लगातार 2 सेमीफाइनल गंवाए। 2006 में वेस्टइंडीज और 2013 में इंग्लैंड ने उन्हें सेमीफाइनल हराकर बाहर किया। साउथ अफ्रीका 2004, 2009 और 2017 में तो ग्रुप स्टेज भी पार नहीं कर सकी। पहले खिताब के बाद टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी में 5 नॉकआउट मैच खेले, 4 सेमीफाइनल गंवाए। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र क्वार्टर फाइनल भी साल 2000 में जीता। यानी टीम वर्ल्डकप में 32 साल तो वहीं चैंपियंस ट्रॉफी में 26 साल से चोक कर रही है।

क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट का वर्ल्डकप जब 2007 में शुरू हुआ तो आईसीसी ने साउथ अफ्रीका को ही इसकी मेजबानी दे दी। टीम ने पहले ही मैच में वेस्टइंडीज को हरा दिया। सुपर-8 में भी टीम ने लगातार 2 मैच जीत लिए, लेकिन आखिरी मैच भारत से हारकर ग्रुप स्टेज से बाहर होना पड़ा। 2009 में साउथ अफ्रीका फिर सेमीफाइनल तक पहुंची, लेकिन इस बार पाकिस्तान से हार गई। 2010 और 2012 में ग्रुप स्टेज से बाहर हुई। 2014 में सेमीफाइनल तक पहुंच गई, लेकिन भारत से ही हारकर बाहर होना पड़ा। 2016 से 2022 तक टीम फिर ग्रुप स्टेज से बाहर हुई और अब 2024 में पहली बार फाइनल में जगह बनाई। टीम ने अफगानिस्तान को सेमीफाइनल हराया और पहली बार टी-20 वर्ल्डकप में कोई नॉकआउट मुकाबला जीता। साउथ अफ्रीका के पास अपना पहला वर्ल्डकप जीतने का मौका था, लेकिन टीम भारत के खिलाफ 7 रन से हार गई। चैंपियंस ट्रॉफी, वनडे वर्ल्डकप और टी-20 वर्ल्डकप के बाद आईसीसी ने टेस्ट फॉर्मेट का टूर्नामेंट भी 2019 में शुरू कर दिया। इसका नाम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रखा, इसमें टॉप-9 टीमों के बीच 2 साल तक 6-6 सीरीज खेली जाती हैं। पॉइंट्स टेबल के आखिर में टॉप-2 स्थानों पर रहने वाली टीमों में फाइनल होता है।

● आशीष नेमा

अंजू महेंद्रू नहीं... इस एक्ट्रेस संग काका की स्ट्रांग बॉन्डिंग देख जलती थीं डिंपल?

बॉलीवुड में यूं तो कई स्टार्स हैं, जिनके प्यार के किस्सों की अलग-अलग कहानियां हैं। राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार रहे। अंजू महेंद्रू संग उनके रिलेशनशिप में रहने और फिर अपनी उम्र से 16 साल छोटी डिंपल कपाड़िया से शादी कर खूब सुर्खियां लूटीं। डिंपल कपाड़िया को राजेश खन्ना ने तब चुना, जब उनका स्टारडम आसामान छू रहा था।

अंजू महेंद्रू संग टूटे रिश्ते के बाद डिंपल उनकी जिंदगी में आईं। लेकिन मुमताज के साथ उनके दोस्ती से डिंपल को काफी जलन होती थी। जलन इस हद तक थी कि एक बार तो एक्ट्रेस ने काका से कह दिया था- उसी से शादी कर लेते। क्या है ये फिल्मी किस्सा, चलिए आपको बताते हैं।

ये एक्ट्रेस और कोई नहीं मुमताज थीं। फिल्म इंडस्ट्री के लोग कई नामों से इन्हें बुलाते थे। राजेश खन्ना उन्हें प्यार से मोटी कहते थे। देवानंद उन्हें प्यार से मुंजी बुलाया करते थे और बहुत सारे लोग उन्हें उनके निक नेम मुमु से पुकारा करते थे। राजेश खन्ना संग उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है और दोनों की

जोड़ी को भी पर्दे पर लोगों ने काफी पसंद किया। प्रेम कहानी, दो रास्ते, आपकी कसम, दुश्मन, रोटी, अपना देश, राजा-रानी और बंधन जैसी कई फिल्मों में दोनों को साथ देखा गया। राजेश खन्ना और मुमताज की दोस्ती बहुत गहरी थी। एक बार वो भीड़ में बिना हिचक के राजेश खन्ना की जान बचाने चली गई थीं।

शाहरुख खान की फिल्म से किया डेब्यू, फिर 1 झटके में छोड़ दिया बॉलीवुड, अमीर बिजनेसमैन से शादी कर बसा लिया घर

बहुत कम ऐसा होता कि किसी को शाहरुख खान की फिल्म से डेब्यू करने का मौका मिले। लेकिन जो किंग खान के साथ कोई फिल्म कर लेता है, तो उसकी किस्मत चमक उठती है। आज हम आपको एक्ट्रेस के बारे में बताते हैं, जिन्होंने शाहरुख खान की फिल्म में करने के बाद बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उनका नाम है गायत्री जोशी।

गायत्री जोशी ने 2004 में रिलीज हुई स्वदेस फिल्म एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। इसमें वह शाहरुख खान के अपोजिट नजर आई थीं। वैसे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, लेकिन क्रिटिक्स से खूब तारीफ मिली थी। कई क्रिटिक्स ने स्वदेस को शाहरुख खान के करियर की बेस्ट फिल्म बताया और उनकी एक्टिंग की तारीफ में कसीदे भी पढ़े। फिल्म में गायत्री की अदाकारी की भी प्रशंसा हुई, लेकिन उनका करियर बहुत छोटा साबित हुआ। फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया था। गायत्री जोशी ने महज 27 साल की उम्र में सिनेमा की दुनिया से रिटायरमेंट ले लिया था। साल 2005 में उन्होंने अमीर बिजनेसमैन विकास ओबेरॉय के शादी रचाई और फिर कभी एक्टिंग की तरफ मुड़कर नहीं देखा।

गोविंदा की जिस फिल्म को आमिर ने बताया था वल्गर, रिलीज होते ही साबित हुई थी ब्लॉकबस्टर, मालामाल हो गए थे मेकर्स

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोविंदा भले ही आज पर्दे से दूर हों, लेकिन आज कई कलाकार वैसा ही स्टारडम हासिल करना चाहते हैं जो उन्होंने अपने समय में हासिल किया था। आज हम आपको गोविंदा की फिल्म आंखे के बारे में बताने जा रहे हैं, जो साल 1993 में बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी और इस फिल्म को आमिर खान ने पहले वल्गर बताया था।

डेविड धवन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में गोविंदा के साथ चंकी पांडे भी नजर आए थे। वहीं, आमिर को यह फिल्म बिलकुल भी पसंद नहीं आई थी और इस फिल्म को लेकर उस समय आमिर ने मीडिया से बातचीत में कहा था, डेविड धवन मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिर सच कहूं तो यह फिल्म मुझे पसंद नहीं आई। शायद डेविड को यह बात मालूम हो। उन्होंने आगे कहा था, यह फिल्म इतनी बड़ी हिट कैसे हो गई, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे यह फिल्म काफी क्रूड लगी। साथ ही, इसके कुछ सीन भी वल्गर हैं। बता दें, गोविंदा की यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होते ही हंगामा मचाने लगी थी, जो बेहद ही कम बजट में बनकर तैयार हुई थी। विकिपीडिया के आंकड़ों के अनुसार, फिल्म आंखें साल 1993 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी।

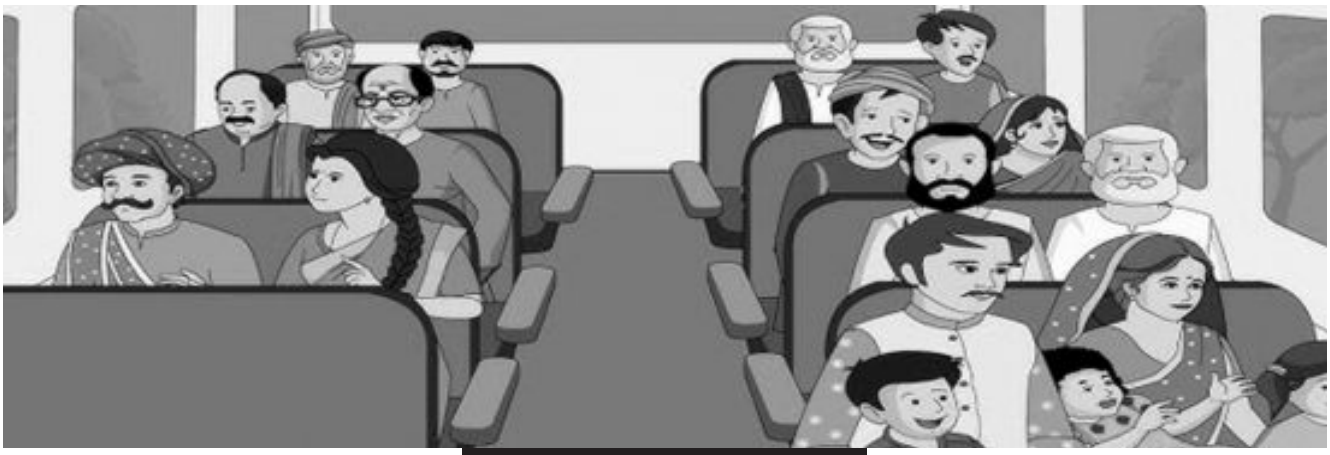

बस की यात्रा

हम पांच मित्रों ने तय किया कि शाम चार बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से दो को सुबह काम पर हाजिर होना था इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शामवाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है।

बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है!

बस-कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा-यह बस चलती भी है? वह बोले-चलती क्यों नहीं है जी! अभी चलेगी। हमने कहा-वही तो हम देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है यह? हां जी, और कैसे चलेगी?

गजब हो गया। ऐसी बस अपने आप चलती है।

हम आगा-पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा-डरो मत, चलो! बस अनुभवी है। नई-नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी।

हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे, वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थीं- आना-जाना तो लगा ही रहता है। आया है, सो जाएगा-राजा, रंक, फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए।

इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। ऐसा, जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे। जो बचे थे, उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है।

बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधीजी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। आठ-दस मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है।

एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस-कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे मां-बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है।

बस की रफ्तार अब पंद्रह-बीस मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे-भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी।

एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह-तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था, कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे-बस तो फर्स्ट क्लास है जी! यह तो इत्तेफाक की बात है।

क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता, जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसको अंत्येष्टि करनी पड़ेगी।

हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी।

धीरे-धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती-निकल जाओ, बेटी! अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही।

एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस्स करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धाभाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बांहें पसारे उसका इंतजार करते। कहते-वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया, पर टायर नहीं बदला।

दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी, कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था, जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही। हंसी-मजाक चालू हो गया।

● **हरिशंकर परसाई**

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

- ज्यादा मज़बूती
- ज्यादा महीन कण
- ज्यादा वर्कबिलिटी
- बेहतरीन निर्माण कार्य
- इको–फ्रेन्डली
- कन्सिसटेंट क्वालिटी
- ज्यादा प्रारम्भिक ताक़त
- ज्यादा बचत

PRISM®
चैम्पियन
प्लस
सीमेंट

दूर की सोच®

Toll free: 1800-572-1444 Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

Address : M-179, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com